(1400/ASA/RBN)

1401 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन में मैं कुर्सी पर नहीं बैठा हूं। उसके पहले माननीय सदस्य आप बोलने लगे। मुझे पहले बोलने दीजिए।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : दादा, स्पीकर सर को बोलने दीजिए। फिर आप बोलिए।…(व्यवधान)

संविधान दिवस के बारे में उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस है और पूरा देश इस संविधान दिवस को बड़ी श्रद्धा के साथ मना रहा है। संविधान के प्रति हमारी गहरी आस्था भी है और विश्वास भी है क्योंकि संविधान का निर्माण भी इसी संसद ने किया था और इसी संसद के केन्द्रीय कक्ष में इस संविधान के निर्माण पर चर्चा हुई और आज खुशी है कि पूरे विश्व में भारत का संविधान और लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, क्योंकि आज संविधान दिवस था, इसलिए सदन की कार्यवाही दो बजे से शुरु की। कल जब आप चर्चा करेंगे तब आपका विषय अंकित होगा तो निश्चित रूप से इस पर व्यवस्था दी जाएगी।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
Ninth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): I beg to present the Ninth Report of Business Advisory Committee.

RE: INTRODUCTION OF BILLS

HON. SPEAKER: Item No. 2.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I have a point of order. I may refer to 19B of Directions by the Speaker: It says:

> "No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced:"

सर, इस पर आपसे बार-बार चर्चा हुई है,…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है कि कौन से दो बिल आपने बताये हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, सर, दादरा और नगर हवेली है और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली(अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) है, दोनों में से एक ही हो रहा है। दोनों में होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज अनऑथोराइज वाला विषय तो पहले इंट्रोड्यूस हो गया।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, जो यह मुद्दा लाये हैं, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन विधेयक, 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 इत्यादि ये बड़े महत्वपूर्ण बिल लाये हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं। हरदीप सिंह पुरी जी पहले इंट्रोड्यूस कर दें।

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (RECOGNITION OF PROPERTY RIGHTS OF RESIDENTS IN UNAUTHORISED COLONIES) Bill

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide special provisions for the National Capital Territory of Delhi for recognising the property rights of residents in unauthorised colonies by securing the rights of ownership or transfer or mortgage in favour of the residents of such colonies who are possessing properties on the basis of Power of Attorney, Agreement To Sale, Will, possession letter or any other documents including documents evidencing payment of consideration and for the matters connected therewith or incidental thereto.

(1405/RAJ/SM)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्ही अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज सम्मिलित हैं, के आधार पर ऐसी कालोनियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करके या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, माननीय मंत्री जी जो बिल सदन में लाए हैं, हम उस बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से यह लाया जा रहा है, सदन को उपेक्षित किया जा रहा है और खास बात यह है कि आपके डायरैक्शन के बाद लाया जाता है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रूलिंग के अंदर यह लिखा हुआ है, अगर आप इसे आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि 'अध्यक्ष अगर अन्यथा'। आप इसे पूरा पढ़ें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह जो आर्ग्युमेंट दे रहे हैं, इसमें कहीं दम नहीं है। यह सिर्फ हम लोगों को डिनाई करने का तरीका है।…(व्यवधान) …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी जी, आप एक मिनट शांत हो जाइए। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम ने यह बिल 23 तारीख, शनिवार को प्रचालित कर दिया था, सभी को भेज दिया था। शनिवार और रविवार दो दिन बिलों के लिए रहता है और इसके लिए दो दिन पर्याप्त समय दे दिए गए हैं। मैंने आपके लिए व्यवस्था दे दी है, बिल इंट्रोड्यूस किया जाए।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप यह चेयर से बोल रहे हैं, इसलिए हम हिम्मत करके बोलने के लिए सदन में खड़े होते हैं। सर, बिल्कुल आपके चेयर का डायरैक्शन है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं व्यवस्था कर रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्ही अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज सम्मिलित हैं, के आधार पर ऐसी कालोनियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करके या अंतरण या बंधक द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I introduce the Bill.

दादर और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

> “कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> “कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. किशन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

औद्योगिक संबंध संहिता के बारे में

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर – 4, श्री संतोष कुमार गंगवार जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह सबसे बड़ा मुद्दा है, आप इसे कैसे बुला सकते हैं?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं इस पर आपको व्यवस्था दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विपक्ष की आपत्ति को मानते हुए, आप इस विधेयक को कल पुर:स्थापित करें।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, दो दिनों का समय दीजिए। यह बड़ा बिल है।…(व्यवधान)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी विराजें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, सुरेश जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको दो दिन की व्यवस्था दी है। ये दो दिन कल हो जाएंगे, इसलिए आप नया विषय क्रिएट नहीं करें। मैंने आपको दो दिनों की व्यवस्था दी है। मैंने कहा है कि मंत्री जी इसको कल इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने आपकी व्यवस्था को मान लिया है।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कहां दो दिन हुए?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कल के लिए कहा है। माननीय सदस्य, आप बुलेटिन में देखिए। आप ऐसा क्यों करते हैं?

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह इतना बड़ा बिल है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतने बड़े विषय हैं, इसलिए मैंने आपकी बात को मानते हुए।

…(व्यवधान)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो आपका आदेश है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप कल बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा नहीं कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा को भी बोलने देंगे या आप ही केवल बोलेंगे।

…(व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा बिल है, बहुत बड़ा विषय है। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए।…(व्यवधान) आज ही उनको एनाउंस करने के लिए बोलिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा बिल है और स्टैंडिंग कमेटी के पास पूरी चर्चा के लिए भेजना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपको पूरे दो दिनों का समय इसे पुर:स्थापित करने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद इस पर डिबेट की जाएगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी डिबेट नहीं कीजिए। मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने किसी को आज्ञा नहीं दी है।

…(व्यवधान)

(1410/VB/AK)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुखद विषय है कि आपका निर्देश वह नहीं सुन रहे हैं। श्री सुदीप जी जो आग्रह कर रहे हैं, …(व्यवधान) वह प्रसंगहीन है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, वह आज ही स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं।…(व्यवधान) महोदय, इस तरह से कैसे सदन चलेगा? …(व्यवधान) यह कल पेश होगा, उसके बाद ये विरोध करेंगे, उसके बाद यह स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा।…(व्यवधान) यह क्या सिलसिला चल रहा है? …(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): It is our right to ask for information from the Government. …(*Interruptions*) Why are you objecting to it? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप आपस में डिबेट मत कीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सदन में आप लोग आपस में डिबेट न करें। मैंने कई बार कहा है, अगर इस सदन को सुचारू रूप से चलाना है, तो आप आपस में चर्चा न करें। न इनको इजाज़त है, न आपको इजाज़त है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, यह ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है। हम इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं। …(व्यवधान) आप क्यों बात करते हो? …(व्यवधान) हम स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यह है…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने एक बार व्यवस्था दे दी है कि यह दो दिन बाद इंट्रोड्यूस होगा, उस समय डिबेट करेंगे कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजना है या नहीं भेजना है। हर बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का सिस्टम न डाला करें। सदन चलने दें। हर बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, तो सदन के अंदर…

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह बहुत बड़ा बिल है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उस समय चर्चा कर लेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उस समय आपकी आपत्ति सुनेंगे।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपत्ति की बात नहीं है सर।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उस समय आपकी आपत्ति सुनेंगे। सदन का जो विचार होगा, उसको माना जाएगा।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I thank you for your observation. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 377 से संबंधित मामलों को मैं उठाने की इजाज़त देता हूँ। सभी माननीय सदस्य 377 से संबंधित विषय सदन में पढ़ सकते हैं।

डॉ. जय सिधेश्वर महास्वामीजी।

नियम 377 के अधीन मामले

Re: Need to approve the proposal of Punyashlok Ahilyadevi Holkar University in Solapur, Maharashtra for construction of swimming pool and multipurpose hall

डॉ. जय सिधेश्वर महास्वामीजी (सोलापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1 अगस्त, 2004 को हुई है तथा इसका उद्घाटन 3 अगस्त, 2004 को महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद फजल के करकमलों द्वारा हुआ है। इसके पूर्व इसे सोलापुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था।

इस विश्वविद्यालय को डिजिटल विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र, पदार्थ विज्ञान शास्त्र, पर्यावरण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र और गणित शास्त्र ऐसे छह विभाग हैं। सामाजिक शास्त्र विभाग में पत्रकारिता का भी समावेश है। इस विश्वविद्यालय का केवल सोलापुर जिले के लिए ही निर्माण हुआ है। यह एक विशेष बात है।

इस विश्वविद्यालय की मालिकाना जमीन 527 एकड़ है तथा 1 लाख 25 हजार छात्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय से जिले के 110 कॉलेज संबद्ध हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ एक प्रस्ताव द्वारा 'खेलो इंडिया' योजना के अंतर्गत स्वीमिंग पूल तथा मल्टीपर्पज हॉल के लिए धनराशि की मांग की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु इन प्रस्तावों को मंत्रालय द्वारा धनराशि देने हेतु उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

(इति)

(1415/PC/SPR)

Re: Regarding Registration of Migrant Workers.

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य से प्रति वर्ष लाखों की तादाद में श्रमिक उत्तर प्रदेश के ईंट-भट्ठों में कार्य करने अपने छोटे बच्चों के साथ जाते हैं।

महोदय, संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है कि देश के किसी भी हिस्से में अपनी आजीविका चलाने के लिए वे जा सकते हैं। श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीयन न होने के कारण मजदूरों को दुर्घटना/जनहानि की मुआवजा राशि नहीं मिल पाती। कई भोले-भाले मजदूर अपनढ़ होने के कारण भटक जाते हैं। अनेकों मजदूर बंधक बना लिए जाते हैं। जैसे मेरे ही विकास खंड बागबहारा के ग्राम मूंनगासेर में कई व्यक्तियों की बाहर मृत्यु हुई। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं।

अत: केन्द्रीय श्रम मंत्री जी से मेरा निवदेन है कि छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को मजदूरों के पंजीयन कराने हेतु निर्देश पारित करें। पंजीयन हो जाने से मजदूर दुर्घटना, जनहानि का मुआवजा पाने के हकदार हो सकेंगे। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य हेतु चिकित्सालयों में नि:शुल्क उपचार भी होगा।

इसके साथ ही रेल मंत्री जी से भी गुज़ारिश है कि श्रमिकों के घर वापसी हेतु मई-जून के महीने में एक-एक सप्ताह स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से रायपुर, छत्तीसगढ़ चलाई जाए, जिससे मजदूर अपने घर सकुशल वापस आ सकें। धन्यवाद।

(इति)

Re: Need to set up a Trauma Centre in Raigarh Parliamentary Constituency, Chhattisgarh.

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रायगढ़ में पूर्व शासन द्वारा ट्रॉमा सेन्टर की स्वीकृति की गई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे धरमजयगढ़ हो या जशपुर हो, वह ग्रामीण इलाका है और वहां जनजातीय समाज के लोग निवास करते हैं।

ट्रॉमा सेन्टर, धरमजयगढ़ और जशपुर के लिए निहायत जरूरी है। वहां 300-400 किलोमीटर दूर हमारे निकटतम राज्य झारखंड में रांची में जाना पड़ता है। ऐसी जगह के लिए ट्रॉमा सेन्टर बहुत ही आवश्यक है। जैसे बिलासपुर और रायपुर में तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिनके द्वारा बहुत सारा उपचार किया जा सकता है, लेकिन जशपुर और धरमजयगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां ट्रॉमा सेन्टर की सख्त जरूरत है। यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि 377 में जो आपने लिखकर दिया है, उसी को सदन में पढ़ना पड़ता है।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल।

Re: Need to ensure completion of Bhavnagar-Somnath National Highway in Gujarat.

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : थैंक-यू, सर।

हमारे हिन्दू शास्त्र में जो ज्योतिर्लिंग बताया गया है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग हमारे यहां सोमनाथ में है। हमारी सालों की डिमांड थी कि मेरी कांस्टिट्यूएंसी भावनगर से सोमानाथ के लिए एक नेशनल हाईवे बनाया जाए। इसके लिए हमने पूर्व में बहुत सारे आंदोलन भी किए। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्रभाई मोदी साहब के आने के बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर भी किया गया और हमारे माननीय मिनिस्टर नितिनभाई गडकरी ने खुद आकर उसका शिलान्यास भी किया।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2017 तक यह मार्ग पूरा होना था, लेकिन वर्ष 2019 तक, अभी भी इस मार्ग का कोई ठिकाना नहीं है। जिन पांच पोर्शन्स में यह मार्ग बंटा है, उसमें से कहीं वह 60 परसेंट बना है। तलाजा से आगे तो सिर्फ 15-20 परसेंट ही यह मार्ग बना है। वहां आगे कुछ भी नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। रोड भी काफी खराब हैं।

अध्यक्ष जी, दूसरी मुश्किल यह है कि जो छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, उनके जो पैसे हैं, जो बिल हैं, वे भी अभी तक नहीं निपट रहे हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और आवागमन में भी बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां भावनगर-सोमानाथ नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द पूरा करवाने की कृपा की जाए। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। अगर आप पढ़कर नहीं बोलेंगे तो मुझे पढ़कर बोलना पड़ेगा।

विनोद सोनकर जी।

(1420/KDS/UB)

Re: Need to provide social security benefits to beedi workers in Pratapgarh district, Uttar Pradesh

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदय, बीड़ी उद्योग मुख्य रूप से एक ग्रामीण आधारित श्रम गहन उद्योग है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे इत्यादि राज्यों में एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। इन श्रमिकों में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक इत्यादि शामिल हैं, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं।

केन्द्र सरकार ने बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बीड़ी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के उपायों की व्यवस्था की है। लेकिन, अभी भी उनके परिवार के सदस्यों को आवास, शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ आदि का विस्तार किए जाने के साथ-साथ उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मॉडल कैरियर सेन्टर, ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल जैसी कल्याणकारी सुविधाएं सुलभ कराने की नितांत आवश्यकता है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुंडा में बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उपरोक्त सभी सुविधाएं प्रदत्त किए जाने हेतु आवश्यक पहल करे।

(इति)

Re: Need to release the balance funds for construction of under-construction bridge on river Yamuna in Etawah parliamentary constituency, Uttar Pradesh

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र इटावा के विधान सभा सिकन्दरा, ग्राम बेहमई, जिला-कानपुर देहात में वर्ष 2009-10 में यमुना नदी पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से लगभग 53 करोड़ रुपये की लागत से सेतु के निर्माण कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत

किया गया था जिसमें शासन द्वारा सिर्फ 49 करोड़ की स्वीकृति हुई, जिसमें 29 पिलर बनाकर निर्माण कार्य किया जा चुका है। बाद में आईआईटी, कानपुर के इंजीनियरों के द्वारा निरीक्षण करने के बाद सेतु की लम्बाई 5 पिलर और बढ़ा दी गई जो मेरे लोक सभा क्षेत्र की तरफ आता है। साथ ही दोनों तरफ सड़क बनाने का भी निर्णय किया गया जिसकी कुल लागत 17 करोड़ रुपये बताई गई तथा पूर्व में स्वीकृत लागत का भी 4 करोड़ रुपये शेष था। कुल 21 करोड़ रुपये अभी सरकार के द्वारा स्वीकृत होने हैं। सरकार द्वारा शेष बची राशि की स्वीकृति न होने के कारण यमुना नदी पर बनने वाला सेतु अभी वैसे ही निर्माणाधीन अवस्था में है, जिसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के लोगों को जालौन जाने के लिए 50 कि.मी. घूम कर जाना पड़ता है और कुछ लोग नाव के माध्यम से आते-जाते हैं, जिससे उनको काफी कठिनाइयां होती हैं। इस सेतु के बन जाने से कानपुर देहात से जालौन जाने वाले लाखों लोगों को सुविधा हो सकेगी।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि यमुना नदी पर बन रहे निर्माणाधीन सेतु को पूर्ण करने के लिए शेष बची राशि को स्वीकृत किया जाए, जिससे निर्माणाधीन सेतु को पूर्ण किया जा सके।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Khajuraho-Singrauli railway project in Madhya Pradesh

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो-सिंगरौली रेलवे लाइन का काम पूर्ण होने से इसका सीधा लाभ मेरे क्षेत्र को मिलेगा किन्तु खजुराहो-सिंगरौली रेलवे लाइन का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तथा किसानों को इसका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है एवं इसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ भी हैं। कई सालों से काम अपूर्ण है। सतना से पन्ना तक काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तथा पन्ना से खजुराहो का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ है।

इस परियोजना में किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में भी अनियमितताएँ हैं। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों को मिलने वाले मुआवजे की विसंगतियों को दूर किया जाये तथा साथ ही साथ खजुराहो-सिंगरौली रेलवे लाइन का काम शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

(इति)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभी श्री विष्णु दत्त शर्मा जी ने जो विषय उठाया है, मैं उस विषय के साथ अपने-आप को सम्बद्ध करना चाहती हूं, क्योंकि यह विषय मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष: थैंक्यू, श्री रवि किशन जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रीति पाठक जी, क्या आपको कुछ बोलना है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने यह क्यों बोला कि आपको सम्बद्ध करना है। आप अपना विषय बोलिए।
श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष जी, वह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
माननीय अध्यक्ष: आपने एसोसिएट करने के लिए बोला है। 377 में एसोसिएशन नहीं होता है।

(1425/MM/SNT)

Re: Need to provide adequate funds for development of Dubri Sanjay Tiger Reserve in Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के अंतर्गत धौहनी विधान सभा में स्थित दुबरी संजय टाइगर रिजर्व बाघों का प्राकृतिक निवास स्थान है एवं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र भी है। विदित है कि सर्वप्रथम सफेद शेर यहीं देखा गया था परंतु पर्यटकों हेतु मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों का रुझान व आकर्षण एक उच्च श्रेणी का पर्यटन स्थल एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी नहीं हो पाता, जिस कारण क्षेत्र व पर्यावरण दोनों का विकास अवरुद्ध है।

अत: मैं आपसे आग्रह करती हूं कि पर्यावरण एवं क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए यहां मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं सम्पूर्ण बाघ आरक्षित क्षेत्र को विकसित करने हेतु पर्याप्त बजट दुबरी संजय टाइगर रिजर्व को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to set up a National School of Drama in Gorakhpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल का प्रमुख शहर है जो उत्तराखंड, बिहार एवं झारखंड के करीब है। गोरखपुर की युवा पीढ़ी जो कला के प्रति जागरुक है और कला के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती है, लेकिन यहां की युवा प्रतिभा स्थानीय स्तर पर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ है। प्रदेश स्तर पर कई रंगमंच हैं जो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करती हैं। यू.पी. एवं बिहार तथा झारखंड की करोड़ों लोगों की आबादी है जिसमें लगभग 50 लाख युवा कला एवं साहित्य के प्रति रूचि रखते हैं। परन्तु कला को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई संस्थान नहीं होने के कारण युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। महोदय, अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में हो जाएगी तो स्थानीय युवाओं तथा पूर्वांचल के अन्य जिले, इसके साथ ही बिहार तथा झारखंड राज्य के युवा भी कला एवं साहित्य के गुण इस संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिल्ली एवं पुणे जाना पड़ता है।

अत: मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में एक एन.एस.डी. (राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय) की स्थापना की जाए जिससे यहां के युवाओं को लाभ हो सके।

(इति)

Re: Setting up of solar power plant in Jalaun district, Uttar Pradesh

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला जालोन में यूपीनेडा के माध्यम से एक 70 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना हेतु चयनित संयुक्त उद्यमी कंपनी द्वारा लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए कंपनी को भूमि की आवश्यकता है। इसीलिए कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को राजस्व संहिता की धारा 90 के अंतर्गत अनुमति लेने हेतु संपूर्ण कागजात सहित प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वायु प्रदूषण को कम करने एवं सस्ती ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए उक्त कंपनी को अनुमति दिलाने का कष्ट करें जिससे यहां के किसानों को सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी। इससे किसान सिंचाई से लेकर अन्य ऊर्जा से संबंधित सभी कार्य आसानी से कर सकेंगे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री संतोष पांडेय – अनुपस्थित।

Re: Need to expedite construction of new railway lines in Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, वर्ष 2018-19 में तीन नई रेल लाइनों अर्थात खानापुर-परली वैजनाथ, लातूर रोड –परली वैजनाथ और परली वैजनाथ-घाटनान्दूर का सर्वेक्षण किए जाने का अनुमोदन किया गया था। ट्रेनों के क्रॉसिंग, रेल इंजनों की दिशा बदलना आदि कामों में बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। यही नहीं सम्पर्क सुविधा की दृष्टि से भी इन नई रेल लाइनों का बिछाया जाना बहुत जरूरी है। लगभग दो साल का समय बीत जाने पर अभी तक इनका सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इन लाइनों के बन जाने से इस सेक्शन में रेल यातायात बहुत सुविधापूर्ण हो जाएगी, नई रेलगाड़ियों का चलाया जाना संभव होगा तथा साथ ही साथ रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऊपर वर्णित तीनों रेल लाइनों का सर्वेक्षण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाकर इन रेल लाइनों का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम – अनुपस्थित।

(1430/MM/RSG)

Re.: Need to promote amla in Pratapgarh parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के छ: विकास खंड आंवला फल पट्टी के रूप में घोषित क्षेत्र है जहां किसानों द्वारा प्रमुख रूप से आंवले की खेती की जाती है। जिनमें मंदिर/ट्रस्ट समिति द्वारा स्वयं प्रसाद चढ़ाने एवं वितरित किए जाने की व्यवस्था प्रचलन में है।

यदि इस प्रकार मंदिर/ट्रस्ट समिति द्वारा आंवले से बनने वाले उत्पाद का इस्तेमाल परम्परागत प्रसाद वितरण के साथ ही वितरित करने की व्यवस्था करा दी जाए तो एक अभिनव प्रयोग होगा और अमृत फल का भोग लगाने की सर्वथा उचित व्यवस्था होने के साथ-साथ जनपद प्रतापगढ़ में कटने के कगार पर खड़े आंवला बगान के किसानों को जीने का सहारा मिलने के साथ-साथ उद्योगविहीन जनपद प्रतापगढ़ को एक कुटीर उद्योग का सहारा मिल जाएगा।

(इति)

Re.: Need to set up bird watching park near Bhandup pumping station in Mumbai North-East parliamentary constituency, Maharashtra

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई नॉर्थ ईस्ट के भाण्डुप पंपिंग स्टेशन के करीब प्रवासी पक्षियों का हॉट स्पॉट है यहां प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में फलेमिंगो पक्षी लगभग 6 महीने मुम्बई के भांडुप पंपिंग स्टेशन के करीब आकर रहते हैं। नवंबर के महीने में फलेमिंगों यहां आ जाते है और मई महीने तक रहते है। यह बहुत ही आकर्षक होता है और मुम्बई की जनता फलेमिंगो के आने का प्रत्येक वर्ष इंतजार करती है।

मैंने माननीय शिपिंग मंत्री महादय से निवेदन किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले भाण्डुप पंपिंग स्टेशन के पास जहां फलेमिंगो का सबसे ज्यादा आना होता है, वहां पर एक फलेमिंगो पक्षी वाचिंग पार्क बनाया जाए और इसे एक टूरिस्ट एरिया के रूप में विकसित किया जाए। इस स्थान पर फलेमिंगो पक्षी वाचिंग पार्क बनाया जाए। इसमें एक टूरिस्ट प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं जैसे पर्पल हार्न, नॉर्थन पीनटेल, ब्लैकटेल गडविल, रूडी शेलडेक, ये कुछेक पक्षियों के नाम हैं जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षक होते हैं और यहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में आते हैं।

इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि भाण्डुप पंपिंग स्टेशन के पास का क्रीक एरिया जहां हजारों प्रवासी पक्षियों का निवास होता है, उसके पास फलेमिंगों बर्ड वॉच पार्क और आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट विकसित किया जाए और शिपिंग मंत्रालय की ओर से जरूरी सहायता संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(इति)

Re.: Need to take necessary measures to open a road between Tawang and Bhutan

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, Bhutan is a Buddhist nation adjoining Tawang which is a Buddhist populated district of Arunachal Pradesh and home to the 400-year old and the second largest Buddhist monastery in the world as well as home to many ancient Buddhist monasteries and holy places. Thousands of Buddhist pilgrims come to pay homage and pray at the monastery and other religious places in and around Tawang and vice-versa thousands of pilgrims cross over to Tashigang in Bhutan to visit age old monasteries and stupas of which the well known is the Gorsam Thorten Stupa every year.

Since time immemorial Bhutan is having trade relations with Tawang; in olden days people from Tawang used to visit neighbouring villages in Bhutan for rice and other ration items.

Opening of road from Bhutan would enable our farmers to easily access the markets in Bhutan and Assam. Due to long journey and lack of market, the scope of agriculture and horticulture in Tawang area is unexplored.

Opening of this road would enable aged people to reunite with their relatives and close family members.

The only hindrance in commuting between the two nations is the road connectivity. On the Indian side the road has been constructed till the border which is also the last Indian post with Bhutan guarded by the SSB personnel but from the Bhutan side they have not completed it yet.

This road should be open only for socio-economic and pilgrimage and in some cases for medical emergencies only and not for any military movement which will enable the people of both the countries to exchange the rich cultural heritage they share. The Government of India should take up the matter with the Royal Government of Bhutan.

(ends)

Re. Need to address the problem of regular traffic jam on NH-31 from Siliguri to Dhupguri in West Bengal

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Sir, the regular traffic jam on NH-31 from Siliguri to Dhupguri particularly from Jalpaiguri to Mainaguri through Teesta bridge is a regular feature.

The NH-31 is a stretch of about 80 kilometres starting from Siliguri to Dhupguri. Currently, construction work is going on and it has been found that due to the construction work for the past few months, traffic jam is a usual phenomenon. Due to this, people using the NH-31 including the students, ambulances, patients, army buses, all are suffering a lot to reach their destination on time.

Further, NH-31 is also crucial as it connects the entire north-eastern region with West Bengal.

Considering the importance of NH-31, I would like to request the hon. Minister to kindly expedite the work to avoid any daily traffic jam on NH-31.

(ends)

(1435/RU/SJN)

Re: Setting up of Institute of Tropical Horticulture under Kerala Agricultural University.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Kerala is the major producer of tropical horticultural crops such as coconut, rubber, pepper, cardamom, ginger, banana, cocoa, cashew, arecanut, coffee and tea covering 89.5 per cent of the total cropped area. Kerala's commercial horticulture is of national importance in terms of foreign exchange earned through exports. The Vazhakkulam pineapple, Chengalik Kodan banana and Malabar pepper of Kerala have been GI tagged and are very famous. We also export large quantities of vegetables, fruits and banana, foliage and flower crops. The State also has a vast wealth of medicinal plants and the Ayurveda industry in Kerala is growing fast. Value addition in horticultural crops is another sector which requires immediate attention. Horticultural crops have improved the livelihood security of the farming community. Kerala Agricultural University is catering to the agricultural education and research in the State but focussed research, education and development on horticultural crops are lacking. It is necessary to start a separate Institute of Tropical Horticulture under Kerala Agricultural University for improving the production/productivity in horticultural crops. This will improve the food, nutritional and livelihood security of the people. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare may take necessary steps to start this Institute in Kerala considering the huge potential.

(ends)

Re: Construction of an Overbridge at Puduppanam-Kottakkadavu Railway Gate

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I would like to raise a matter regarding the construction of an overbridge at Puduppanam-Kottakkadavu Railway Gate which is a long awaiting dream of the residents of western part of my parliamentary constituency, Vadakara. Daily, more than 80 trains are passing through this gate. The gate is kept closed for almost five hours a day. The distance between the National Highway and the Railway Gate warning point is hardly ten meters. When the gate is closed due to limitations of space, vehicles occupy most part of the National Highway Road which is already narrow

and thus, the traffic becomes a nightmare. During emergency, patients are delayed in reaching a certain specialty hospital due to frequent closure of gate causing danger to their life.

Apart from this, students going for high schools and colleges and people who are to take up trains face a lot of difficulties.

I, therefore, urge the Government to take necessary action to facilitate and construct above said overbridge at the earliest.

(ends)

Re: Promotion of tourism in Rayagada and Koraput Districts of Odisha

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Sir, Rayagada and Koraput districts in Southern Odisha are filled with pristine and unmatched natural beauty, lush valleys, perennial rolling mountain streams, religious and historical heritage, and rich tribal culture which provide huge potential for development of tourism and job creation. Developing specific themes will attract a lot of tourists due to the exotic location and heritage. I would urge the hon. Minister of Tourism to approve a few circuits under “Swadesh Darshan Scheme” given the huge potential.

Tribal Circuit includes key destinations like Rayagada, Gunupur (Puttasingh), Bantabiri Village, Onukadelli, Machhakund, Gupteswar, Nandapur, Kunduli, Koraput, Kurli, Kolab, Kakriguma, Sunki, Paduwa, Deomali and Rathibali, etc.

Religious Circuit includes key destinations like Rayagada, Chatikona, Padmapur, Bissamcuttack, Neelabadi, Koraput, Jeypore, Gupteswar, Sunabeda, Damanjodi, Subai, Nandapur, Pedapadu, Padua, Kechela and Ramagiri Tribal Hatt, etc.

The current footfall is 50,000 and with approval, this would increase manifold. I would request the Minister of Tourism to take necessary steps and approve the same.

(ends)

(1440/KKD/SJN)

Re: Celebration of Thiruvalluvar's Birthday on 17th January as National Thiruvalluvar Day

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Thiruvalluvar was a unique poet and philosopher, who was born 2000 years ago. His literature by the name 'Thirukkural' is one of the unique contributions in the world. With a couplet of 1330, Thirukkural is considered to be the face and property of Tamilians.

The Thirukkural has 133 chapters each one of them having 10 couplets. Nothing is untold in this book like education, health, Government, justice, nature and so on.

If a man fully follows the advice and principles of Thirukkural, he will become a man of perfection and incomparable to anybody in the world. Our Prime Minister, nowadays, whenever he goes abroad, he gives a quote of Thirukkural. When he speaks about water, he quotes Thirukkural by saying "Neerindri Amayathu Ulagu". The book has been translated in several Indian and foreign languages like Gujarati, Bengali, Hindi, Karnataka, Malayalam, Manipuri, Oriya, Rajasthani, Sanskrit and Telugu. Also, it has been translated in Arabic, Chinese, Malai, Urdu, French, German, Italian, etc. It is the only book translated in so many languages. No other book can claim this status. As the year calculated before Christ and after Christ, in Tamil Nadu, we also calculate the year on the basis of Thiruvalluvar birth and we call it as Thiruvalluvar Andu. On 16th January, the birthday of Thiruvalluvar, Tamilians celebrate Thiruvalluvar Day. Thirukkural is not only for one language or community, it is a book for the whole world and all languages. So, I appeal to the Government of India to celebrate Thiruvalluvar's Birthday on 16th January as a National Thiruvalluvar Day.

Re: Need to frame a National Menopause Policy

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Menopausal symptoms consist of a wide range of physical and psychological elements, which include night sweats, hot flushes, loss of concentration, changes and irregularity in menstrual flow and depression. India needs a clear policy to accommodate women employees both in Government and private sector, who are going through menopause.

Hence, I would request the hon. Minister for Women and Child Development through you to frame a National Menopause policy.

(ends)

Re: Need to eradicate manual scavenging in the country

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Sir, in spite of the fact that it is illegal, Government officers and private agencies are increasingly employing persons as manual scavengers on daily basis across the country. People die in sewer line and septic tanks. They should be given modern equipment. The atrocious practice continues rampantly across the country causing loss of dignity and lives of *dalits*.

Hence, I would urge the Government to take immediate steps to eradicate manual scavenging and rehabilitate them.

(ends)

Re: Financial assistance to Andhra Pradesh for implementation of projects under Navaratnalu scheme

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, the Chief Minister of Andhra Pradesh came up with Navaratnalu (9 Gems) Scheme for people to avail various kinds of benefits. Navaratnalu contains:

Financial assistance to 67,500 farmers under Rythu Bharosa.

YSR Aasara: Rs. 15,000 crore would be allocated for 89 lakh DWCRA women; and they would be given loans at zero per cent interest.

(1445/RCP/GG)

YSR Cheyuta pension of Rs.2000 per month to all eligible people above 45 years.

Amma Vodi aimed to financially help students on monthly basis. Students from Class I-V are given Rs. 500; for classes VI-X are given Rs. 750; and, Intermediate students will get Rs. 1000 per month.

Housing for poor – 25 lakh houses would be constructed for poor.

Medical assistance under Arogyasri to all treatments above Rs. 1000.

Fee reimbursement for students. About Rs. 1-1.5 lakh spent every year on each student.

Jalayagnam – to complete all irrigation projects. Priority is Polavarani.

Ban on alcohol.

Since Andhra Pradesh is in precarious financial condition, the Chief Minister of Andhra Pradesh has met the Prime Minister and submitted a Memorandum to help Government of Andhra Pradesh financially to implement Navaratnalu. Andhra Pradesh CM has also requested the Government of India to take up above Navaratnalu on pilot basis in Andhra Pradesh and replicate the same all over the country.

In view of the above, I request the Government to be magnanimous towards Andhra Pradesh and provide sufficient grant to Andhra Pradesh for implementation of Navaratnalu. (ends)

Re: Need to expedite Nagpur-Nagbhid broad gauge project in Maharashtra.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): महोदय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 116 किलोमीटर नागपुर-नागभिड, नैरोगेज मार्ग को बंद करने के साथ ब्रॉडगेज में इसके रुपांतरण के लिए डेक को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना सन् 2013-14 में मंजूर की गई थी। रेल विभाग ने कहा था कि " आमान परिवर्तन पर काम दिसम्बर में शुरू होगा"। एसईसीआर के नागपुर डिवीजन के तहत 650 किलोमीटर से अधिक नैरोगेज नेटवर्क में से 116 किलोमीटर नागपुर-नागभीड एकमात्र अपग्रेडेड शेष था। रेल विभाग ने कहा कि ब्रॉडगेज का काम 21 महीनों में पूरा होने का लक्ष्य है, तब इसे बेहतर सुविधाओं के साथ यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। 1400 करोड़ रुपये की नागपुर-नागभीड ब्रॉडगेज परियोजना भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें रेलवे और राज्य 280 करोड़ रुपये साझा करेंगे, जबकि 840 करोड़ रुपये का ऋण है। जब इस परियोजना की घोषणा की गई थी, तब इसकी लागत 400 करोड़ रुपये थी। यह लाइन बनने से यात्री ट्रेनों के साथ-साथ उत्तर और दक्षिण मालगाड़ियों के लिए सीधे लिंक का विकल्प होगी। ब्रॉडगेज परियोजना मूल रूप से क्षेत्र में बिजली संयंत्रों को कोयले के परिवहन को आसान बनाने के लिए है। यह लाइन बनने से चन्द्रपुर जिले में खदानों से कोराडी और खापरखेड़ा में कंपनी के बिजली संयंत्रों को कोयले की परिवहन दूरी कम होने से रेलवे को प्रतिवर्ष 152 करोड़ रुपये की बचत होगी।

अत: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे छात्रों, क्षेत्रीय लोगों सहित व्यापारियों को सुविधा मिल सके।

(इति)

Re: Need to ensure time-bound supply of LPG cylinders in Gopalganj parliamentary constituency, Bihar.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में गैस सिलेंडर की उपलब्धता की कमी है। गोपालगंज एक कृषि प्रधान जिला है। यहां की आबादी लगभग 21 लाख है। हर गांव एंव घर को गैस सिलेंडर मिले, यह सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि लोगों को 3-4 दिनों तक लाइन लगा कर इंतजार करना पड़ता है, फिर भी सभी को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता है। इस कारण कानून-व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। लोगों को मजबूर हो कर लकड़ी से खाना बनाना पड़ता है।

गरीब किसान, मजदूर एवं नौजवान का ज्यादा समय गैस जुटाने में लग जाता है। समस्या बढ़ती ही जा रही है। यदि गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली कम्पनी समय से सप्लाई करे तो इस समस्या का निदान हो सकता है। अत: सदन के माध्यम से मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में गैस सिलेंडर को समय पर सप्लाई करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, ताकि जनता की परेशानियों को शीघ्र दूर किया जा सके।

(इति)

(1450/SMN/GG)

Re: Review of Pension of Coal India Limited.

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Pension hike mechanism incorporated in the CMPS 98 under clause-22 for Review/enhancement of Pension of the Coal India Limited contributory pensioners is allegedly lying quite dead and defunct since the beginning of the scheme without making necessary fund provisions till 01-10-2017 in due compliance with the said scheme.

(ends)

Re: India's rank in Global Hunger Index.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): India is at the 102nd spot among 117 countries in the Global Hunger Index (GHI) that was released by Ireland-based Concern Worldwide, an aid agency. The country's ranking is eight spots below Pakistan (94) and 14 below Bangladesh (88). GHI uses indicators such as undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality to calculate the levels of hunger and under-nutrition worldwide, and India's score of 30.3 means it suffers from a level of hunger that is 'serious'.

There are two aspects of the 2019 GHI report that should worry the Government. One, India has the highest child wasting rate of any country (20.8%). Second, the child stunting rate is 37.9%. (ends)

Re: Bilateral talk of N.D.F.B and Government of India.

श्री नबा कुमार सरनीया (कोकराझार): महोदय, एनडीएफबी के साथ सरकार की वार्ता चल रही है जहां नॉन बोड़ो विभिन्न जिले से करीब 500 गांवों को शामिल करने की योजना चल रही है। बीटीसी समझौता होने के समय वहां के रहने वाले नॉन बोडो लोगों के लिए सम-अधिकार तथा उनके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रखने की बात हुई थी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उनके सभी अधिकार छीन लिए गए, इसलिए बीटीसी के लोग अपने गांव को अलग करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह अनदेखी कर के अगर कोई नया समझौता होगा तो बीटीसी की हालत बिगड़ेगी, क्योंकि सन् 2014 में हमारे चुनाव लड़ने से पहले बीटीसी में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए और लोगों के बीच आपस में टकराव की स्थिति अभी भी बरकार है। अभी तक छात्र नेताओं के हत्यारों को कोई सजा भी नहीं हुई।

(ends)

(1455/KN/MMN)

माननीय अध्यक्ष : श्री बदरुद्दीन अजमल – उपस्थित नहीं।

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम।

Re: Need to provide adequate compensation to farmers who suffered loss of crops due to heavy rains in Jamnagar Parliamentary Constituency, Gujarat.

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी किसानों के जीवन स्तर को सुधारने एवं उसको ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाओं की शुरुआत की है। किसानों द्वारा उपयोग होने वाले उपकरणों, बीज, खाद एवं सिंचाई की लागतों को कम किया गया है। नीम कोटेड यूरिया एवं प्रधान मंत्री आयुष्मान कार्ड योजना द्वारा किसानों के लिए कार्य किए गए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आय को दोगुना करने के लिए प्रयत्नशील हैं, फिर भी समग्र सौराष्ट्र क्षेत्र में हर बार फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में असंतोष दिखाई पड़ता है। इस बार भी गुजरात राज्य सरकार ने राहत पैकेज घोषित कर दिया है, परन्तु बीमा कम्पनियां जिस तरह से सर्वे करती हैं, उससे किसानों को समुचित भुगतान नहीं दिया जाता है। इस बार भी इस तरह की शिकायतें एवं फरियाद हमें प्राप्त हो रही हैं। प्रधान मंत्री ने कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी के इस शुभ कार्य में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियों की पॉलिसी एवं उनके कामकाज से किसानों को देश में प्राकृतिक आपदा से हुई फसल नुकसान की भरपाई समुचित ढंग से नहीं हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जामनगर, द्वारका एवं मोरवी में अतिवृष्टि से किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त है एवं उनके परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा काफी दयनीय हो गई है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प को पूरा करने के लिए बीमा कम्पनियों की मोनोपॉली को समाप्त किया जाए। बीमा कम्पनी के मनमाने सर्वे पर रोक लगाई जाए और हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया जाए, जिससे किसानों को हुए नुकसान का पूरा अंदाजा लगाया जा सके एवं किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा पूरा मिले। इसके लिए सरकार को ठोस एवं मजबूत कदम उठाना चाहिए, जिससे हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर सकें।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैडम, अच्छा पॉइंट बोल रही हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन नियम प्रक्रिया से।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, आइटम नंबर 7, द नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको पहले ले लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आज सदन दो विधेयक लेगा। कल का पूरा काम आज करना पड़ेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : ठीक है साहब। हम तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री सोम प्रकाश जी।

(1500/VR/CS)

NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN (AMENDMENT) BILL

1500 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the National Institute of Design Act, 2014, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

HON. SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to amend the National Institute of Design Act, 2014, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

1500 hours

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Hon. Speaker, Sir. I thank you for giving me this opportunity to speak on the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019.

At first glance, one might mistake it for a Bill of minor importance, because in essence, it gives four design institutes the status of national importance, just like the original Bill proposed to do with National Institute of Design, Ahmedabad in Gujarat. These four design institutes, which are situated in Madhya Pradesh, Assam, Haryana and Andhra Pradesh will now function as autonomous institutes. This was also proposed by the Standing Committee on Commerce in 2013. These institutes will also be able to grant degrees and diplomas to students pursuing academic courses there. *....(Interruptions)*

Dada, will you kindly take you seat? *....(Interruptions)* Sir, what is this? *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): सर, मैं ऐसे थोड़े ही हवा में बोलूँगी। ये बीच में बोल रहे हैं।…(व्यवधान) आप कल देख लेना, who has resigned or who has not. *....(Interruptions)*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): अभी यहाँ से निकलकर देख लेना।...(व्यवधान)

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): हाँ। ...(व्यवधान)

Therefore, the very first outcome of this Bill is that it gives the National Institutes of Design a much-needed professional outlook. I am glad that this Government under the competent leadership of Shri Narendra Modi ji has granted these four institutes the status of institutes of national importance. By doing that, this Government recognises the need for this much required link between design and industry.

1502 hours (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

Madam, a lot of industries require designers, whether it be housing or manufacturing, it can be textiles or technology, cinema, publishing, marketing. These are huge industries, which require skilled designers. There is a lot of scope for employment opportunities in these sectors, and this Government has rightly identified that scope and taken a decision that will, and I quote from the NID Act, "act as a nucleus for interaction between academia and industry."

Take the example of IITs. There has been a huge surge in sponsored research by MNCs, by various Ministries and by different Governments. The revenue generated through sponsored research has increased three to four times in the last 5 years. IIT Madras alone received projects worth Rs.546 crores in one financial year. IIT Delhi, Guwahati and Bombay earned more than Rs.300 crores each. These are stories of proven success. These are examples of what can be done when academia and industry interact and this is exactly what we hope that National Institutes of Design will do. By granting the status of national importance to these institutes, the Government is providing a platform to these institutions to provide design solutions to the world and not just India.

Hon. Madam, a major initiative of this Government has been to skill people in various fields and the importance of design in such an initiative cannot be undermined. A lot of scope is there in animation, graphic designing, film and video design. I have spent decades in the film industry. From costume designing to setting up the sets, designers are required everywhere. Even in theatre, there is a massive scope and we need to explore that.

My next point is regarding the development of tier 2 and tier 3 cities. Lately, India's growth pattern has moved towards tier 2 and tier 3 cities. With the

development of more than one hundred airports and metros functioning in over a dozen cities, with several others in the pipeline, urban design acquires great importance in today's India.

In fact, my constituency, Chandigarh, is known as one of the first planned cities in India. It continues to be one of the best examples in urban planning and modern architecture globally and an increased focus on urban design policy will be crucial in curating urban solutions of waste management, of pollution, of traffic, etc. I hope that National Institutes of Design will be instrumental in achieving that.

(1505/SAN/CS)

At the same time, we need to bring the traditional designs of India to the forefront. India, a Union of States, has always been proud of its diversity. In every State, even within States, if you go a few kilometres, you can see the changing nature of traditions and of design. We have a large number of folk designs, tribal designs and classical designs. We have the Gond art from Madhya Pradesh. We have immense and beautiful art forms from the States of the North-East. There is Madhubani from Bihar and Kalamkari from Andhra Pradesh. There are most wonderful and diverse weaves in various our places like Banaras and all of South India.

The artisans of these designs are based in rural parts of India. In order to preserve such art forms and develop them, an immediate intervention is required to make these art forms a part of the curriculum in the National School of Design. Further, marketing these beautifully designed products to the world, in the domestic or global markets, will directly benefit the local artisans.

Madam, I think, we all agree that we require a space where academia and industry can interact, and have a real time interaction, which is why I would give a few humble suggestions to the hon. Minister. These are related to the constitution of the Governing Council of these institutes.

Further, the Governing Council, as per the original Act, already has representatives from the Ministries of Finance, Higher Education and Information Technology. I would propose that the Ministry of Tribal Affairs should be also given a representation in the Council. It could be a member of the TRIFED, the body responsible for socio-economic development of tribal people by way of marketing development of the tribal products.

Our tribes have a rich sense of design which is reflected in their crafts and incorporating these in the mainstream study of design will open a plethora of opportunities for export of such products and will eventually lead to their development.

Lastly, I would thank the hon. Minister for bringing this Bill. I am confident that this Bill will be instrumental in helping us fulfil the aspirations of the new and modern India while taking our traditions forward and giving them modern solutions to reach out in the whole world.

Thank you.

(ends)

1508 hours

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Madam, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on this National Institute of Design (Amendment) Bill.

I would like to remember the families of Ford and Sarabhai who were institutional in setting up the National Institute of Design in Ahmedabad. Over a period of ten years, this idea was mooted and subsequently, it was decided to set up a National Institute of Design and it came into being in the city of Ahmedabad in 1961. Subsequently, over the past 50 or 60 years, there have been set up the National Institutes of Design by the Government in Gandhinagar, Bengaluru, Vijayawada, Jorhat, Kurukshetra and Bhopal, but sadly, though the Jorhat and Bhopal institutes were given the approval to start in 2009 and 2014, they have still not materialised and the institutes are not functional. I think, the Ministry should look into how earlier they can be started so that a lot more students can benefit.

Though the Government has only had a limited number of these institutes started, the private institutes have set up so many institutes which have given opportunities to several thousands of students who are studying different forms of designs like new media design, transportation and automobile design, apparel design, strategic design management, toy and game design etc. Earlier they were not given a bachelorhood, but now they are now being given a bachelorhood because of this Bill. That way, I feel that this Bill is going to help a lot of students to make a good livelihood in their lives.

(1510/RBN/RV)

Talking about design, I would like to say something about the place where I come from, that is Tamil Nadu. We are known for our architecture and handlooms. While we are talking about architecture, I am reminded of a dam called *Kallanai*. At a time when some dams do not last even for 30 or 40 years, this *Kallanai* which was built 2,000 years back is still functional. Earlier it was serving an area of 70,000 acres. With the enhancement of facilities, it is now servicing an area of 1,00,000 acres of land.

Similarly, I would like to cite the architecture of Mahabalipuram. Recently there was a visit by the Chinese President to Mahabalipuram. Prime Minister

Shri Narendra Modi hosted Chinese President in Mahabalipuram. They chose this place because of the age-old ties which exist between Tamil Nadu and China in the form of trade, etc. Everybody remembers only the visit of the present Chinese President. I would like to bring to the notice House that this is not the first time a Chinese President visited here. It was already visited by Premier Zhou Enlai in December 1956. During his visit he went to a village in Tamil Nadu where he spent some time. There are some inscriptions which are still there which talk about his visit. People do still remember the visit of the then Premier of China.

I would like to quote what he said during his visit. It is an awakening for a lot of people in our country to know about the excellence and growth of Tamil Nadu. He said:

> "Although it is only a few hours since I arrived here, I have already discovered from my first contacts with the city and its people that Madras is a city which has made outstanding contributions for the mighty culture of India. We believe that we can learn many things from your city that will be useful to us."

This is what he said that Tamil Nadu is a place where a lot can be learnt. It remains true even today from where a lot things can be learnt by the people of this country from our culture and our people.

At present there are 100 seats which are being allotted for under graduates in this basic design course and 285 seats for post-graduates. The fee is ranging from Rs. 1 lakh to Rs. 3 lakh or Rs. 4 lakh. I was wondering if some kind of concession can be given for people who cannot afford this kind of fee.

Having talked about the greatness of Tamil Nadu, I am surprised that not one college is found in Tamil Nadu. I feel it would be proper that a college of National Institute of Design should be there somewhere in Tamil Nadu, in any district of Tamil Nadu.

I hope if the present Bharatiya Janata Party Government changes its designs then it would be a lot more educative to the people. Thank you very much Madam.

(ends)

1513 hours

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): The National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019 seeks to declare four National Institutes of Design as Institutions of National Importance. There are four States where the NIDs are coming up. They are, the National Institute of Design, Amravati, Vijayawada; the National Institute of Design, Bhopal; the National Institute of Design, Jorhat, Assam; and the National Institute of Design, Kurukshetra, Haryana.

We are quite happy to know that more youngsters of this country are getting more opportunities, especially in the field of design and we welcome this decision. At the same time, there are minor concerns which need quite a bit of clarity. I think there are minor amendments to the Act, which are consequential in nature, such as to rename the NID, Vijayawada as NID, Amaravati and to designate the post of Principal Designer as equivalent to a Professor. Both are to be considered necessary.

(1515/SM/MY)

The problems to address are these. According to the article reported in the Hindu in 2016, the establishment of these four new centres would approximately cost around Rs.540 crore and it will create 2000 more seats. It is unclear as to how much it will cost for the establishment of these new centres.

According to that report, it seems that this was the cost when they planned to establish new centres in the following cities – Hyderabad, Kanpur, Bhopal and Jorhat. While the plan to establish centres in Bhopal and Jorhat has remained, Centres will now be established in Vijayawada, a two-tier city Amaravati and Kurukshetra, as opposed to Hyderabad and Kanpur. It is unclear as to how much the change will affect the Budget.

Madam, I come from a city called Cochin, where we have a lot of historical importance. We have 21 different communities across the globe including the Jewish in 16 square kilometre in a placed called Mattancherry in my constituency.

Historically, we have had trade – the Dutch, the Portuguese and other people had done the spice trade. The city holds a very historical position and it is also called the commercial capital of Kerala.

So, I would like to raise a very important point. We have a lot of ancient churches, temples, structures, monuments etc. Kerala is known as ‘God’s own country’. In Cochin, we have a lot of tourists coming every year and everyone who comes, understands the architecture and history of the place. I believe that there is a lot of scope in the area of design.

I would also like to mention that Cochin may also be included in this NID policy. We also uphold the right to have an institute in Kerala being a centre of excellence and, also it is a well-connected city. This place has a lot of industries. One NID can be considered in Cochin as well. Thank you.

(ends)

1517 hours

SHRIMATI SATABDI (BANERJEE) ROY (BIRBHUM): Thank you, Madam. We support the National Institute Design (Amendment) Bill, 2019.

मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के संस्थान डिग्री दे रहे हैं। Then why not in West Bengal? We have the National Institute of Design in Dum Dum. उसमें भी डिजाइन की डिग्री देने की परमिशन मिलनी चाहिए। अगर इन चार संस्थानों को डिग्री देने की परमिशन मिली है, तो उसको भी मिलनी चाहिए।

I have some suggestions and queries also. Training should be of that level वहां कैम्पस में जो इंटरव्यू होता है, उसमें लोगों को अच्छी तरह से जॉब मिलनी चाहिए। अगर इसको इंटरनेशनली कम्पीट करना है, तो faculties must be good.

मुझे लगता है कि इसमें और भी कोर्सेज़ आ सकते हैं। फैशन डिजाइन के अलावा अभी ऐसा भी हो गया है कि आप किसके साथ क्या पहनेंगे, वह भी डिजाइन में आ रहा है, जैसे- आप कौन-सा बैग लेंगे या कौन-सा शूज़ पहनेंगे। आज डिजाइन का मतलब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे डिजाइन्स हैं, जिनको इन्क्लूड करना चाहिए।

The chairperson must be an eminent academician, scientist, technologist, professional or industrialist to be nominated. It must provide more study options for the students. It must provide reservation to various courses for the SC, ST and Other Backward Class students. The institute must provide job opportunities to the pupil on regular and fair basis. That is more important.
अगर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, तो डिग्री से कोई फायदा नहीं होगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए so that we can compete with the international level.

It also says: Institute campus means the campus of an institute as may be established by such institute at any place within India or outside. If you say 'outside India', then why are you calling it the national institute? I also want to know as to who will provide the fund.

(1520/CP/AK)

जैसे IITs, IIMs में आल ओवर इंडिया कैम्पस इंटरव्यू हो रहे हैं, मेरी रिक्वैस्ट है कि और स्थानों पर भी कैम्पस इंटरव्यू होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद ने जितना अच्छा किया है, वैसे ही इंडिया में और भी स्टूडेंट्स आएं और डिजाइन बढ़े।

(इति)

1520 hours

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019.

It gives me lot of pleasure to speak on this Bill mainly because out of these four Institutes that are getting established or getting the status of national institutes of importance one is in Andhra Pradesh, that is, Vijayawada, Amravati. It is also because of the reason that the National Institute of Design (NID), which was established in Ahmedabad has done great service for our country, India. But as the speakers before me have already requested, I would also request the hon. Minister, not to restrict the National Institute of Design to 3 or 4 of them, but we should have them across the country.

We have more than 20 IITs in this country, and we can have one of the NIDs in each of the IITs or one of the NIDs in each of the NITs. I give this suggestion because of two reasons. Why do we need NIDs across the country? The first reason being that IITs have done great job for this country and done yeomen service for this country, and has put us on a higher pedestal with regard to the service industry. We have done extremely well, and we have got a lot of FDIs in respect to the service industry. But somehow, when it comes to manufacturing or design, we have always been left behind. Hence, I would request them to open even more NIDs across the country.

The second reason that I give for the Minister to open up more NIDs is that we need to take pride in the culture that we have in India. I give the example of our ex-Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu *Garu*, who believed and who tried to make everyone in Andhra Pradesh believe that a capital city cannot be designed by someone in India, but the capital city has to be designed by someone staying in Singapore or London. This is the kind of confidence that he has oozed on the people of India and Andhra Pradesh. We need to take that into account. …(*Interruptions*) We have to take pride in our own designs, and we want that to happen in India. …(*Interruptions*)

I would like to give the example of what happened in 1860s when the first ships came to Japan. …(*Interruptions*) They showed all the technological marvels of the western world, and the first one that they brought to Japan was

the steam engines. They showed the Japanese that they could build a lot of rail routes in Japan, but the Japanese said : "No, we are not going to just take your technology and place it in our country and let you run wild.". They said that : "You collaborate with our designers and engineers, and start the locomotive industry in Japan.". If you look 150 years later, the best super-fast trains across the world are there in Japan right now. So, that is how much design and thinking behind it has to be given importance; that is the pride when you look at the culture; and that is the pride you have to take in your own culture.

In conclusion, I would request the Minister to consider three things. Firstly, please look into the patents that are being filed by these NIDs because most of these patents, which are coming through, have to be related to the problems that are there in the society. They cannot be something that is not related to the society. So, please make sure that these patents are coming through. Secondly, think of the problems these NID students are taking up -- just like how Dr. Harshvardhan is doing it in the medicine sector wherein he is at least making the students to practice in the rural setting.

(1525/SPR/CP)

In the same way, students of National Institute of Design should take problems that are there in society and answer them. For example, the problem of pollution.

We have to have our own designs. We cannot expect the western countries to come and show us designs. We have to have designs for our farmers where the landholding is only one acre. We cannot expect the western nations to come and show designs for our country. We want our engineers to show us designs, and we need our designs to work.

Finally, I would request the Minister to expedite the process of allocating the budget and also to release funds so that these four Institutes would come up. Most importantly, I would request the Minister to ensure that the institute in Andhra Pradesh comes up as soon as possible.

Thank you once again for bringing this up and giving us the Institute of National Importance. In this august House, promises were made to a lot of hon. Members from Andhra Pradesh. One of them is setting up of the Institute of National Importance. Please fulfil those promises. I would also request the Government to fulfil other promises which were made. I would also request the Government to fulfil its promises of giving Special Category Status to Andhra Pradesh. Thank you very much for giving me this opportunity.

(ends)

1526 बजे

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदया, आपने मुझे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, जो अहमदाबाद का एनआईडी है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। हम सब एनआईडी के लिए गौरव लेते हैं, गर्व करते हैं। मैं इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताऊँ, तो एनआईडी, अहमदाबाद की स्थापना भारत सरकार, फोर्ड फाउंडेशन और अहमदाबाद के साराभाई परिवार, जिसमें इसरो के पूर्व चीफ स्वर्गीय श्री विक्रम साराभाई की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। उस संस्थान का भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एक नाम था। मैं पद्म भूषण विनर, 2011 श्री दशरथ भाई पटेल का जिक्र करूँगा कि उन्होंने एनआईडी में छात्रों की एजुकेशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसे आज भी लोग याद करते हैं। एनआईडी, अहमदाबाद की वजह से गुजरात और अहमदाबाद में उनका योगदान रहा है। अहमदाबाद एक जमाने में, it was known as textile city of India. It was also called the Manchester of India.

इंजीनियरिंग की अहमदाबाद में बहुत अच्छी इंडस्ट्री चलती थीं और अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ चलती थीं। इस क्षेत्र से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ के मामले में अहमदाबाद को हब माना जाता था। एनआईडी की वजह से गुजरात और अहमदाबाद की इंडस्ट्री को एस्थेटिक रिलेटेड डिजाइन क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पहचान मिली थी। एनआईडी की वजह से गुजरात में बहुत सारे जो डिजाइन क्षेत्र से जुड़े हुए संस्थान हैं, ऐसे संस्थान अहमदाबाद और गुजरात में बने हैं। अगर मैं इनका जिक्र करुं तो निफ्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन जो गांधी नगर में स्थापित किया गया है, यह उससे ही एक प्रकार से जुड़ी हुई संस्था गुजरात में है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको हम एफडीडीआई के नाम से जानते हैं, वह अंकलेश्वर में बना है। 'सेप्ट', सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद में है और कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अहमदाबाद में बना है। कहीं न कहीं एनआईडी की वजह से ये सब इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में खुले हैं।

अहमदाबाद में जो एनआईडी बना, वह पहले डिग्री नहीं डिप्लोमा प्रदान करता था। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और हमारे मंत्री जी एनआईडी अमेंडमेंट बिल, 2014 लेकर आए और इस इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपोर्टेंस का स्टैटस दिया गया। इसकी वजह से इसकी एक बहुत बड़ी पहचान बनी।

(1530/NK/UB)

जो उसमें सुधार किए गए, उसकी वजह से इसे वर्ल्डवाइड रिकग्निशन मिला। जो बिल लाया गया है, उसकी वजह से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में डिग्री प्रदान करने की क्षमता मिली, इसकी वजह से एनआइडी, अहमदाबाद को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान मिली, इसकी वजह से अलग-अलग स्टुडेंट अहमदाबाद में आने लगे। देश-विदेश की रिनाउन्ड फैकल्टी अहमदाबाद आने लगी क्योंकि रिसर्च और प्रशिक्षण में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज सरकार इस बिल को

लेकर आई है। इस बिल में प्रावधान है कि अहमदाबाद जैसे कुल चार नए संस्थान देश के अलग-अलग भागों में बनाए जाएंगे। जहां तक दक्षिण भारत का सवाल है, आंध्र प्रदेश में अमरावती में इसकी स्थापना की जाएगी जो देश का हार्ट है। मध्य प्रदेश, भोपाल, पूर्वोत्तर राज्य असम के जोरहट और हरियाणा के कुरूक्षेत्र में एनआईडी संस्थान की स्थापना होगी। ये सभी अहमदाबाद की तर्ज पर बनेंगे। जिस प्रकार से अहमदाबाद में 2014 में अमेंडमेंट आया और यूजी और पीजी में जिस प्रकार डिग्री प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जिस प्रकार से यह संस्थान बनाया गया, उसके लिए मैं अपनी सरकार और यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं।

पचास साल पहले 1961 में एनआईडी की अहमदाबाद में स्थापना हुई थी। इसके बाद एनआईडी को मजबूत करने का अगर किसी ने कोई कार्य किया है तो हमारी सरकार और प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इस संस्थान में पहले वरिष्ठ डिजाइनर का पद था। इस बिल में उसको अपग्रेड करके प्रधान डिजाइनर किया गया है और उसे प्रोफेसर के समकक्ष माना गया है। इस बिल से जो फायदा होने वाला है, इस बिल की वजह से अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे, उत्तर पूर्व के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, पश्चिमी राज्यों को अलग-अलग नया अवसर मिलेगा। इसके लिए डिजाइनिंग क्षेत्र में जो स्किल्ड मैनपॉवर है, हमारे देश में अलग-अलग लोग स्किल से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे ग्रामीण, हमारे गरीब, हमारे किसान, हमारे आदिवासी और हमारे दलित के हाथों में जो हुनर है, उस हुनर को वैल्यू एडिशन मिलेगा। मेरा कहना है कि इसकी वजह से गांव से जुड़े हुए हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई कला है, जो डिज़ाइन है, जो हुनर है, उसकी वजह से रोजगार का सृजन होगा। मैं इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो डिजाइनर है जो प्राइवेट पार्टनर हैं, उनके साथ उनका एमओयू होगा। जो गांव में बसे हैं, जो लोग पवर्तीय प्रदेश में बसे हैं, जो लोग जंगल में बसे हैं, प्राइवेट पार्टनशिप से उनको एक नई पहचान मिलेगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए यह बहुत अह्म रहेगा। मैं इस बिल के बारे में मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। Ahmedabad NID is an established institution.

मेरा सरकार से एक निवेदन है कि अहमदाबाद एनआईडी की जो सीट है, उनकी जो कैपेसिटी है, स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी लोगों को यहां आने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे इस इंस्टीट्यूट को वैश्विक पहचान मिलेगी। अहमदाबाद एनआईडी के स्टुडेंट जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें डिजाइन की क्षमता का अवसर प्राप्त होगा। इसी वजह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने मेक इन इंडिया का सपना दिया है, जो स्टार्ट-अप का सपना दिया है। अलग-अलग प्रदेशों के हुनर से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, गरीब है, आदिवासी हैं, दलित हैं और आर्टिजन हैं, उनको मेक इन इंडिया में बल मिलेगा। भविष्य में अहमदाबाद के सिवाय चार नए एनआईडी बना रहे हैं।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि हर राज्य को एक एनआईडी मिलना चाहिए। भारत एक विविधता से जुड़ा हुआ प्रदेश है। भारत के सभी प्रदेशों में हुनर है, सभी प्रदेश में लोगों में डिजाइन की क्षमता है, चाहे वह गांव का गरीब हो, चाहे वह पढ़ा-लिखा न हो, तब भी उनके हाथों में कौशल है। अगर हमें इस कौशल को बाहर लाना है तो हमें हर राज्य में इसके लिए काम करना चाहिए। इससे हस्तकला की पहचान रहेगी।

(1535/SNT/NK)

मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर होने के नाते मेरा सुझाव है कि मेडिकल क्षेत्र में अलग-अलग गैजेट्स, हैल्थ इक्विपमेंट्स होते हैं, इनमें भी एनआईडी का योगदान होना चाहिए। एनआईडी पीपल्स फ्रेंडली डिजाइन्स होता है, जैसे हैल्थ से रिलेटिड इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं, स्टुडेंट यूजी और पीजी को प्रोजेक्ट देना चाहिए, they can evolve the things. इसमें चाहे आर्टिफिशियल लिम्ब हो, प्रोसेसेज़ हों, हम जयपुर फुट से मंगाते हैं। अगर एनआईडी के स्टुडेंट्स की इसमें भागीदारी रहेगी तो आर्टिफिशियल लिम्ब में बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं और यह पेशंट फ्रेंडली रहेगा। आर्टिफिशियल लिम्ब, जो वॉकिंग स्टिक्स, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड फ्रैंडली बैठने की सीट होती है, दिव्यांगजनों को बैठने में कई सारी दिक्कतें रहती हैं, मैं समझता हूं कि इनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के स्टुडेंट्स अगर कुछ योगदान देंगे तो सीट को भी फ्रैंडली बना सकते हैं। ये सब सिलेबस में जोड़ना चाहिए।

मेरा एक और सुझाव है। बैचलर और अन्य प्रोग्राम की वार्षिक फीस करीब दो लाख रुपये है या कभी इससे भी ज्यादा होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि महिलाओं, गरीबों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ शिक्षावृत्ति का प्रावधान रखना चाहिए ताकि एनआईडी के पाठ्यक्रम, सिलेबस में भागीदारी निश्चित हो। माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मंत्र को लेकर चल रही है, इसलिए हमें इसे करना चाहिए।

गुजरात में पूरे देश में नमक प्रोवाइड करने के लिए अगर कोई राज्य है तो गुजरात है। मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना था, तब वह गुजरात के मुख्य मंत्री थे, रेलवे के वैगन्स साल्ट भेजते हैं उसकी वजह से कोरोज़न होता है, क्योंकि वह स्टील से बना होता है। क्यों न इसमें एनआईडी लोगों की राय ली जाए, फैकल्टी की राय जी जाए, स्टुडेंट्स की राय ली जाए और फाइबर के वैगन के जरिए भेजा जाएगा तो कोरोज़न नहीं होगा। इसके अलावा लाइट व्हीकल की वजह से फायदा होगा।

अहमदाबाद एनआईडी की जो पहचान है, वह पूरे विश्व में एक अलग प्रकार से बनी है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एनआईडी बिल लेकर सरकार सदन में आई है। हम सब दलगत राजनीति को दरकिनार करके सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें।

आपने मुझे बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1539 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I rise to support this Bill which proposes to give NID Andhra Pradesh the tag of an Institute of National Importance, along with four other NIDs in the country, and I would like to thank the hon. Minister Shri Piyush Goyal Ji for this.

As is mentioned in the Bill, the NID at Amaravati, a region which I represent in this House, has already been established in 2015 and started its academic session from Nagarjuna University in a temporary campus. A 50 acre plot has been given to the Ministry for constructing the required infrastructure, hostels, and other facilities. But the point is, it was promised that academic blocks, hostels and staff quarters would be completed by June of this year.

(1540/RSG/SK)

We are at the fag end of the year now but the required infrastructure is still at a nascent stage. This is resulting in a lot of inconvenience to students as they are not able to take up their planned activities.

If you look at clause 1 of the Bill, which deals with the short title and commencement, it clearly says that this Act will come into force on such date as the Central Government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act. I am not able to understand what exactly this means. Does it mean that whatever degrees and diplomas are issued by NID, Amaravati are valid only after a gazette notification under this Act is issued? That is a big question because NID started its academic classes in 2015 at Amaravati and if I am correct the fifth batch has joined. This means that at least one batch has passed out with degrees and diplomas. The question I would like to ask the hon. Minister is this. What is the fate of the students who were issued the degrees and diplomas? How are the degrees and diplomas valid when you are giving legal backing to NID, Amaravati prospectively and it is clearly indicated in clause 1 of this Bill? I would like the hon. Minister to clarify what would happen to the degrees and diplomas issued by NID, Amaravati so far.

If you look at the explanations to clause 7 of the Bill, there is some confusion. The first explanation says that his Act is deemed to have come into force as far as NID, Ahmedabad is concerned from September, 2014, but when

it comes to NID, A.P. and the other NIDs, the explanation 2 says that the commencement of this Act will come into force as and when the provisions of the NID Act come into force. It means, it will come into force only when notification is issued as is mentioned in clause 1. So, I want to ask the reasons behind this discrimination between NID, Ahmedabad and the other NIDs in this country. What will happen, again as I asked earlier, to the degrees and diplomas issued by NID, A.P. so far?

Finally, Shri Shekhar Mukherjee, the Director of NID, Amaravati has rightly said that design is neither a decorative art, nor is it about technology or fashion; design is an attitude, a way of life, and is not exclusive but inclusive, and should always be human-centric. However, if you look at design education in our country, it is still in a rudimentary stage, as it is a new subject for our country. It is surprising to note that we are still at a nascent stage in designing in spite of having a rich treasure of arts and crafts when compared to the western countries. I would, therefore, like to know from the hon. Minister how we can connect our talented artistes and artisans with students of design to create a new Indian renaissance of design and make India the design hub of the world.

There is a Ph.D. programme in NID, Ahmedabad but in NID, Amaravati, there is only a bachelors and a masters programme. So, I would like to know from the hon. Minister when he is going to introduce the Ph.D. programme in NID, Amaravati.

Finally, before I conclude, the hon. MP from YSRCP spoke about Amaravati and I need to respond to that. First of all, I would like to thank Shri Amit Shahji and Shri Kishen Reddyji for responding to my ‘Zero Hour’ submission last week where I pointed out that the capital of A.P., Amaravati has been left out of the political map. Within a day, this was realised and corrected. So, I would like to thank the hon. Ministers. But in Amaravati Rs. 9,000 crore have already been spent to build the city; another Rs. 50,000 crore worth of projects have been stranded at different stages. The election promise of Shri Nara Chandrababu Naidu in 2014 was to build a capital as great as Singapore; Singapore was brought in to help us develop the masterplan. Foster and Partners from London, known for their iconic Apple headquarters in California, were brought in as architects. The NID, Amaravati was also brought in to work along with these world-renowned architects and they are richer for the experience. It is ironic that the hon. MP from YSRCP is talking about design when all they have done since coming to power is only stopping and destroying what has already been built.

Thank you.

(ends)

1544 hours

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Thank you very much, Madam.

The National Institute of Design Bill, 2019 seeks to amend the National Institute of Design Act, 2014, which declares the National Institute of Design, Ahmedabad as an 'institution of national importance' and further declares four National Institutes of Design at Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Assam and Haryana as 'institutions of national importance'.

(1545/PS/SK)

Madam, although it is a very welcome move to have these NIDs in these States, as part of institutes of national importance, but two of the biggest States in the country, UP and Bihar, and also many more States in the entire country, are yet to have their own NIDs. Such States need their own National Institutes of Design, which are of national importance. But I particularly talk of these two States as these northern States hold about 40 per cent of the country's population. Unless we have institutes of such calibre in these States, it will not be possible to create employment and also to further business in these States. The States, where there are untapped talents, such steps would provide a welcome respite.

I would also say that it is very important that in the National Institutes of Design we also focus on handicrafts. We have a huge tradition of handicrafts and crafts, but it has not gained any place in studies or researches in our National Institutes of Design. I would suggest the hon. Minister here that the study and research of our own indigenous handicrafts should be brought into the ambit of the courses that are provided in our national institutes.

The National Institute is set up to improve the design capabilities of India's small and medium enterprises. We need to pay greater attention to the design of our crafts industry because without a thriving craft industry, we cannot showcase to the world and we cannot even export, our ancient traditional craft with better quality and better design. In order to do so, such courses have to be implemented in our design institutes. So far, we have introduced the National Institute of Fashion Technology, the Footwear Design and Development Centres, but handicrafts are still left out.

So, I urge upon the hon. Minister, who is present here, to kindly take this into account and also put in the study of handicrafts and handlooms that still remain outside the ambit of design institutes. Students who enter NIDs should have the option of specializing in craft and design. Unless you are going to upgrade the traditional handicrafts and artisanal skills, you are not going to be able to expand employment and you are not going to be able to expand exports. So, it is of utmost

importance that we take handlooms and handicrafts under the ambit of the National Institute of Design and provide such courses. There was an hon. Member who has just mentioned here that the fees, that are charged in these institutes, are fairly high. As has been said by the hon. Member, it is over Rs. 2 lakh. खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे भारतवर्ष के एससी और एसटी लोगों को संस्थान से जोड़ने के लिए अत्यंत जरूरी है कि हमारे देश में इन संस्थानों में फीस का प्रावधान कम किया जाए और उनको फ्री एजुकेशन प्रदान करके इस डिजाइन इंस्टीट्यूट की मुख्यधारा से जोड़ा जाए ताकि वे देश की उन्नति में पूरी तरह से भागीदारी निभा सकें।

I would also like to point out here that the Standing Committee had also recommended that the Chairperson of the Governing Council of the Institute should be an academician from the field of design only. But currently, what we have is that the Chairperson can be an eminent academician, scientist or technologist or professional or industrialist, to be nominated by the President of India. This, I think, also needs a fair amount of study. We need to look at the fact that the National Institute of Design ought to be headed by somebody who is an expert in the field so that they may be able to strengthen the institution in itself and take it forward.

(1550/RU/MK)

At the end, as per section 6(1)(m), I would suggest that the Institute should establish, develop and equip courses and centres for research, workshop promoting traditional and indigenous and cultural designs of various parts of India.

Madam, I thank you very much for allowing me to speak and I appreciate this opportunity. I hope that the hon. Minister will make specific provisions for fee discounts or free education for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this Bill as well.

(ends)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, who is the Minister responsible for this Bill?

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Shri Som Prakash, Minister of State for Commerce and Industry.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Would you please sit down, Prof. Ray?

… (*Interruptions*)

1551 hours

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Madam Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on this very important Bill today.

First of all, it is very heartening to see that design has been brought to the forefront. It is indeed a big recognition for the design profession in the country and this Bill will give an impetus to the activities of the Institute, giving design in India a global foothold.

The students and faculty will get immense benefit with this recognition. This status will also help in repositioning of the Institute globally for networking with premier design institutions, create additional opportunities for research scholars, faculty and student exchange and boost design research in the country.

These units of NID in different regions of the country will help produce highly skilled manpower in design by providing sustainable design interventions for rural technology, crafts, handloom, small, medium and large-scale enterprises and outreach programmes for capacity, capability and institution building.

Setting up of more branches of National Institute of Design in different regions of the country will add to producing highly skilled professionals in the field of design and will create ample job opportunities in small, medium as well as large scale enterprises.

Madam, I would specially request the hon. Minister of Commerce and Industry for setting up a unit of the National Institute of Design at Hyderabad as there has been injustice done to our State of Telangana. The current NID centre at Vijayawada was actually sanctioned for Hyderabad but due to bifurcation, it was shifted to Vijayawada.

A branch of the National Institute of Design should be sanctioned to Telangana or the current NID Centre at Vijayawada should be shifted to Hyderabad at the earliest. This is my humble request to the hon. Minister of Commerce and Industry.

(ends)

1554 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019.

Over the last 60 years, the Parliament has declared 134 institutions as Institutes of National Importance. It started way back in 1956 with IIT, Kharagpur and we are now going to add four more institutions in this Session.

Simply declaring institutions as Institutes of National Importance is not enough. Many institutions are facing several challenges. We must think about those challenges seriously. The main problem in the Institutes of National Importance is not students but faculty. They get the best students because they come through competitive examinations and we select the best but as regards faculty, we have a long way to go. Even in IITs, the faculty shortage is anywhere between 30 and 40 per cent. In IIMs, the faculty shortage is anywhere between 20 and 30 per cent and these are Institutes of National Importance.

My earnest request to the hon. Minister is to please pay attention to faculty development in the Institutes of National Importance.

(1555/KKD/IND)

But at the same time, tuition fees and hostel fees have been increasing day by day. The students are getting agitated against this fee hike.

Taking this opportunity, I would request the hon. HRD Minister to intervene in the matter and settle the strikes including the strike in JNU.

While coming back to the Bill, I do agree that the Institution like the National Institute of Design has a big role to play in social development and employment generation. The National Institute of Design was set up to improve the design capability of India’s small and medium enterprises. NIDs have the option of specialising in craft design because unless you are going to upgrade the traditional handicrafts and artisan skills, you are not going to be able to expand employment and exports either.

So, I think that focus on craft is needed. Social innovation at the grass-root level is very important. I would request the Government, which came forward with ‘Make in India’ to start a ‘Design in India’ Programme as it would expand employment and exports; and it would also deepen the roots of social innovation, which our neighbouring countries are doing.

With these words, I conclude. Thank you. (ends)

1558 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019.

Madam, I feel that this Bill is in the proper direction and I also feel that it is a good move. Once this Institution is made a national institution, it would enable to grant degrees and diplomas to students. In addition to this, they would have freedom in designing the courses, conducting the examinations and other similar kinds of things.

Madam, marketing side is also very important. 'Made in India', and 'Design in India' will have an impact. It would also meet the demand of employment generation. Similarly, consumer attraction is also very much involved here. So, in order to achieve all these things, we have to make our education system up to the international standard.

This Bill is a good move. Instead of offering conventional types of degree courses on the higher education side, we have to foresee heralding the new era at the national and international level. India is blessed with talented young manpower. With optimum utilisation of manpower in accordance with the developing world market, India can rise and come to the forefront.

Upgradation of accessing design colleges to universities will create more and more avenues to us. Employment opportunities in India and abroad is also very attractive. Industries need such persons.

If we look at the salary side, salary part is very attractive for the designers. For example, an average salary package, nowadays, available for an average fashion designer is Rs. 3.50 lakh. For a graphic designer, it is Rs. 2.70 lakh; for a UI/UX designer, it is Rs. 6 lakh; and for a textile designer, it is Rs. 3.60 lakh. These are very attractive packages.

Among the top 15 countries in the world, India is a very less expensive country in the education sector. So, we can attract foreign students also. The expenses in the Indian higher education are comparatively less. Similarly, the medium of instruction in the Indian higher education sector is English. So, in all these ways, we can attract students from different parts of the world.

Now, I would like to emphasis on a very important point. Giving autonomy and giving national status for higher education institutions is a very good and welcome move. But here, we have to be very careful also. What is it? Autonomy should not be an Open General Licence for the higher education institutions to do anything according to their desire. One thing is sure. As has been pointed out by a Commission, autonomy should be coupled with accountability. It is the most important point.

Another important point is affordability. Affordability of all sections of society is very necessary. It should not be unreachable for the poor students. Similarly, like all kinds of reservation systems, this kind of system also should be strictly adhered to.

Madam, I would like to cite a very classic example. I do not look at JNU. I am talking about IIM, Chennai and BHU. What is happening there? We have given them freedom. That is okay. But we must understand one thing. The hon. Minister is accountable to this Parliament. He is accountable to the tax-payers. If the university or the national institutions believe that they can live in an island of their own, which is undisputed and unquestionable, that is not acceptable. They must have accountability to the people. But what is happening there? Recently, the hon. Minister of Education issued a Circular on IIMs.

(1600/RCP/IND)

In the Circular, he talks about SC/ST/OBC faculty in IIMs. He has given the figures. Those figures are with me. In IIMs, they are denying reservation. Some caste-based kind of consideration is prevailing in such an institution. The hon. Minister has warned all the IIM people not to go in this direction. It should be reachable and this kind of reservation principle should be strictly adhered to.

My next point is this. This country is that of poor. We know, there are crores and crores of people below the poverty line. We should not close the doors of higher education for the poor students. They must have access to those institutions.

What I am saying in brief is this. All these kinds of things are good. We must have a national institute. India is having a bright future. The most talented young manpower resource is there in India. Everywhere, we have got chances. Indians are having that much of prominence around the world. As I said in the beginning, we can attract students from foreign countries also. India is going to have a golden era. In this regard, I would like to say that we must ensure social justice. Social justice should be strictly adhered to. I welcome this move. At the same time, you must take into consideration the points which I have humbly raised.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1602 बजे

श्री पल्लब लोचन दास (तेजपुर): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन मैनेजमेंट बिल, 2019 को लाकर असम में नया एनआईडी बनाने और एनआईडी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाने का जो सिद्धांत लिया, उसके लिए मैं असम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज के समय डिजाइन का बहुत महत्व है और डिजाइन द्वारा हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं।

1603 बजे (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार <u>पीठासीन हुईं)</u>

आज के समय हम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं और हमारे जितने भी नई पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, उन्हें हम रिसर्च करने का, अच्छी ट्रेनिंग देने का और मार्केट रिसर्च करने के बाद पढ़ने का जो मौका और माहौल दे रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें रिसर्च करने का मौका देंगे और उन्हें टेलेंट दिखाने का मौका देंगे, तो देश में एक नया माहौल बनेगा। आज एनआईडी के द्वारा यह माहौल बन रहा है। एनआईडी द्वारा हम जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वे स्टूडेंट्स जा कर मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं और सभी चीजों को देखकर वे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स सभी राज्यों में होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारे जैसे राज्यों में आज बच्चे ऐसे कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिनसे हम केवल क्लर्क ही बनते हैं। हमारे लिए टेक्नीकल नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को टेक्नीकल नॉलेज बहुत ज्यादा थी और हम लोग टेक्नीकली बहुत साउंड थे, लेकिन टेक्नीकल इंस्टीट्यूट्स न होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज असम में एनआईडी बन रहा है। अभी भी एनआईडी है, लेकिन एनआईडी केवल डिप्लोमा तक ही सीमित है और वह डिग्री नहीं दे पा रहे हैं। अभी एनआईडी मास्टर्स नहीं दे पा रहे हैं, पीएचडी नहीं दे पा रहे हैं।

(1605/ASA/SMN)

अगर यह बिल आएगा तो इस बिल के माध्यम से वह डिग्री उनको मिल पाएगी, मास्टर्स वे लोग कर पाएंगे और वे लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। सरकार ने यह बहुत अच्छा इनीशिएटिव लिया है। हम चाहते हैं कि वहां पर जो भी कोर्सेज हैं, उनका दायरा और भी बढ़ाना चाहिए। अभी जो-जो कोर्सेज हैं, जैसे एनीमेशन फिल्म डिजाइन, सैरेमिक एंड एग्जीबिशन डिजाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, फर्निचर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, प्रोडक्ट एंड टैक्सटाइल डिजाइन ये सारे जो डिजाइन हैं, इनमें दूसरे नये-नये और हम लोगों के ट्रेडीशनल डिजाइन को भी इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आसाम में जो अभी सीट कैपेसिटी 60 है, उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा मैं आग्रह करूंगा। वहां पर फैकल्टी भी बढ़ाना चाहिए। फैकल्टी की वहां पर जो क्वॉलिटी होनी चाहिए, वह इंटरनेशनल लैवल की होनी चाहिए।

यहां बिल में बोला गया है, हम लोग कैम्पस बना सकते हैं। देश के बाहर भी हम लोग कैम्पस बना सकते हैं। इसलिए यह भी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके साथ

हमको भी कम्पीट करना है। इंटरनेशनली बच्चे को या हमारे नये स्टूडेंट को उस लैवल तक लेकर जाना है। हम लोगों ने एन.आई.डी. अहमदाबाद को देखा है। वहां बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। एनआईडी, अहमदाबाद के थ्रू अभी इंटरनेशनली एनआईडी, अहमदाबाद को बाहर भी और यू.एस.ए. में भी रिकॉगनेशन मिला है।

मैं असम के संदर्भ में बोलना चाहूंगा। हम बोलते हैं कि हमारे सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर जो शंकर दीप जी थे, उन्होंने उस समय वृन्दावनी वस्त्र बनाया था, जिसे वृन्दावनी वस्त्र बोला जाता है। उनका जो बनाने का हुनर है, लंदन में वह म्यूजियम में है, अभी असम में वह नहीं है। उस लैवल तक हम लोग टैक्सटाइल, टैक्नीशियन को आगे ले जा सकते हैं। असम में सबसे बढ़िया सिल्क मिलता है। उस सिल्क को कितने अच्छे डिजाइन तक हम लोग ले जा सकते हैं, उसकी भी अगर वहां पर व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।

वहां पर बेल मैटल के कारीगर रहते हैं। उनका भी ट्रेडीशनल डिजाइन है। उस डिजाइन को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं और हमारे जितने भी ट्रेडीशनल डिजाइन्स हैं, उन डिजाइन्स के ऊपर अगर हम लोग रिसर्च करके उसी डिजाइन को अगर हम लोग एनआईडी में इंक्लूड करते हैं और उसको पढ़ाने की अगर हम लोग व्यवस्था करते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। इससे हमारे स्टूडेंट्स भी सीखेंगे और हमारे जो भी कारीगर्स हैं, उनको एक मार्केट मिलेगा। उस लैवल तक अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एनआईडी के थ्रू मैं यह भी बोलना चाहूंगा क्योंकि एनआईडी के स्टूडेंट्स को दूसरी-दूसरी जगहों पर भी लेकर जाना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे हायर सैकेंड्री लैवल के स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में उन लोगों को ले जाकर उनका इंटरेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। जितना नये-नये बच्चों के साथ वे लोग इंटरेक्शन करेंगे, उनको भी टैक्नीकली आगे बढ़ने के लिए उतनी ही प्रेरणा और अवसर मिलेगा। मैं यही आशा करता हूं कि जो अभी हम लोग नया एनआईडी बना रहे हैं, उसकी क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा रहे हैं, एक्सीलेंस बढ़ा रहे हैं, आगे भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मैं असम के संदर्भ में कहना चाहूंगा और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा क्योंकि असम में यह एनआईडी बन रहा है और बढ़ रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसकी सीट कैपेसिटी और सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1609 hours

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much Madam Chair. This may seem to be a routine Bill but actually covers a vital set of issues. Actually, design plays a very important role in our country, perceived by its global neighbours and citizens and the fact is that while we have a lot happening in the design area, Indian designers are re-imagining today's products by evoking the spirit of our country's age-old traditions.

(1610/MMN/ASA)

Nonetheless, the fact is that we have to appreciate that in everything to do with the conceptualisation and communication of the essentials of our nation in the globalised world, design and arts play a vitally important role. What are we doing to understand and enhance our appreciation of design? How do we take it a step further so that the capacity to deliver design is pursued by our Government? In fact, everything we do, every single action, from the way we brush our teeth to the way we talk or we deliver a speech in Parliament, has two elements to it. There is the motive, that is the intention or purpose, and there is the execution which is the performance of the action. Now it is in the performance of the action that we see the design. Through the design we see what materials have been used, how these have been arranged, what method has been used to arrange them or combine them as one another. It is through the design of an action that you conduct the appropriateness of the action to its motive or purpose.

Whenever we see, hear, interact with a person or with a product, design heavily influences our perceptions and our ability to interact with it. And, on top of that, the synchronisation between product design and communication can increase the perceived value of a product or service in the eyes of a consumer. Indian design in turn influences how India is perceived across the world. Given that the world in the Twenty-first Century, is increasingly a world in which we are focussing on the importance of soft power, where we have to really win over the publics of the world, design is part of our crucial strength in soft power. So, any sound legislation for a design eco-system is crucial for the future of a modernising economy like India. This becomes especially relevant to India, given our young population and our competitive performance in the design sector. Now the Bill is obviously crucial in this.

We understand now the importance of what design is. What are we doing through this Bill to encourage the study and delivery of design? Now Indians have, for centuries, proven that given the right training and environment, we can produce works of arts in substance that are unmatched in design across the world. Consider jewellery design, where India is a world leader, for example. The bedazzling shapes and material combinations that our country's master jewellery workers constantly churn out is a testament to the significant demand and appreciation for our jewellery from the rest of the world. Same is with our robust textile industry.

Even the successive ISRO's Mars orbiter, Mangalyaan is linked to design. We all know and we boast about the fact that it was developed at a total cost lower than the cost of the Hollywood space movie, 'Gravity'. It is a great example of India's ability to embrace frugality with high technology design. But do we know that it owes a good part of this success to the modular design approach that was favoured by ISRO? So, design comes in, in all sorts of ways that perhaps, we have not taken into account in this debate.

But despite this rich history of design innovation, we are outpaced and outnumbered by other nations when we just look at things like Intellectual Property Registration Applications that are made every year. In fact, these patent trademarks of industrial designs provide a very, very good indication of design innovation. In 2017, India filed just 1,583 international patent applications as against 48,206 by Japan and 48,900 by China. I am quoting figures from the World Intellectual Property Organization. We fare even worse on the industrial design front. In 2017, India registered only 10,253 industrial designs as compared to China's 8,57,753 and 3,53,707 of the US. So, our total number of industrial designs is just 2.97 per cent of the US and staggeringly just 1.23 per cent of China. Where are we lagging?

We talk about 'Make in India', 'Start-up India' and 'Digital India'. While these are admirable in principle, we must associate them as an upskilling design principle. Otherwise, we will not be able to succeed in any of these, including manufacturing. There is more to manufacturing. It is just not building something. Manufacturing is production of physical goods but design involves the way in which these goods are produced, how the products are constructed and they go

all the way right up to service delivery as a whole. Conceived in such a manner, design is a vital part of our economic development and overall quality of life.

(1615/VR/RAJ)

Sir, this is why I think this whole institution, the National Institute of Design is so important to us and why it is, in a common sense understanding of the term, an institute of national importance.

But what exactly is an institution of national importance? The HRD Committee has observed that the term ‘institution of national importance’ has not been defined anywhere in this Bill. Despite 95 higher education institutions having earned this title until 29th October, this term has never been defined. No parameters have been set to evaluate an institution in terms of its academic excellence, faculty resources, infrastructure. Surely, Mr. Minister, there must be some criteria of both quality and numbers to merit such a term. I urge the Minister to insert this explanation into the Bill.

Our institutions of national importance keep swelling. They have gone from 40 in 2013 to 95 just six years later in 2019. So, if this Government keeps wanting to create these institutions, please define the term so we understand what it is we are creating. The organisations like UGC, MHRD, AICTE all use the term. There is still nothing in the legislation. It is reasonable to expect that a term that has such significant bearing on our higher education eco-system should be well-defined in our law books. The Committee has strongly recommended that the Government must do this and I would urge you to encourage the Minister to define this. In fact, the Committee actually called for the NID Bill 2014 to define it. But it was not paid heed to either in the 2018 or the 2019 versions of the Bill, neither of which by the way had been referred to the Standing Committee. So, there is a real fault her.

The failure to define the term INI means a failure to lay down the criterion and, therefore, without well-researched objective criteria, it will be a shame, if institutions unworthy of the title get it and institutions deserving of it don’t get it. That is what is happening.

The Committee has recommended in the past that mere nomenclature will lead to complacency. So, what we need is for institutions to understand what they need to do to become INIs and how that limited distinction confers certain obvious prestige and benefits. The truth is that the concept is not being diluted

by our present Government, which as I said has gone from 40 to 95, and every expert will tell you the status should be earned and not just conferred at random. We can pass a Bill but what has the institution done to earn the distinction in this Bill? On that we absolutely need some clarity from the Minister.

I do want to say, Madam, that we have an example, the IIITs, Indian Institutes of Information Technology. In addition to four IIITs, 20 were proposed to be established to be operated on a private public partnership with the investment being shared between Centre, States and private industry. Then, with all of this, they came up with a certain logical panel that would decide whether these institutes should get INI status and they said that they would look into strength, competence of faculty, outcomes, learning outcomes, etc. So, at least there is a process there. Here, we do not know where this is coming from.

As I mentioned, Madam, we are lagging behind on research and innovation. There is a recent World Bank analysis which says that our nation has fewer research and development professionals per million people than most of the countries. We just had 216 in 2015, whereas China had 1158, the US had 4279 and Japan had 5173 per million people. So, we have to make sure that the Indian workforce is equipped to do the necessary research and development. We need to make sure that we redesign curricula for the 21st Century economy. We need to create value added jobs in the manufacturing and design areas, give advanced training in various aspects of design, graphics, animation, computer design, software, architectural and industrial design. Film industry is also trying to catch up.

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Please conclude.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): It cuts across board, Madam. Two minutes more, I just will wrap up.

Inability to provide desirable jobs to graduating students is a consequence of what I have described. Students graduating out of NID, Ahmedabad, which is the first one to get the INI status, has experienced a major gap between the education they received and the jobs offered to them. Last year, the luxury car manufacturer Rolls-Royce came to NID to recruit. This year, they have not come back. The question everyone is asking, is NID finding out what went wrong, was the issue with students' performance, is our curriculum out of date, are we not upto the global standards? We should keep improving the quality of NID before

we just blindly give a terminology. I do want to stress that making our design graduates acceptable to world class recruiters is in the national interest. Let us promote quality as well.

(1620/SAN/VB)

Let us promote quality as well. Finally, let us bring design to the masses. We are still a relatively poor country. I am very proud to say that my constituency is where the birthplace of Raja Ravi Varma was. What did he do? His lithographs brought images of Gods and Goddesses to the masses, including to the people who in those days were excluded from worshipping in the temples. Just designs can actually transform a society. What is today’s lithograph by comparison? How do we ensure that this is done?

The National Investment and Manufacturing Zones were created and there were supposed to be NIDs in everyone of them. That mandate has not been fulfilled either. Therefore, the whole question of setting up the necessary digital labs has not been taken care of.

Madam, I am going to end finally with a concluding remark which is just this. The Bill is a missed opportunity. Merely conferring the status of institution of national importance without defining it, is too limited an objective for this Bill. The design sector needs a national policy on design which can then be incorporated into a legislation.

We need to develop India’s workforce, stress on research and development and digital ecosystem and ultimately move towards the future of our modernising economy. In addition to ‘Make in India’, we need to encourage ‘Design in India’. This is what will help build India in the 21st Century.

Thank you.

(ends)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, it is final that *… (Not recorded)*

HON. CHAIRPERSON (DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR): Nothing is going on record. This is not going on record.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member Shri Anubhav Mohanty.

1622 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Madam, in 1956, when India was embarking on a scientific and industrial journey, legendry product designers of that era, Charles and Ray Eames, were invited to India so that they could recommend a programme that can fuel India's growth in the manufacturing and industrial sector. Based on their interaction, they presented the India Report which recommended the formation of National Institute of Design and thus, NID came into existence in 1960. The date is important as design thinking at that point of time was still in infancy in the West. Thus, I salute the vision of the then Government that looked into the aspect of manufacturing from the lens of design and understood that aesthetic and usability of a product is equal to its utility.

Design thinking is a brilliant cognitive process and at the centre of it lays empathy. Design thinking says that every product should be seen from the eyes of the customer. One should employ empathy by placing himself in the shoes of the customer. The customer should find the product non-taxing on him and should be able to interact with it in a fluid manner. In this context, the example of Amazon is important to cite as Jeff Bezos once told his designers that buying anything should not be more than three steps. The beauty of Apple products lies in design thinking. Why did Apple phone first do away with the conventional keypad? It was the first one in the industry to have only one button. It seems that it is way back to design thinking. Steve Jobs did not know how to do computer coding. He only knew how to design consumer interaction with the product. Thus, his whole life was a quest to have better interaction with the product.

The National Institute of Design aspires to do the same. In our campuses, there might be so many Steve Jobs thinking how to design something big, the next big thing. We have to support them and this Bill does that precisely by giving all they need as our support.

By giving the 'institution of national importance' tag to the newly established NIDs as well, we are elevating the brand of NID and increasing their confidence. The students of NID are at the forefront of much cutting-edge work. From designing survival kits to designing the newly launched uniforms of the Marshals in the Rajya Sabha, NID students have been making us proud. I thank the Government for bringing the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019.

(1625/RBN/VB)

Before I conclude I just wanted to bring to your notice that Odisha is the land of art and culture and many more things. It is attracting many tourists to its land. One such place is known as Pipili, a small village in Puri known for its art. Recently it has got a special mention in one of the top most production houses of India, Yashraj Films, in *Sui Dhaga* movie. Those who have seen the movie *Sui Dhaga*, must be aware of this. …(*Interruptions*) This movie casts Varun Dhawan and Anushka Sharma has played out a tough task of designing movie's logo and they went all over the country to design the logo of the movie and artists from different parts of India put their efforts to get the work done within the given time.

Odisha's Pipili village has contributed its part with its stunning designs in Chandua, the town which is famous for designing beautiful Applique handicrafts. It is not only that. Odisha has got a space in the recently launched movie trailer. YRF decided to make an exclusive video on Pipili so that it will be able to reach out to millions of people across the globe.

While concluding, I would like to remind the House of the promise of NID to establish an Institute in Bhubaneswar that has been pending since 2009. My Chief Minister, hon. Shri Naveen Patnaik is passionate about bringing NID to Odisha and we have been raising the same demand for years. Odisha had been shortlisted for the same. But the final decision did not see my State make the cut. Odisha has got huge potential with regards to textile and stone crafting among the several other art forms. Thus, NID in the State shall propel the growth of these sectors in the State.

I would like to request the Minister to look into the above stated demand and bring the next NID to the State of Odisha. I expect the hon. Minister to kindly keep in mind our request and fulfil the demand of Odisha, which is pending for years, as an honour to Odisha and as an honour to art and culture which has been attracting the whole world. Thank you so much.

(ends)

1628 hours

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Madam, designating National Institutes of Design in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Assam and Haryana as institutions of national importance was a recommendation of the Standing Committee, which has now been incorporated in this Bill. The Amendment will bring about the change in order to be able to now grant degrees and diplomas. This did not exist before as these institutes were registered as Societies under the Societies Registration Act, 1860. Thus, it is a welcome amendment as was suggested by the Committee as it will encourage more students to take up design courses in various sectors and build skilled professionals in our country.

This Bill has gone through its due parliamentary procedure and has taken note of the recommendations from various stakeholders. It has provisions that are beneficial to all. We would like to emphasise that this procedure should be followed for all Bills that require special scrutiny in Parliament.

The Standing Committee had also recommended that the Chairperson of the Governing Council of the Institute should be an academician from the field of design only. Currently, the Chairperson may be a person who is an eminent academician, scientist or technologist or professional or industrialist to be nominated by the Visitor, that is the President of India. It is vital that the Government also brings about this amendment before this Bill becomes an Act.

This Bill will make design courses more inclusive and will bring forth a revolution in design in India. With the Institutes receiving the 'institutes of national importance' status, the rich culture and heritage of India along with modernisation will have a larger scope to flourish and create innovation.

(1630/SM/PC)

I would also like to point out the importance of designing a relevant curriculum framework in national design institutes. This will prepare the students for the dynamic modern industry of design. Being in sync with the industry, its ever-changing needs should be a crucial aspect of the course structure of these institutes.

Greater attention should be paid to the crafts industry including the tribal art forms. NID students should have the option to specialise in these areas. This will give a much-needed boost to MSMEs in the country.

Madam, before I conclude, I must address two crucial issues. First, we must realise that we have made a mockery of our institutions as we are declaring non-existing institutions as institutions of eminence like the yet-to be-constructed Jio University.

Secondly, it is my duty to highlight the current situation of India's greatest institute of national importance which is Viswa Bharati University in the State of West Bengal.

Kabiguru Rabindranath Tagore has said in his last letter to Mahatma Gandhi that "Viswa Bharati is like a vessel carrying the cargo of my life's best treasure and I hope it may claim special care from countrymen for its preservation."

It is with great dismay that I say that Rabindranath's greatest treasure, the Viswa Bharati University, is being compromised today with the deployment of CISF paramilitary forces on its premises due to the administration's unwillingness to respond to the needs of their own students.

I would urge the Government, especially the Home Ministry, to resist from deploying the paramilitary forces at the drop of a hat and preserve our crown jewels, preserve our children's lives, preserve the future of this great nation, preserve the dream that Tagore had. Thank you, Madam.

(ends)

1532 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Chairperson, Madam, thank you for the great opportunity to speak on the National Institute of Design (Amendment) Bill, 2019, which I support.

I welcome and congratulate our Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and the hon. Minister who has formulated the Bill to amend the National Institute of Design Bill, 2014, thereby seeking to declare four National Institutes of Design in the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Assam and Haryana as institutions of national importance at par with the National Institute of Design at Ahmedabad.

Currently, these four institutes are registered as societies under the Societies Registration Act, 1860 and they do not have the power to grant degrees or diplomas. On being declared institutions of national importance, the four institutions will be granted the power to grant degrees and diplomas.

Our hon. Minister of Industry and Commerce, Shri Piyush Goel Ji already assured, while passing this Bill in Rajya Sabha, that the autonomy of these four NIDs will not be affected even after the passage of the Bill.

Madam, my State, Tamil Nadu, is world famous for its culture which is related to design with its arts and sculptures. People of Tamil Nadu are very much talented in various design interventions. For example, we can say our former President Abdul Kalam Ji, present Chairman of ISRO, Shri Sivan, Google CEO, Shri Sundar Pichai are all from Tamil Nadu State. So, I request through you, Madam, the Hon. Minister to consider and take necessary action to establish a new NID centre in my State of Tamil Nadu.

Finally, I strongly believe that declaring NIDs as institutions of national importance in different geographical regions of the country will certainly help to produce highly skilled manpower in design which, in turn, will automatically create job opportunities, both direct and indirect, by providing sustainable designing interventions for crafts and handlooms, rural technology, small, medium and large-scale enterprises.

(1635/KDS/AK)

So, I support this Amendment Bill keeping in view all these good factors. Thank you very much.

(ends)

1635 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदया, सदन में आज राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा हो रही है। इस बिल के माध्यम से चार स्टेट्स के चार संस्थानों को इससे जोड़ा जाएगा। वहां के छात्र-छात्राओं को डिग्री और डिप्लोमा मिलेगा। उन्हें निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और उन्हें रोजगार के नए साधन मिलेंगे। मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं।

महोदया, वर्ष 1961 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध के लिए वर्ष 1956 की औद्योगिक पॉलिसी के संकल्प के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इस बिल के आने से हमारे चार स्टेट्स- आंध्र प्रदेश के अमरावती, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के जोरहाट और हरियाणा के कुरूक्षेत्र के नए केंद्रों को इस कानून के दायरे में लाकर उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा इन इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मिलेगा। उनके अंदर खुशी की लहर है, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स से आज से पहले जो बैचेज निकले थे, उनके बारे में भी यहां क्वेश्चन रेज किया गया था। उनको भी कैसे इसका फायदा मिले, निश्चित रूप से इसके बारे में भी सरकार के संज्ञान में मैं अपनी बात लाना चाहता हूं। मैं विश्वविद्यालय और कॉलेज में राजनीति में रहा हूं और मैंने बेरोजगारों के लिए रोजगार हेतु हमेशा आंदोलन किए हैं। मैं रोजगार को लेकर सदन में भी हमेशा अपनी बात रखता हूं।

महोदया, मैं माननीय मोदी जी की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि जबसे सरकार का गठन हुआ, उसके बाद एक से बढ़कर एक अच्छे बिल आए। हमें उम्मीद है कि बेरोजगारों और किसानों के लिए भविष्य में भी अच्छे बिल आएंगे। सबसे पहले धारा-370 और 35 ए जरूरी था। उसके बाद राम मंदिर का फैसला जरूरी था। कांग्रेस के लोग, विशेषकर श्री अधीर रंजन जी खुश हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में यह हो गया, वह हो गया। उसे छोड़िए, कितने स्टेट्स से कांग्रेस जाने वाली है, आप उसकी चिंता कीजिए। आपको ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि तीन, चार पार्टियां मिलकर, आप लोग वहां कुछ कर पाएं, लेकिन ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश आपके हाथ से कभी भी निकल सकते हैं। आपको इसकी चिंता करनी चाहिए।

महोदया, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलने से डिजाइन, शिक्षा सामाजिक तौर पर अधिक समावेशी होगी। इसके अलावा इससे कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। आज देश को इस बात की खुशी है कि आज जिन चार संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है, वे डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दे सकते थे, क्योंकि वे सोसायटी एक्ट के दायरे में थे। यह बिल पास होने के बाद इस क्षेत्र से जुड़े छात्रों को डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त होने का अधिकार मिलेगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधन बढ़ेंगे।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि जिस कांग्रेस ने गांव में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पिछले 70 सालों में गड्ढे खोदे, उसके विकास को अवरूद्ध किया, उन गड्ढों को भरकर विकास की नई बुलंद इमारत इस देश में खड़ी करेंगे। आज पता नहीं क्यों कांग्रेस के लोग खुश

हो रहे हैं? श्री अधीर रंजन जी सोच रहे होंगे कि दो दिन हमने हाउस में विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। आपकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। आपकी सरकार नहीं चलेगी। वहां भी आपसी खींचतान हो जाएगी।

सभापति महोदया (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार): कृपया बिल पर चर्चा करें।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): महोदया, वैसे तो मैं बिल पर बोल रहा था, लेकिन राजनीति पर आ गया। मैं वापस बिल पर आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऐसे बिल लाए और मैं प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत् रूप से भी आग्रह करूंगा कि हमारे सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जितने भी पद खाली हैं, उन सब पदों को भरा जाए।

(1640/MM/SPR)

ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण छात्र, जो हमारे गांव के अंतिम छोर पर बैठे हैं, उनको किस तरह से अच्छी शिक्षा मिले और कैसे आम आदमी दिल्ली और जयपुर में अपने बच्चे-बच्चियों को पढ़ा सके, इस दिशा में प्रधान मंत्री जी चिंतित हैं। पहली बार किसी ने चिंता की है कि गरीब, जो अंतिम छोर पर बैठा है, उसको अच्छा घर मिले, उसको अच्छी चिकित्सा मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले। आज से पहले यह किसी की सोच नहीं थी, तभी तो ये सारे के सारे विधेयक इस सरकार को लाने पड़ रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकारें नहीं ला पायीं।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह ऐसे नये-नये बिल लेकर आए, जिनसे आम आदमी, गरीब आदमी के हितों की रखवाली हो सके। धन्यवाद।

(इति)

1641 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदया, डिज़ाइनिंग और फैशनिंग की बात हो तो हम देखते हैं कि टॉप लेवल, वर्ल्ड लेवल की जगहों पर ग्रामीण कल्चर दिखाई देता है। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण कल्चर अगर किसी की डिज़ाइन में दिखता है, चाहे वह कपड़े की डिजाइन में हो, बिल्डिंग की डिजाइन में हो या कालोनी की डिजाइन में हो, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसको सरकार की तरफ से कुछ ऐसे इंसेंटिव मिले, जिससे उनकी हिम्मत बढ़े और हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा मिले। दूसरा, टॉप लेवल पर जाकर जब हम देखते हैं, यह लुटियंस जोन का इलाका है। जब यह जगह बनी तो इसके आर्किटेक्ट सर एडवर्ड लुटियंस थे। उन्होंने पूरी नई दिल्ली को डिजाइन किया, जिसे लुटियंस जोन कहते हैं। वह आर्किटेक्ट का नाम था। जब पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन को डिजाइन करने की बात आयी तो सर एडवर्ड लुटियंस ने कहा कि मेरे पास तो वर्क लोड है और उन्होंने अपने दोस्त को इसके लिए बुलाया। एक ऐसी दिल्ली की डिजाइन की है, लंदन, यूके से भी बेहतर डिजाइन की है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी जगह कहीं देखने को नहीं मिलती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो टेलेंट्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और वह बाहर जाने की बजाय, सरकार ऐसा कोई सिस्टम करे कि वह हमारे देश में रुक सकें और जो लोग बाहर जाकर, जैसे मुम्बई में एक आर्किटेक्ट बिजॉय जैन हैं। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को आईवीवाई लीग कहते हैं, उनमें वर्ल्ड की सात टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि हमारे देश की यूनिवर्सिटी की शुरूआत पांच सौ नंबर के बाद होती है। 501 पर अहमदाबाद की एक यूनिवर्सिटी आती है। बिजॉय जैन को हमारे देश की सरकार प्रमोट नहीं कर पाती है, तालमेल नहीं बैठा पाती है। वह ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और फिलाडेलफिया में लेक्चर देने जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, उन लोगों को अट्रैक्टिव पैकेज दें और जो हमारे देश की कालोनी और बिल्डिंग्स बढ़िया डिजाइन हो रही हैं, उनमें उनकी फीस और रेप्यूटेशन को ध्यान में रखकर अट्रैक्ट करें, जिससे वे यहीं डिजाइन कर सकें। आज जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, इसका बहुत बड़ा दायरा है। करीब 10-11 साल पहले मुम्बई में अम्बानी साहब ने अपने मकान का डिजाइन बनाने की बात की तो सर नॉर्मन फोस्टर हैं, अब तो वे लॉर्ड हैं, वे आर्किटेक्ट हैं, उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपना हवाई जहाज भेज रहा हूं, आप आ जाइए और मेरे मकान का डिजाइन कर दीजिए। उनकी ईगो को चोट लगी और उन्होंने कहा कि अम्बानी साहब, मैं अपना हवाई जहाज भेज देता हूं, आप आ जाइए और उनका ऑफर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर रोजर हैं, वह भी वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट हैं। इसमें इतना स्कोप है, जिसकी कोई थाह नहीं है। सरकार आज

जो बिल लेकर आयी है, हम इसका समर्थन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ चीजों का इसमें एडिशन किया जा सकता है।

(1645/SJN/UB)

आज हम लोग जहां पर बैठे हैं, वह राजधानी है और राजधानी के एनसीआर हिस्से में मेरठ भी आता है। संजीव बालियान जी यहां पर बैठे हैं। वह मुजफ्फरनगर से आते हैं। राजेन्द्र अग्रवाल जी मेरठ से आते हैं। गिरीश चन्द्र जी नगीना से आते हैं। अगर केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार आपस में तालमेल बैठाकर मेरठ में इस इंस्टीट्यूट को स्थापित कर दे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि इसको मेरठ में बना दिया जाए। बिजनौर के भी, नगीना के भी, बागपत के भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चों को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी तरक्की होगी। उनके सामने पूरे संसार में काम करने के लिए एक रास्ता खुलेगा।

(इति)

1645 hours

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Madam, today is the 70th Constitution Day. The Constitution is a success in India. We are all celebrating that success. We are moving a relatively significant Bill because we are declaring four National Institutes of Design as institutions of national importance.

Madam, over the last sixty years, Parliament has declared 134 institutions as institutions of national importance. We will add four more institutions this time. These 138 institutions should be the pride and jewel of India, not non-existing institutions which are declared as Institutes of Eminence. Madam, the establishment of National Institute of Design goes back to the Kamraj and Nehru period. It is fashionable to decry and criticise the Congress era but most of the institutions of science & technology and higher education were established in the Congress period.

The Government of India asked for recommendations on a training programme on design that would serve as an aid to the small industries. That would resist the present rapid deterioration of design and quality of consumer goods. The Government wanted to explore the problems related to design and to make recommendations for a training programme. A design specialist toured throughout India and carefully studied many centres of design, handicrafts and general manufacturers.

The National Institute of Design was set up to improve the design capability of India's small and medium enterprises. I would request the hon. Minister that we need to pay greater attention to the design of our crafts industry. We have a throbbing and thriving crafts industry. It has enormous employment potential and export potential but this will improve only if our designs improve. Over the last few years, we set up National Institutes of Fashion Technology and the Footwear Design and Development Centres, but the main crafts, the handicrafts and the handlooms remained unattended to from the point of view of design. I would request the hon. Minister to pay greater attention to crafts.

Let the students who enter NIDs have the option of specialisation in craft design because unless you are going to upgrade the traditional handicrafts and artisanal skills, you are not going to be able to expand employment opportunities and exports. So, I think the focus on craft is needed. Social innovation at the

grassroots level is very, very important. I think the NID which has done excellent work is well equipped to handle the challenges.

Design in this country is unique in its insight, in its quality and in the depth and width of its thinking. The famous phrase of the Gita refers to a man's right to work but never to the fruits. I wish the Government to explore the existing symbols of India.

I request the Government to come forward to set up a new National Institute of Design in my constituency, Kanyakumari, the tip of India to expand employment, to expand exports and deepen the roots of social innovation.

In 1954, Shri Kamraj was the Chief Minister of Tamil Nadu. He studied only till 6^{th} standard. In Kanyakumari, there were two mountains from where water could not pass. The man who studied till 6^{th} standard, Shri Kamraj, designed and constructed the Mathur Bridge to link those two mountains at the height of 120 ft. Even the engineers refused to construct that bridge because that was not possible.

While walking on this bridge, one will find that, on the one side, there is running water and, on the other side, people can walk.

(1650/SNT/GG)

All engineers told him that it was not possible. But the man who ruled Tamil Nadu for nine years, Shri K. Kamaraj, constructed the bridge. It is now called Mathur Thotti Palam. Now, people are coming from all over the world, engineers are coming from all over the world to see how a man has constructed this bridge.

So, we, as the people of Congress and also as Kamaraj's people, are always working hard. We want more help from the Government to develop Tamil Nadu as well as Kanyakumari.

Thank you very much.

(ends)

1650

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साथ उद्योग जगत की भागीदारी पूर्णतया आवश्यक है, क्योंकि अंतत: डिजाइनिंग उपभोक्ताओं के लिए ही होती है। संस्थानों में संगत क्षेत्र के संकाय में सुधार करने की आवश्यकता है। शैक्षिक जगत और विश्वविद्यालय के विचारों के साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों से सहायता, सहयोग तथा विचार भी प्राप्त किए जाते हैं। हमारे शिल्प उद्योग के डिजाइन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधान डिजाइनर के साथ ही, वेतनमान के उच्चतम निर्धारण के उद्देश्य से पंजीयक का पद भी प्रदान किया जाए। ओडिशा, नालंदा, बिहार और तमिलनाडु की कलाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

महोदया, आईआईटी, आईआईएमएस, आईआईएससी, आदि जैसे प्रतिष्ठा के राष्ट्रीय संस्थानों के लिए ही वित्त पोषण की जरूरत है। मैं बिहार राज्य में भी एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोलने की अनुमति की मांग करता हूँ।

उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में डिजाइन के बढ़ते महत्व को समझते हुए और उससे देश के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2007 में राष्ट्रीय डिजाइन नीति (एनडीपी) की स्वीकृति दी थी। डिजाइन संबंधी शिक्षा सामाजिक रूप से समावेशी बन सके और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण और शहरी स्वच्छता सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक अन्य क्षेत्रों में डिजाइन संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सके। इससे प्रतिभा कौशल और प्रशिक्षण के साथ राष्ट्र और विश्व को सेवा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय कौशल वाली श्रम शक्ति तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, रणनीतिक दूरदर्शिता और मानव केन्द्रित प्रक्रियाओं जैसी महत्वपूर्ण डिजाइन पहलों के माध्यम से हमारी धरती को बचाए रखने के लिए सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इसमें भी मदद मिलेगी।

महोदया, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस की तरह किए जाने से डिजाइन के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमबल तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण तकनीक, लघु, मंझोले एवं बड़े उद्यमों के लिए स्थायी डिजाइन संसाधन उपलब्ध कराते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही, इससे क्षमता, दक्षता एवं संस्थान निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को भी बल मिलेगा। धन्यवाद।

(इति)

1654 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you, Madam, for allowing me to speak. Actually, all the illustrious Members of this House have spelt out on this issue in such an elaborate manner, I think, nothing much could be added further. However, I would like to say that it is really a beautiful subject, which is called 'design'. If you see, the entire existence of the universe, of the human being, is based on design. The nature has been designed by the supreme being.

(1655/KN/RSG)

It is said that Vishwakarma has created the world. He was a great designer. In each and every aspect of our life, everything is designed. Our birth is designed. Our way of life is designed. We cannot go beyond the design.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Financial Memorandum. It is estimated that there would be an expenditure of approximately Rs. 434 crore for the establishment of these institutes. Accordingly, a sum of Rs. 434 crore was sanctioned during the Twelfth Plan; non-recurring expenditure is estimated at Rs. 336.72 crore and recurring expenditure is estimated at Rs. 97.28 crore. My question is this.

आपको चार इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं और आप इन चार इंस्टीट्यूट्स में 474 करोड़ रुपये बांट दीजिएगा तो एक-एक इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपये के आस-पास मिलेगा। यह क्या हाथी के पेट में इलायची के दाने के बराबर नहीं होता है। एक-एक इंस्टीट्यूट के लिए 100 करोड़ रुपये में क्या होगा? कल पेपर में देखते थे कि कहीं हिन्दुस्तान के किसी राज्य में सरकार बदलने के लिए … *(Not recorded)* जब हिन्दुस्तान के एमएलए के भाव … *(Not recorded)* लेकर आप एक-एक इंस्टीट्यूट को दान करते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। इससे मैं सहमत नहीं हूं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. काकोली घोष दस्तीदार) : गणेश जी, बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें और ज्यादा राशि दी जानी चाहिए, और ज्यादा राशि का इंतजाम कर देना चाहिए। अगर आप सही ढंग से इन इंस्टीट्यूट्स को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको किस पर छोड़ रहे हैं? After the institutes become fully operational and start generating revenues through fees and consultancy income, dependence on Government grants for recurring expenditure will gradually reduce.

आपको यह लग रहा है कि इंस्टीट्यूट बनाते ही यह कमाना शुरू कर देगा, फीस लाएगा, कंसल्टेंसी इनकम करने लगेगा। इनका सरकार पर निर्भर करना कम हो जाएगा, लेकिन इसके मद्देनज़र अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स को राशि प्रदान करने में थोड़ी कंजूसी करेंगे तो आपका जो मकसद है, यह मकसद पूरा होने की सम्भावना नहीं है। It has an enormous potential for generating jobs and employment. That is why my suggestion is that you should infuse more funds into these institutes. मेरे बंगाल के एक साथी ने कहा कि बंगाल में एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मैं

इससे सहमत हूँ, क्योंकि हमारे इतने बड़े देश में यह नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन, इसका अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनको और विस्तृत रूप से सारे राज्यों को देना चाहिए।

1658 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सारे राज्यों में न हो, कोई ग्रुप, ईस्टर्न इंडिया में कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जोरहाट में दिया है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया इतना बड़ा ज़ोन है, उसमें किसी जगह यह डिजाइन इंस्टीट्यूट नहीं है। एक आपने आंध्र प्रदेश में दिया है। ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक नहीं, दो दीजिए, सौ दीजिए, लेकिन ईस्टर्न इंडिया इतना बड़ा ज़ोन है। आपके बगल में ओडिशा है। हमारे मंत्री जी ओडिशा के हैं। झारखंड है, बिहार है, बंगाल है। कुल मिलाकर वहां एक डिजाइन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र शशि थरूर जी ने भी यह बात उठाई कि नेशनल इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंस के तौर से, एमिनेंस के तौर से इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका पैरामीटर, आज तक स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हम इन इंस्टीट्यूट्स को और ज्यादा मौका दे रहे हैं, क्योंकि यह पहले सोसायटी एक्ट में था, अभी इससे आगे निकल कर डिग्री और डिप्लोमा देने का मौका मिलेगा। मैं इस विषय पर जानना चाहता हूं, आप जानते हैं कि जियो इंस्टीट्यूट में इनका कोई एक्सीलेंस नहीं था। कभी कोई स्टूडेंट भर्ती नहीं हुआ था, लेकिन जियो इंस्टीट्यूट को कैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस और एमिनेंस बना दिया गया, यह बड़ा सवाल है। जियो इंस्टीट्यूट के साथ क्या संबंध है कि यह जियो इंस्टीट्यूट, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना दिया गया।

(1700/CS/PS)

ये दो-तीन मुद्दे हैं। मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री को इसमें शामिल कीजिए। अगर इंडस्ट्री के साथ आपके इंस्टीट्यूट का तालमेल अच्छा होगा, तो आपको लाभ होगा और यह हिन्दुस्तान के लिए और अच्छा होगा। जब इंडस्ट्री इसमें शामिल हो जाएगी, तो इसे according to the needs of the consumers आगे जाने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं कि डिजाइन के ऊपर वर्ष 2007 में यह ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी। आज वर्ष 2019 आ गया है, इसलिए इस ड्राफ्ट पॉलिसी में थोड़ा ओवरहॉलिंग करना जरूरी है। इसमें और थोड़ा नई-नई चीजें शामिल करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में जो 'क्रैप्स' है, हर राज्य में अलग-अलग 'क्रैप्स' है, मैं इसका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। इसको कस्टमाइज करके, हर रीजन की, हर स्टेट की जो 'क्रैप्स' है, इस डिजाइन इंस्टीट्यूट के दौरान उसको आप और प्रमोट कीजिए। इसके साथ ही साथ विदेश में भी हमारी बहुत सारी एम्बेसीज हैं। विदेश में हमारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर देश में हमारी जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी को इसमें शामिल कीजिए, जो हमारे इस 'क्रैप्स', डिजाइन को दुनिया भर में प्रमोट कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसे पास करा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। आप सुनिए।

1702 बजे

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश): महोदय, मैं धन्यवादी हूँ कि बहुत सारे मेंबर्स ने इस पर चर्चा की है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माइक अपने आप चालू हो जाता है। माननीय सदस्य, आप चिंता मत कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI SOM PRAKASH: Hon. Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members who have participated in the discussion. As many as 21 hon. Members have participated in the discussion and have given their valuable suggestions, which I really appreciate.

Sir, the National Design Policy was passed by the Government in the year 2007. With a view to impart quality education in design, it was decided to establish four more National Institutes of Design on the pattern of NID-Ahmedabad. The Ahmedabad Institute has already been declared as the institute of national importance. It is only by way of legislation that the Parliament can declare any institute for scientific or technical education as an institute of national importance, as per the requirement under Entry 64 of the Union List of the Seventh Schedule of the Constitution of India.

महोदय, जो हमने चार नए इंस्टीट्यूट्स सैटअप किए हैं, उनको नेशनल इम्पॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड वही होगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के लिए सभी ने कहा है, उधर से भी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है। उसी पैटर्न पर ये चार इंस्टीट्यूट सैटअप किए जा रहे हैं, उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इसलिए डिक्लेयर किया जा रहा है कि इन सारे इंस्टीट्यूट्स की इम्पॉर्टेंस हो। जो एन्ट्री 64 ऑफ दी यूनियन लिस्ट है, सेवंथ शेड्यूल ऑफ दी कांस्टीट्यूशन, उसके मुताबिक ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस बन सकें।

महोदय, हमने चार इंस्टीट्यूट्स सैटअप किए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, मध्य प्रदेश, भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, आन्ध्र प्रदेश, अमरावती में है। इसका प्रथम बैच वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, कुरूक्षेत्र में है। वर्ष 2016-17 में इसकी फर्स्ट क्लास शुरू की गई थी। चौथा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, असम, जोरहाट में है, जो वर्ष 2019-20 में शुरू किया गया था।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I need one clarification. What was the criteria under which it decides ...(*Interruptions*)

(1705/RU/RV)

माननीय अध्यक्ष: आप रिप्लाई के बाद प्रश्न पूछ लेना। रिप्लाई के बाद मैं आपको मौका दे दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सोम प्रकाश: सर, चारों इंस्टीट्यूट्स शुरू कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो इंस्टीट्यूट है, वहां के फर्स्ट बैच के विद्यार्थी इस साल दिसम्बर में ग्रैजुएट होंगे और उन्हें उसकी डिग्री दी जाएगी। उन्हें हम डिग्री प्रदान कर सकें, इसलिए यह बिल लाया गया है। Only by declaring this Institute as an Institute of National Importance, we can do it. At present, these are established under the Societies Registration Act, 1860 and these Institutes have no power to grant degrees. जो चार इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके लिए एक कॉमन सेन्ट्रल एग्जाम होता है। उसी के थ्रू इसमें एडमिशन देते हैं। इसके लिए एक नेशनल लेवल पर सेलेक्शन टेस्ट होता है और डिज़ाइन एण्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जो अहमदाबाद का इंस्टीट्यूट है, उसी की तरह का सेम सिलेबस इन सारे इंस्टीट्यूट्स का है।

सर, शशि थरूर जी जो बात कर रहे थे कि इनका स्टैण्डर्ड क्या होगा तो इनका वही स्टैण्डर्ड होगा जो गुजरात के इंस्टीट्यूट का है। इनका वही सिलेबस है, वही सेलेक्शन का ढंग है। इसलिए ये इंस्टीट्यूट्स उसके बराबर के होंगे।

The Government wants to make this Institute a hub of exports and outsourcing of design and for preparation of platform for creative design and development. At present, new NIDs have been set up and ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये स्टार्ट हो चुके हैं। The ones in Andhra Pradesh and Haryana are working in transit camps. सर, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स वर्ष 2015-16 और 2016-17 में शुरू किए गए थे। The NID at Bhopal and NID at Jorhat have commenced from the academic session 2019-20.

सर, ये जो चारों इंस्टीट्यूट्स शुरू किए जा रहे हैं, इनका मकसद यही है कि इनमें एक स्टैण्डर्ड एजुकेशन दी जाए और डिजाइन में पात्र का नाम हो। 'मेड एण्ड डिजाइन इन इंडिया' का जो कॉन्सेप्ट है, उसे लेकर हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट्स बनें।

मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चारों इंस्टीट्यूट्स से संबंधित जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसे पास करें ताकि हम इनके विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान कर सकें।

(इति)

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): सर, जवाब दिया गया, पर जवाब पूर्ण नहीं है।...(व्यवधान)

Sir, when I asked you what makes an Institute of National Importance, you said that 'if it is like the one in Ahmedabad'. But by what yardstick do you decide it? How do you measure the criteria of excellence that merits the term 'Institute of National Importance'? Your Government since 2014 has raised the number of Institutes of National Importance from 40 to 95. On what basis has it been

done? Can this Parliament just by giving the words confer quality, can it improve the faculty, can it guarantee world class curriculum, can it produce learning outcomes? What we need is some measurable standards. The Committee on HRD way back in 2014 also called for measurable criteria and yardsticks on the basis of which the term 'Institute of National Importance' can be earned. We are just passing a Bill and conferring this title but how are they earning it? What are they doing specifically, what yardsticks are they attaining to be able to earn this title? That is a very important issue to which you have not replied. You cannot say that an institute is of national importance because it is of national importance. Fine, but how do we measure that? This is my question, Mr. Minister.

श्री सोम प्रकाश: सर, नेशनल डिजाइन पॉलिसी वर्ष 2007 में पास की गई थी, जब काँग्रेस की सरकार थी। उन्होंने यह कहा था कि अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट की तरह चार इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए। उसी के मुताबिक ये इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट का जो स्टैण्डर्ड है, उसी के स्टैण्डर्ड के ये इंस्टीट्यूट्स होंगे। इनमें वही क्वालिटी होगी।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014, राज्य सभा द्वारा यथापारित, का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

(1710/MY/KKD)

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

खंड 5

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 6

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 2 से 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 2 and 3. But I am moving my amendments No. 4 and 5.

I beg to move:

‘Page 3, *for* lines 7 and 8,--

Substitute “(4) Any institute may establish an Institute Campus in the States with a population over two crores as per last census within a span of five years”. (4)

‘Page 3, line 9,--

after “Ahmedabad”

insert “in the State of Gujarat”.’ (5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

माननीय अध्यक्ष: प्रो.सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 6. But I am moving amendment No. 7.

I beg to move:

‘Page 3, line 29,--

after “Madhya Pradesh,”

insert “West Bengal,”.’ (7)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 32

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving amendment No. 8.

I beg to move:

'Page 5, line 7

after "Madhya Pradesh,"

insert "West Bengal,".' (8)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 32 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving amendment No. 9. But I am moving amendment No.10.

I beg to move:

'Page 5, line 17,--

after "Madhya Pradesh,"

insert "West Bengal,".' (10)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 33 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving amendment No. 11 on which I will seek a division.

I beg to move:

'Page 5, *after* line 34, *insert,--*

"2A.	West Bengal	The National Institute of Design, Dum Dum, a society registered under the Societies Registration Act, 1860	National Institute of Design, West Bengal."'

(11)

(1715/CP/RCP)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 11 के पश्चात,

2क. पश्चिम बंगाल	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, दमदम	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, पश्चिम बंगाल।"

अंत: स्थापित करें। (11)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I demand Division. It will be proved who is for West Bengal and who is anti-West Bengal.

माननीय अध्यक्ष : लॉबीज़ क्लियर कर दी जाएं।

लॉबीज़ क्लियर हो गई हैं।

महासचिव।

(1720/NK/SMN)

ANNOUNCMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान मैं स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के संचालन से संबंधित बिन्दुओं की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगी। मतदान आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ही ग्रहण करना चाहिए और उसी स्थान से बटन को प्रेस करना होगा। जब माननीय अध्यक्ष 'अब मतदान' बोलेंगे तो मैं मतदान का बटन एक्टिवेट करूंगी जिसके पश्चात् माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर डिस्पले बोर्डों के ऊपर लाल बल्ब जलेंगे और इसके साथ-साथ गौंग की ध्वनि भी सुनाई देगी । मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गौंग की ध्वनि के पश्चात् ही दोनों बटन एक साथ दबाएंगे। मैं इसको पुन: दोहराना चाहूंगी कि केवल गौंग की ध्वनि के बाद ही दोनों बटन दबाएं। प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा बटन और सीट की डेस्क के सबसे ऊपर लगे तीन बटनों में से कोई एक बटन – 'हां' के लिए हरा रंग है, 'नो' के लिए लाल रंग है और मतदान में भाग न लेने के लिए पीला रंग है। गौंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक और प्लाजमा डिस्पले के ऊपर लगे लाल रंग के बल्बों के बुझने तक, जिसकी अवधि दस सेंकड है, दोनों बटन को प्रेस किए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि पहली गौंग साउंड सुनने के पहले ही वह बटन दबा देंगे। गौंग साउंड सुनने के बाद ही बटन दबाएं और दूसरी गौंग साउंड सुनने तक दोनों बटन एक साथ प्रेस करके रखें। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों तरफ स्थापित डिस्पले बोर्डों पर अपना मत देख सकते हैं। मत अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो पर्ची के माध्यम से बाद में मतदान की मांग कर सकते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 11 के पश्चात,

2क. पश्चिम बंगाल	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, दमदम	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, पश्चिम बंगाल।"

अंत: स्थापित करें।

(11)

<u>लोक सभा में मत विभाजन हुआ:</u>

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 23

नहीं: 93

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन-उपस्थित नहीं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I beg to move:

Page 5, *after* line 45, *insert*, -

"6. Kerala	The National Institute of Design, Kerala, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860.	National Institute of Design, Kerala.".

(17)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडीकुन्नील सुरेश द्वारा खंड 34 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1725/SK/MMN)

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 8 और 9 ली जाती है।

1726 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019 (No.14 of 2019) promulgated by the President on 18 September, 2019."

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to prohibit the production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of electronic cigarettes in the interest of public health to protect the people from harm and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 सितम्बर, 2019 को प्रख्यापित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।"

> "कि जनता की अपहानि से सुरक्षा करने के लिए जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने के लिए उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

1727 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, to start with, I do not have any fundamental objection to the contents of the legislative documents. But the way, the Government has been bringing the legislation after the promulgation of Ordinance certainly draws criticism and opposition from our end because the Government has been playing footsie with the Ordinance route.

I would like to remind the hon. Minister of what the former Speaker, Mavlankar said on 17th July in the year 1954: "The issue of an Ordinance is undemocratic and cannot be justified except in cases of extreme urgency or emergency." The Session was about to be commenced and it was known to you when you went for the promulgation. When you went for the promulgation of the Ordinance, at that time you were aware that the Parliament Session would immediately commence in the month of November but your Government has brought the Ordinance in the month of September.

It is ridiculous to note that you are talking of e-cigarettes in the Ordinance while your Minister of State for Health has claimed in Parliament that only three per cent of the population is aware of this, that is, that an estimated 0.02 per cent of the population uses the e-cigarettes. That means, insofar as e-cigarette is concerned, only three per cent of the Indian population is aware of the subject, 'e-cigarette', and out of these three per cent population, only 0.02 per cent uses the e-cigarettes.

(1730/VR/MK)

However, you thought it prudent to invoke the Ordinance part which intrigues me about what had triggered the Ordinance is really undefined and unclear in your legislation.

Sir, in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, it has been stated that:

> "In view of the above recommendations and in the overall interest of public health as envisaged under article 47 of the Constitution, it was expedient that the e-cigarettes and the like devices should be prohibited."

I am not questioning the intention of the Government in so far as prohibition of e-cigarette is concerned.

You have also cited Article 47. What does Article 47 elaborate? It says:

> "The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties."

So, you thought it wise that e-cigarette smoking is also one of the ingredients of public health which I think may have driven you for invocation of the Ordinance route.

I would also like to cite an example so far as malnutrition is concerned. About 93 per cent of our children are suffering from malnutrition. It has been stated by no fewer than your Minister, Shrimati Irani ji.

In so far as Global Hunger Index is concerned, in the year 2014, India was ranked 65 in the world. But now we have been relegated to 102. That means half of the population hiked from the pangs of hunger have been again relegated to the ambit of hunger.

So, when you are citing Article 47 of the Constitution, I would suggest that you should also consider the other aspects which have been infecting the entire country.

E-cigarettes are electronic devices that heat a substance, with or without nicotine and flavours to create an aerosol for inhalation which a user can inhale like the action of smoking.

In your argument, you yourself stated here that it is not yet established that e-cigarettes are safer than traditional cigarettes and the harmful effects of e-cigarette use are now emerging across the world. Available scientific evidence indicate that use of e-cigarettes is hazardous for an active as well as passive smoker. E-cigarettes solutions and emissions are known to contain harmful chemicals which are hazardous and some of which are considered to be toxicant.

While arguing this, you yourself have failed to assert your argument as to when you are going to prohibit the e-cigarettes. You said that it is not yet established. It means that there is a scope for further scientific research which could establish views contrary to yours as it has been admitted by you in your statement.

Sir, When the conventional cigarettes are available in each and every corner of our country and are being sold with impunity, then why is the Government only concentrating on e-cigarettes? I am not finding fault with you for identifying e-cigarettes because I think that they are also injurious to health. But here it appears to me that you are bringing in a targeted legislation only to prohibit e-cigarette.

(1735/SAN/IND)

Why are conventional and traditional cigarettes being sold with impunity? These are some sort of contradictions which are befuddling me.

In our country, where we are now, in so far as cigarette smoking or tobacco consumption is concerned, according to a Nationally Representative Case - Control Study of Smoking and Death in India, 'tobacco will be responsible for one in five of all male deaths and one in twenty of all female deaths in the country by 2010. This means approximately one million Indians would die annually from smoking by 2010.' According to the Indian Heart Association, India accounts for 83 per cent of the world's heart disease burden, despite having less than 20 per cent of the world's population. The IHA has identified reduction in smoking as a significant target of cardiovascular health prevention efforts. That is where lies my contention. When we are losing one million Indians every year only due to consumption of tobacco, you are not trying anything to stem the rot out of tobacco consumption. On the other hand, you are going to prohibit e-cigarettes. Why is this kind of attitude being nursed by this Government? Could you say that this is a level playing field?

I am referring to the Supreme Court of India's judgement delivered on 02 November, 2001 in Murli S. Deora versus Union of India where the Supreme Court observed:

> "Tobacco is universally regarded as one of the major public health hazards and is responsible directly or indirectly for an estimated eight lakh deaths annually in the country. It has also been found that treatment of tobacco related diseases and the loss of productivity caused therein cost the country almost Rs. 13,500 crore annually, which more than offsets all the benefits accruing in the form of revenue and employment generated by tobacco industry."

These are the appalling episodes emerging across the country in so far tobacco is concerned. It has already assumed a menacing proportion, but you prefer to be reticent on the consumption of tobacco. On the other hand, you are deploying your entire legislative muscle only to prohibit consumption of e- cigarette. Here lies my question.

I am not in favour either of e- cigarette or conventional cigarette, but your attitude should be robust and comprehensive while dealing with smoking, which, you think, is injurious to health.

Every third adult in rural areas and every fifth adult in urban areas of India uses tobacco in some form or the other. It has been revealed in the Global Adult Tobacco Survey-2 released by the Ministry of Health and Family Welfare. The survey revealed that 28.6 per cent of adults aged 15 and above in India currently use tobacco in some form. Among the adults, 24.9 per cent are daily tobacco-users and 3.7 per cent are occasional users. The most commonly used tobacco product in India is khaini, a tobacco-lime mixture, that is used by every ninth adult. The next most commonly used tobacco product is beedi, smoked by 7.7 per cent of adult Indians. Gutkha, a tobacco, lime and areca nut mixture, ranks third at 6.8 per cent consumption and betel quid with tobacco ranks fourth at 5.8 per cent.

(1740/RBN/RAJ)

That means the prevalence of tobacco use among men is 42.4 per cent, while among women it is 14.2 per cent. It is according to the Survey. The Survey Report II shows that every tenth adult in India smokes tobacco. The Survey also shows that second hand smoke is gradually becoming a major cause of concern in India. More than one-third, that means 35 per cent of non-smokers, were exposed to second hand smoke at home in urban areas and 25 per cent of non-smokers in rural areas.

Tobacco use is the leading cause of premature non-communicable diseases, and associated mortality and morbidity. It is a growing public health challenge. While many people are aware that tobacco use increases the risk of cancer, there are alarming gaps in knowledge of the cardiovascular risk of tobacco use. According to World Health Organisation, more than half of adult Indians did not know that smoking can cause stroke. Tobacco epidemic is a major public health challenge in India and flavoured smokeless tobacco users in

India is very high. Concerted strong political commitment and targeted action over the last decade have contributed to commendable achievement in pushing back the tobacco epidemic. We must certainly agree that something has been done. But it has not yielded the desired results.

Survey II was carried out in many States of India and in the two Union Territories of Chandigarh and Puducherry from August 2016 to February 2017. The analysis is based on the 74,000 complete interviews. So, this is the menacing proportion of the problem that we are observing insofar as tobacco consumption is concerned. So, we should not differentiate between the conventional cigarette and the e-cigarette. We should completely stop all kinds of tobacco consumption that are prevalent in our country.

You said that scientists, doctors, etc. are recommending ban on e-cigarettes. But there is some confusion still over the e-cigarette issue. You are certainly aware of it. However, I would like to draw your attention to it. In the year 2015, the global market for e-cigarette industry was estimated to be 10 billion US dollars. I know that India is a signatory to the WHO Framework Convention on Tobacco Control which was introduced in response to the globalisation of tobacco epidemic. In 2014, the WHO Framework Convention on Tobacco Control appealed to all its signatories to consider prohibiting or regulating the use of e-cigarettes in their respective countries. This was suggested due to emerging evidence of the negative health of e-cigarettes which could result in lung cancer.

Again in the Global Audit Survey Report 2016-17, it was found that approximately three per cent of the adults in India were aware of e-cigarettes and there were 0.02 per cent e-cigarette users. In August 2018, the Ministry of Health and Family Welfare issued an advisory to all the States recommending that they should not approve any new e-cigarettes and restrict the use of advertisement for the existing e-cigarettes. Based on the advisory, 16 States, including Delhi, Maharashtra, Uttar Pradesh, have since banned e-cigarettes. In May 2019, the Indian Council of Medical Research recommended complete prohibition of e-cigarettes. That means, as per your advisory, most of the States have started banning or prohibiting e-cigarettes. When that is the case, why did you feel it necessary to promulgate an Ordinance in this regard? The Ordinance-addicted Government could not convey a positive message to the common

people. It appears that this Government is Ordinance-addicted Government. Without any rhyme or reason or without any lucid argument, you are unnecessarily promulgating Ordinances. I think this was not at all necessary.

(1745/SM/VB)

You are using canon to kill a little mosquito. This is simply to get myself enriched by you. As per the Public Health England and the United States National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, e-cigarettes are substantially less harmful than traditional cigarettes. You are a doctor. You shall be the best person to deal with this subject. I am a layman.

The argument of Public Health England and the United States National Academies of Sciences, Engineering and Medicine is that e-cigarettes are substantially less harmful than traditional cigarettes. They lack the tar and carbon monoxide of traditional cigarettes because combustion, which produces significant toxic substances, does not occur. Therefore, substituting e-cigarettes for traditional cigarettes may reduce the smokers' exposure to numerous toxic substances and carcinogens.

A clinical trial in the United Kingdom found that people who used e-cigarettes to quit smoking were twice as likely to succeed as people who used other nicotine replacement products such as patches or gum. I think patches and gum have not been prohibited by you. However, there is still insufficient evidence to quantify the health risks and long-term effects of e-cigarettes. So, these are the issues on which many people like me are confused. So, I am raising this before you for getting myself more enlightened.

At present 30 countries including Brazil, Mexico and Thailand have banned the manufacture, trade and advertisement of e-cigarettes. In addition to this, Singapore and Cambodia have explicitly banned the possession of e-cigarettes. On the other hand, over 98 countries such as the United Kingdom, Canada and France have decided against banning e-cigarettes. These countries are also advanced and developed countries. They have decided against banning e-cigarettes and they were recommended by the WHO to take the following measures. What are those following measures -- (i) prevent the initiation of e-cigarettes by non-smokers, and youth, (ii) minimise the potential health risks to e-cigarettes users and non-users from exposure, (iii) prevent unproven health

claims about e-cigarettes, and (iv) protect tobacco control activities from all commercial interests related to e-cigarettes.

To implement these measures, countries have used a range of regulatory mechanisms such as classifying e-cigarettes as tobacco products, prohibiting sale to minors, prohibiting use in public places, and regulating the amount of nicotine in e-cigarettes. For instance, the European Union's Tobacco Products Directive requires the manufacturers of e-cigarettes to restrict the nicotine concentration at 20 milligrams.

Further, health warnings for e-cigarettes advising consumers that they contain nicotine should not be used by non-smokers, are mandatory. Similarly, in the United Kingdom, packaging must include a list of ingredients contained in the product, information on the product's nicotine content, and information on adverse effects, addictiveness and toxicity. In the United States, several States such as New York, Michigan and Massachusetts have prohibited flavoured e-cigarettes.

That means, 80 countries still are not agreeing on prohibition of e-cigarettes. They are resorting to various kind of regulations. That is why, my question is, why are you rushing for banning without resorting to other measure also? Those countries are also the developed countries.

This is simply to know this from a competent person like you. Why those countries still are not prohibiting e-cigarettes and, on the other hand, we are prohibiting e-cigarettes, while the percentage of e-cigarettes smokers in India is very much insignificant?

My request to the hon. Minister is that you should elaborate all these issues, so far as e-cigarettes and conventional and traditional cigarettes are concerned because both the issues are to be thoroughly discussed as it is related not only to our health but also to the health of our future generation. We need that special care should be afforded to our generation. All of us know that smoking is injurious to health.

(1750/AK/PC)

However, smoking is continuing.

Now, e-cigarette has come into the market as a new entrant, but traditional cigarettes are flourishing everywhere. I hail from West Bengal where in the District of Murshidabad most of the people are addicted to smoking, which is

recognised as one of the largest manufacturers of *beedi*. So, I know about the ill-effects of smoking, and I think that the Government should be more careful and serious in dealing with this menacing and appalling situation due to tobacco-consumption in our country. Thank you, Sir.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : सभा की सहमति हो तो सभा का समय विधेयक समाप्ति तक बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : हां महोदय, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : श्री वरुण गांधी जी।

1751 hours

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, I rise to support the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019.

E-cigarettes or ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) are electronic devices that heat a substance, which contains nicotine to create vapour for inhalation. The previous speaker said that the quantities of nicotine in this are not very well decided. The Harvard T. H. Chan School of Public Health states that treated nicotine in an e-cigarette is 1.6 times that of a conventional combustible cigarette. There is a very strong industrial and commercial lobby, which has sought to propel the myth and lie that e-cigarettes are far less harmful than combustible tobacco cigarettes. The fact remains that treated nicotine, which is present in these devices, is a carcinogen that is a tumour-promoter; it is responsible for neuro-degeneration; and it is responsible for anxiety, behavioural and breathing disorders. So, I am unsure as to how that claim of being less dangerous can be made.

1752 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

We must look at three factors when we are looking at the net public health effect of e-cigarettes. One, their effect on youth; two, their effect on adult cessation of combustible tobacco products; and three, their inherent toxicity. The science behind it is what I want to get to. One of the greatest problems with the science behind e-cigarettes is that it is highly questionable at best in a certain way. Nearly 94 per cent of global e-cigarette devices come from China. These products have no nicotine-product standardization. It is very important that we note this point.

We have absolutely no accountable chemical composition of any of these devices including Juul Labs nor Philip Morris, none of them. The unregulated sale that happens in India *via* the internet is 99.3 per cent, which means that we are dealing with a product of which we know not the quality, not the purity, not the provenance, and which sells purely through the grey market on the internet. There is no licensing of the companies that sell e-cigarettes in India, and these are unmonitored online sales.

What is the impact of e-cigarettes on youth? It is potentially disastrous. Due to a lie that these cigarettes are safe, they will become a giant gateway drug for children as young as 12 to use. The average age of a conventional combustible tobacco smoker in America is 38 years old. The average age of an e-cigarette user is 17 years old. This is a very frightening thing with 70 per cent of e-cigarette users saying that they were 15 years old when they first tried an e-cigarette. At these ages, the long-term consequences include brain development getting stalled. The New England Journal of Medicine, which is a very famous and recognised journal, has shown that of those who smoked e-cigarettes rather than those who did not smoke, the percentage of learning disorders was up by 28 per cent. There is absolutely no evidence to show that e-cigarette cause a cessation of smoking normal cigarettes.

(1755/SPR/KDS)

According to the Philip Morris Industry-backed Study, smoking in America has risen every single year, year on year, since 1954. Right. E-cigarettes, which were introduced in America since 2004, have also increased year on year. So, if both have increased year on year, then, how is the advent of one leading to the demolition of the other?

The Study by the Royal College of Physicians in London shows that 70 per cent of e-cigarette smokers smoke conventional cigarette simultaneously, which means that it really makes very little difference in terms of replacing one.

The Indian Council of Medical Research has put out a very succinct and very important study, where they have said that the introduction of an unproven product in the context of a declining trend in tobacco consumption and multiple measures being taken to achieve tobacco control would be highly questionable. What is the reason for the timing of this ban? I heard hon. Members who spoke before me say, what is the reason for the timing of the ban? I tell you the reason. The reason for the timing of this ban is that prevention is better than cure. Yes, we have 120 million smokers in India. That is true. The point is, do we want to introduce another gateway drug for children? Sir, JUUL Labs and Philip Morris, which have not entered India – Dr. *Sahib* knows this very well - they have earmarked Rs.250 crore, and Rs.550 crore from 2020 to 2022 to establish India as their greatest frontier market for e-cigarette distribution. So, this is the time to get into this market and stop this incoming menace.

Yes, it is true that 16 States have banned this product and I read the strong circular of the Central Drug Standards Control Organisation calling for a blanket ban. I do not want to get into other aspects of the Bill like imprisonment, etc.

What are the other approaches of other countries towards e-cigarettes? The WHO Framework for Tobacco invited in 2014 all its signatories to ban and restrict e-cigarettes. Singapore, Brazil, Philippines, etc. have banned e-cigarettes. Over 30 countries like Mexico and Thailand have practically banned; with 98 other countries, putting a strong regulatory approach, restricting their supply, advertising, etc.

I want to get into one or two countries that have specifically done. The UK has opposed the ban on e-cigarette but I read the science on this. I am not just used to speaking like this. Sir, the Royal College of Physicians Report says, and I want to quote this, “nicotine is not in itself a hazardous drug, it is unlikely that nicotine contributes to the morbidity caused by smoking.” This is an extremely questionable scientific premise. This is saying that nicotine is not bad for you. I want to know whether the tobacco lobby had paid for this or not. It is crazy to me. I want to know that if countries believe that nicotine consumption is not a risk, should we allow our Indian populace to be a guinea pig in this experiment till they determine whether nicotine is not bad for you?

Sir, in the same Harvard T.H. Chan School of Public Health Report, it states, the lab experiments have shown – this is very important – that e-cigarettes contain twice the amount of heavy metal and chemicals namely diacetyl than normal cigarettes and double the number of harmful effluents. This is the most significant work that is done in this field. The same report by the UK College of Royal Physicians says that e-cigarettes help people who cannot quit. But if you read the full study, it contradicts itself because in the first paragraph, it says this; and in the fourth paragraph, the same study states that out of 900,000 people who attempted to stop smoking and switched to an e-cigarette, 780,000 returned to full-scale conventional smoking in a year. Really it is not any kind of conventional substitute.

(1800/UB/MM)

Sir, I want to make a psychological argument. Almost everybody in the world knows about the dangers of smoking more or less. My question is, just by the introduction of ‘x’ product which has ‘x’ amount of marketing and questionable science, will it lead to a person, who has taken a heavy-duty psychological decision to be a proper smoker, to give it up? I mean this is something I would really like to ask the House.

The hon. Member who spoke before me mentioned that the European Union has issued a Tobacco Products Directive, it is true, which states that maximum nicotine concentrations should be there. But what he omitted to state is that not a single country in the world has been able to put in place a maximum nicotine concentration. You can put on paper whatever you like but if it is not there in the actual device, what is the use of it? No country in the world has been able to put a maximum nicotine concentration, none. My contention is that nobody has been able to put this in earnest and as 90 per cent of e-cigarettes sales are via the internet and semi-hidden platforms, how will you enforce it even if you put it into law?

The second thing is that, in Philippines where they banned it, why did they ban it? It was because a mysterious lung injury killed 47 people. In America, in the State of Virginia, which is the largest tobacco grower in America, you also know that, people went to one court and said that across all the fifty States, over 2000 people who have smoked e-cigarettes for two years under the age of 21 have been seriously afflicted by a mysterious illness which Columbia Presbyterian had not been able to ascertain as a hospital.

Sir, my question is that, in a country like India, medical data is neither centrally procured, nor processed, nor documented, nor analysed. In a country like America, if they could not tell you about the dangers of a mysterious illness, in a country like India, these deaths will not and cannot be traced. Can we expose our populous to the same illness?

The Health and Family Welfare Ministry of Brazil has put a health study which shows that tobacco substitution products act as a catalyst for people under the age of 15 to be part of a social trend and be introduced to smoking. Incidentally, we should take Brazil seriously because they are the first and the only country in the world to achieve the target reduction of 30 per cent in smoking

according to the Global Action Plan of WHO. That is the only country that has achieved it. They have banned tobacco substitution products.

Sir, at an age when young children are not prone to thinking about the ramifications of every action, should we be introducing this to them? In a very dangerous trend, what are the four products that Juul Labs is launching in India next year if the Government had not got this Bill into the House? They were going to launch Banana flavour, strawberry flavour, melon flavour and apple flavour of e-cigarettes. I want to ask this House, is this not an absolute way of introducing young children to cigarettes? Is a grown man going to smoke a strawberry-flavoured cigarette or an apple-flavoured cigarette? Certainly, nobody that I know. So, we cannot have a product where it seems that the product is fun and child friendly. For God's sake, we are talking about a treated tobacco product, a nicotine product and a chemical product here or which we do not even know what chemical composition it is.

Sir, I have a suggestion to give to the hon. Minister and the Government. This is a highly positive step. The hon. Member who spoke before me about the tobacco smokers being very many in number. Yes, they are very many. He also suggested that we should ban tobacco. I do not want to disagree, in principle. There are 130 million farmers today who are involved in tobacco farming. Are you going to put them on streets by banning tobacco? Let us speak about the things which we can do reasonably.

(1805/SNT/SJN)

Let us not just speak in the air here. We are going to take 130 million farmers and strip them of all their assets and all their technical wherewithal. I find it extraordinary. But what can we do? For three years, the taxes on tobacco have not been adjusted for inflation. Right now, they are 53 per cent. My suggestion is if we can take them to the WHO standard of 75 per cent, that, I think, would be a step in the right direction.

Sir, smoking *bidis,* as we know, is something that has not been touched for a long time because they are seen to be a simple pleasure available to the poor.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Hon. Member, you are suggesting that the hon. Health Minister would suggest to the Commerce Minister to increase the tax slab on tobacco.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Sir, this is not my duty to suggest. I can only put forth a suggestion as a Lok Sabha MP. But I can say this that when we are talking about *bidis*, smoking *bidis* cost the Indian exchequer in ill health Rs.80,000 crore a year. It costs Rs.80,000 crore a year but the revenue gained is Rs.417 crore a year. Now, there are those who will say that the tax should not be increased, that is one of the simple pleasures to the poor. However, my question to the House is this. By keeping very low taxes on *bidis*, are we helping or killing the poor? This is the question I want to ask the House.

The reason I have focused on taxation is because, I think, to ban tobacco, frankly, is something that is not possible. So, I do not want to speak in the air. I will just lastly say we have a national goal of having a healthy population and a productive workforce. When I look at this Ordinance, I am proud that we have taken a step towards looking at the direct cause and externalities which are crushing this national goal.

Let us not introduce yet another addiction and hazardous habit into our youth without having the need for it. We may not know the chemical poison it carries but we can definitely, clearly see into the future as to the social poison that it brings with it.

Thank you, Sir.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: As an intelligent Member of Parliament, I hope, all of you will agree, the hon. Member not only supported the Bill, but also has given a very good suggestion relating to taxation on tobacco. I think, the Government will take it forward so that we will discourage the tobacco taking practice that is also growing in our country.

Thank you, hon. Member.

1808 hours

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Chairperson Sir!

I am here to speak on the Prohibition of Electronic Cigarettes Bill, 2019. The House adjourned in the month of August, and the Ordinance was brought in the month of September. Then, the Session has been started in the month of November. So, what is the urgency in bringing the Ordinance? What sort of things can be brought in an Ordinance? An Ordinance is something to deal with situations where an emergency arises requiring urgent action.

So, I would like to know whether consuming of less than 0.02 per cent of e-cigarettes is very important national urgency that should have been brought in by an Ordinance, when the Session is going to start in November. There are so many urgencies/emergencies which are to be addressed. For example, eradication of poverty, empowerment of women, safety of children, health, and providing social equality and justice. These are all other important issues which are much more important than bringing an Ordinance to ban e-cigarettes.

I have a strong doubt that bringing an Ordinance of this sort would have been lobbied by the tobacco/cigarette lobby. So, a big, strong doubt arises out of this.

What is e-cigarette? E-cigarette is a battery-operated device that emits doses of vaporized nicotine to inhale. So, it is basically inhaling tobacco without the smoke.

(1810/RSG/GG)

E-cigarette has good potential for cutting down cigarettes. Who says this? It is the British Medical Journal published in February, 2018 which has urged the doctors practising in Britain to suggest that 95 per cent of e-cigarettes are less harmful than the conventional smoking methods. Many countries which have banned smoking e-cigarettes, as

we have done now, have revoked the ban saying the potential health hazards are much less compared to the conventional smoking methods. But Dr. Harsh Vardhan should be knowing, as I know since I am too a doctor, that both e-cigarettes and cigarettes have hazardous effects on health such as COPD, emphysema, chronic bronchitis, lung cancer, and heart diseases. Does it anywhere say that e-cigarettes are less harmful than conventional smoking? Both are hazardous. Why do you target only one of them?

In the Statement of Objects and Reasons, you have given a clear statement that the International Association for Study of Lung Cancer does not recommend use of e-cigarettes. I would like to know whether the International Association for Study of Lung Cancer recommend the usage of regular cigarettes or regular tobacco-related products? No, it does not. So, why do we cut and paste scientific evidences which suit the Government of the day? Should we not put out all scientific data together to substantiate our theory? When we put out data, based on scientific evidence, we should put it out in its full context.

We have a COTPA, the Cigarette and Other Tobacco Products Act, for regulating branding and sales of cigarettes. Before bringing a hundred per cent blanket ban on e-cigarettes, why did we not try the route of regulating e-cigarettes? The friend from BJP had said that there are Chinese products which are harmful without any scientific data but we could have put in a regulatory Act just like COTPA before bringing out a total ban on e-cigarettes.

The quality of life we seek for every citizen and the ethos and the morals that we would like to set for our students, the younger generation of India, to cultivate would be judged by the sincerity of this Government. The sincerity of the Government and that the Government means business can be proven by banning all tobacco products, if they are really concerned.

An hon. Member said that there are many farmers who had taken up tobacco farming. We can give them an alternative though it cannot be brought in a day like the Government has brought in an Ordinance. India is a country of young generation. Your Government has such a strong majority. It was not at all necessary to bring in an Ordinance. We should look at moving forward, banning tobacco products totally, including tobacco cigarettes and everything related to them.

My doubt about the ban arises because of this. In our State of Tamil Nadu, we have a ban on gutkha-related products. There was a CBI raid on *… (Not recorded)* when all the sale of gutkha was being done despite the ban.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): The name of the Minister should not go on record.

… (Not recorded)

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, I am just concluding.

We have the respected Health Minister here. I have a high regard for him. We would like to take the gutkha scam case to its logical conclusion and bring justice. This Government's motto of *sabka saath, sabka vikas* is very doubtful. Seeing the recent developments in politics, we would also like to add that we would not want to see it as *sabka … (Not recorded)*. I would like to take this to a conclusive end. So, along with the ban on e-cigarettes, our Party also suggests a ban on all tobacco-related products if you want to prove that you are not just *sabka … (Not recorded)*.

Thank you.

(ends)

1814 hours

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak in this august House.

The promulgation of the prohibition of Electronic Cigarette Ordinance, 2019 proHibits the production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, and advertisement of e-cigarettes in India.

(1815/PS/KN)

Any person who contravenes this provision will be punishable with imprisonment of up to one year or a fine of one lakh rupees or both. For any subsequent offence, the person will be punishable with an imprisonment of up to three years, along with a fine of up to five lakh rupees. Additionally, storage of e-cigarettes will be punishable with an imprisonment of up to six months or a fine of Rs. 50,000 or both. Once the Ordinance comes into force, the owners of existing stocks of e-cigarettes will have to declare and deposit these stocks at the nearest office of an Authorized Officer. Such an Authorised Officer may be a police officer or any other officer as notified by the Central or the State Governments. The Ordinance defines electronic cigarettes, that is e-cigarettes as battery-operated devices that heat a substance, which may or may not contain nicotine, to create vapour for inhalation. These e-cigarettes can also contain different flavours such as menthol, mango, watermelon and also cucumber. Unlike traditional cigarettes, e-cigarettes do not contain tobacco and therefore, are not regulated under the Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2003.

Now, I come to the key features of this Bill. The Ordinance defines electronic cigarettes, that is, e-cigarettes as electronic devices that heat a substance, natural or artificial, to create aerosol for inhalation. These e-cigarettes may contain nicotine and flavours and also include all forms of electronic nicotine delivery systems, heat-not-burn products, e-hookahs and other similar devices.

The second feature is banning of e-cigarettes. The Ordinance prohibits the production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution and advertisement of e-cigarettes in India. Any person who contravenes these provisions will also be punishable with imprisonment of up to one year or a fine of up to one lakh rupees or both. For any subsequent offence, the person will be punishable with imprisonment of up to three years along with a fine of up to five lakh rupees.

Now, the third feature is storage of e-cigarettes. No person is allowed to use any place for the storage of any stock of e-cigarettes. If a person stores any stock of

e-cigarettes, he will be punishable with an imprisonment of up to six months or a fine of up to Rs. 50,000 or both.

The fourth and the last feature is powers of authorised officers. If an Authorised Officer believes that any provision of the Ordinance has been contravened, he may search for any place where trade, production, storage, or advertising of e-cigarettes is being undertaken. The authorised officer can seize any record or property connected to e-cigarettes found during the search.

In this context, it is pertinent to mention that prior to this announcement, 16 States and one Union Territory had already banned e-cigarettes. In August 2018, the Ministry of Health and Family Welfare had released an advisory to all the States requiring them not to approve any new e-cigarettes and restrict the sale and advertisements of e-cigarettes. Further, there are also international regulations for e-cigarettes. India is a signatory to the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) which was developed in response to the globalisation of the tobacco epidemic. In 2014, the WHO FCTC invited all its signatories to consider prohibiting or regulating e-cigarettes in their countries. This was suggested due to emerging evidence on the negative health impact of these products which could result in lung cancer, cardiovascular diseases, and other illnesses associated with smoking. Since then, several countries such as Brazil, Mexico, Singapore and Thailand have banned the production, manufacture and sale of e-cigarettes. Recently, the States of New York and Michigan in the USA banned the sale of flavoured e-cigarettes, whereas, in UK, the manufacture and sale of e-cigarettes has been allowed based on certain conditions. Further, the advertisement and promotion and the levels of nicotine in e-cigarettes is also regulated. This ban will also help youngsters.

The notion that e-cigarettes may help smokers quit regular cigarettes benefitting their long-term health is a myth. Rather, young people who have never smoked traditional cigarettes, are taking up e-cigarettes which are available in over 1500 flavours, including bubble gum and candy floss.

(1820/RU/CS)

In a survey of US youths aged between 12 and 17 years, 81 per cent of e-cigarette users reported that the first product they ever used was flavoured and that they use e-cigarettes because they come in flavours which they like. According to the US Centre for Disease Control and Prevention (CDC), over 3.6 million children in the US use e-cigarettes with a jump of 78 per cent (from 11.7 per cent to 20.8 per cent) of US high school students reporting e-cigarette use from 2017 to 2018. In the UK,

1.6 per cent of those aged between 11 years and 18 years use e-cigarettes more than once a week compared to 0.5 per cent in 2015. Due to the highly addictive nature of nicotine, there is also a risk that young e-cigarette users might switch to using traditional cigarettes. Indeed, some health care professionals refer to e-cigarettes as a 'gateway drug'.

A recent US study was published in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. It had investigated the effect of chronic e-cigarette use on markers of lung injury in the airways of vapers. Proteases linked to tissue damage were increased in both smokers and vapers as compared with non-smokers.

Once the ban comes into force, consumption, production, manufacturing, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement of e-cigarettes would become illegal in India also.

E-cigarettes were promoted as a way to get people out of their smoking habits but reports have shown that many people are not using it as a weaning mechanism but are rather addicted to it. The decision to ban e-cigarettes is aimed at protecting the youth, the section that is most vulnerable to the health hazards of e-cigarettes. The ban will help to protect population, especially the youth and children, from the risk of addiction through e-cigarettes.

So, I support the Bill.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Thank you, hon. Member.

I would just like to suggest one thing to the hon. Minister. The honourable lady Member is the first speaker to speak on the Bill. More women today are going into smoking. Has any survey been done by our Government or any agency on the issue as smoking is being taken up in a very big way by the women folk of our country? And that is quite alarming. So also are school going children because e-cigarettes look just like pen drive. That gets carried in the school bags. So, it is necessary, as the woman Member just now spoke, that the Government should make all efforts in creating awareness about it. The hon. Member spoke in favour of the Bill.

Now, I call Shri Margani Bharat to speak….(*Interruptions*)

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): सर, अगर सभी लोग इसके फेवर में हैं तो इसे पास कर दिया जाए। …(व्यवधान)

1823 hours

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): I thank you, hon. Chairman, for giving me the opportunity to speak on the Bill. Sir, we have been trying hard to ban tobacco and its related products for decades, be it through higher taxes or warning which has now been mandated to print at 80 per cent of the pack. But the results are not what we expected or what it ought to have been. So, in a lighter vein, I say that instead of printing a warning as ‘cigarette smoking is injurious to health’, you may print the warning as ‘cigarette contains fat’ and you may see the effect the very next year. You will find that cigarette sales have dropped down to zero.

Why I am saying this is because, as per WHO, almost ten lakh people are getting killed using cigarettes and related products. The Government should take stringent steps in controlling cigarette-based products.

The Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) was celebrated as a solution to smoking problems as it was considered as a safe non-tobacco alternative. Also, it is a very less risky smoking option and has attracted not only youth but also those who want to quit smoking. However, the researchers, the health practitioners, the Government and the whole world has realised the ill effects for quite sometime now.

(1825/KKD/RV)

Sir, the proposal to ban them through this Bill is welcoming, and I support this Bill not only on behalf of YSR Congress Party, but also, being a youth, on behalf of youth of this country.

My first point is relating to Clause 3(d), which defines what constitutes ‘electronic cigarette.’ A lengthy definition has been given saying: “the electronic device that heats a substance with metals like lead, chromium, nickel, chemicals like formaldehyde, with or without

nicotine and flavours….e-hookah and the like devices, by whatever name called and whatever shape, size or form…"

Sir, my point is that they are saying: 'e-hookahs and the like devices.' But nowhere, they have mentioned banning of conventional hookahs, which can be seen in every household, particularly, in North India, which is being used right from a young boy to 90-year old. The point that I am talking about is about the e-hookahs also. I wanted to know: why is the Bill silent on this? Why are they not banning such hookahs? So, I would request the hon. Minister to clarify this point.

Sir, my second point is relating to Clause 6 of the Bill, which gives an officer the authority to enter into any premises without any warrant and carrying search and seizure. It further says that he can enter into any premises if he reasonably believes that any provision of this Act has been contravened. But how do they define or quantify the phrase 'reasonably believes'. I may have a grudge on anybody, for instance; and taking advantage of this provision, I will enter into the premises of a person on whom I have a grudge, plant something and take action against him. So, how is it justified, Sir?

I would suggest for the consideration of the hon. Minister that let the authority concerned get warrant for search and seizure. Otherwise, it may be misused thoroughly. These days, it is happening everywhere in the country.

My next point is this. There is no doubt that the Government is going to ban e-cigarettes. But it does not mean that henceforth, these e-cigarettes would not be available. They will be available through dubious means. We have banned the foreign cigarettes, but still they are available in India. So, the same thing may happen with e-cigarettes if we do not implement it with sincerity, commitment and great spirit. If we show the kind of commitment and breadth on banning tobacco, *khaini, zarda, ghutka,* pan masala and cigarette that are responsible, as per WHO Report, for killing more than 10 lakh people in the country, I

have no hesitation in saying that banning of e-cigarettes will also smoke away.

Therefore, I feel that having a legislation in the Statute Book does not serve the whole purpose. All we need is the commitment and dedication to implement this objective. Otherwise, it will become one more dead letter.

Sir, the Government is saying that seven deaths have occurred in the US due to use of e-cigarettes. The New York State has banned the e-cigarettes in all forms. But it is not just New York, even San Francisco, Brazil, Australia and more than 20 other countries from South America, Middle-East and South-East Asia have banned e-cigarettes. Punjab and Delhi have also banned it. But as per my knowledge, they are available openly in plenty everywhere in the nook and corner of the cities.

I agree that banning of e-cigarette is a good move. But what about the innumerable deaths being caused by cigarettes? So, why do the Government not completely ban tobacco and related products? They cannot do this because the lobby is very strong and can prevail over the Ministers and the Government of the day. So, I would suggest for the consideration of the hon. Minister to ban tobacco, which is a basic ingredient to cigarette and related products.

(1830/RCP/MY)

You may be surprised that how a Member from Andhra Pradesh, which is one of the leading States in production of tobacco, is batting for banning of tobacco. I am conscious of what I am saying. Tobacco is to be banned lock, stock and barrel. But, at the same time, tobacco farmers, be it in Andhra Pradesh or in Karnataka or in any other State, have to be protected.

With your permission, let me come to the issue relating to tobacco. There is no doubt that 50 per cent of the tobacco grown in the country comes from our Prakasam district alone in Andhra Pradesh. The variety

grown here is Flue Cured Virginia which is commonly known as Virginia or Cigarette tobacco. The Government of India has been earning thousands of crores of rupees every year in the form of foreign exchange by exporting FCV tobacco. In 2013-14, the Government of India earned around Rs. 6,060 crore. In 2014-15, the Government of India earned Rs. 5,200 crore. In 2017-18, the country exported around Rs. 5,539 crore worth tobacco. The countries which import our FCV tobacco are Panama, UAE, Saudi Arabia, Libya, Sudan, South Africa, Indonesia, Israel, Afghanistan, etc. This is one part where we have a flourishing market. If you look at employment that the tobacco sector generates, it stands at 36 million. It means, it is a golden goose to earn the foreign exchange as we are one of the top three exporters of tobacco in the whole world.

Now, look at the other side of the coin. I would like to explain the pathetic position of tobacco farmers in India. There is an extreme pressure on the farmers from the Tobacco Board and the Government of India to give up tobacco farming. The ground reality is that they cannot shun it overnight because they have invested lakhs of rupees on each barn. Construction of one barn costs around Rs. 10 lakh which a tobacco farmer takes from moneylenders and financial institutions. In spite of this, they are willing to give up and all they are asking is for giving some compensation. The Government is also proactive in giving compensation but there are some more debts to be cleared by the Government. Especially in my State, there are thousands of farmers who still have to get payments from the Government of India. I would request the hon. Minister to look into this particular aspect seriously. I suggest for consideration of the hon. Ministers of Health, Commerce and Agriculture that if a farmer has two barrens, we can convince him to grow only in one barren. For the remaining one barren, I wish to submit that a suitable compensation be paid by ensuring that he switches to other crop or other alterative farming. Compensation can be given by the

Tobacco Board which has in its kitty about Rs. 400 crore to Rs. 500 crore collected through cess, taxes and profits.

Secondly, the whole world knows that ITC for many decades has been enjoying the lion's share in tobacco profits. So, I would request that ITC should also be involved in this and it should share some burden of the Tobacco Board. Also, since ITC has Agro Products Division, it can guide tobacco farmers for producing agro products which it can buy from them. So, through this, we can rein in tobacco in the country.

The YSR Congress Party would further request the Healthy Ministry to undertake a mass awareness drive regarding e-cigarettes and to make provisions against the use of ENDS as well.

With this observation and hoping that the Government will take a suitable action particularly with regard to tobacco farmers, I wholeheartedly support this Bill.

Thank you so much, Sir.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Mr. Bharat always comes up with good suggestions. He hails from a State which is a tobacco growing State. Yet, he has said, hon. Minister, that he is in favour of banning tobacco. But he has come out with certain suggestions saying very clearly that it is the foreign exchange that India earns because of export of our tobacco of high quality.

(1835/SMN/CP)

The suggestions which he is making are very apt. I think the Government will consider ways to discourage use of tobacco by our fellow citizens. That should be the crux of the issue. He supports the Bill. At the same time, he has given certain suggestions. This is in the right spirit of this House.

At the same time, the farmers' interest also needs to be protected and an alternative engagement should be provided to them.

1836 बजे

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर प्रतिबंध के लिए सदन में जो विधेयक लाया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। कोई भी नशा हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से वह कहीं न कहीं हानिकारक है। कुछ साथी बाहर इस पर चर्चा कर रहे थे। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक नहीं जानते कि ई सिगरेट क्या है, वह कैसी होती है? शायद दो-चार पर्सेंट लोग इसे जानते होंगे। हमने भी सुना है कि यह ऐसी सिगरेट है, जिसको पीने से बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। लोगों का कहना है कि बीड़ी-सिगरेट से साल में करोड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन ई सिगरेट से कोई नहीं मरता है। वह कैसी महंगी सिगरेट है और कौन सी वह सिगरेट है, जिस पर हमारी सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है। हमें जहां तक अनुमान है कि ई सिगरेट अगर देखने में अच्छी है, पीने में अच्छी है, तो कहीं न कहीं वह बहुत हानिकारक होगी। जब हम लोग राजनीति में आए थे, तो एक बहुत बड़े रणनीतिकार ने बताया था कि अगर किसी से अच्छे ढंग से दुश्मनी साधनी हो, तो उसको हेरोइन पीना सिखा दो। हेरोइन एक नशा है। उन लोगों ने कहा कि हेरोइन पिलाना सिखा दो। हेरोइन एक ऐसा नशा है…(व्यवधान)

माननीय सभापति : हीरोइन नहीं हेरोइन।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, हेरोइन एक ऐसा नशा है कि जिनको एक बार उसका नशा लग गया, उनका घर तो बर्बाद होगा ही, उनका परिवार, दौलत सब खत्म हो जाएगी। देश का तो इसके साथ-साथ नुकसान होगा ही। हमको लगता है कि ई सिगरेट वैसी ही सिगरेट है। जब पीने में इसका स्वाद इतना अच्छा है और इतनी महंगी सिगरेट है कि गांव के गरीब किसानों ने उसे आज तक देखा नहीं है, तो कहीं न कहीं से वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यह देश हित और स्वास्थ्य हित में कतई नहीं है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम समझते हैं कि देश की जनता के हित में यह निर्णय लिया है।

सरकार कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन लोकतंत्र की परिपाटी बहुत पहले से चली आ रही है कि सत्ता पक्षा कितना ही अच्छा काम क्यों न करे, विपक्ष का काम है विरोध करना। सरकार कितना ही अच्छा काम करेगी, लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना है। देश की जनता जानती है कि सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। सरकार ने सही समय पर इस पर प्रतिबंध लगाया है।

महोदय, इसके साथ-साथ हम कहना चाहेंगे कि देश में धूम्रपान एकदम निषेध करिए। सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़ी भी हानिकारक है, तम्बाकू भी हानिकारक है, जिससे साल में करोड़ों लोग मरते हैं। ई सिगरेट के साथ-साथ बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू

सब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(1840/NK/MMN)

अगर राजस्व सृजन की दृष्टिकोण से देखते तो प्रतिबंध नहीं लगाते। किसी भी जनप्रतिनिधि या सरकार का यह दायित्व होता है कि वह कोई भी कार्य आर्थिक सृजन के लिए न करे, देश हित और राज्य हित में करे। आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कर दी। इसी तरह से तम्बाकू, सिगरेट और बीड़ी जितनी भी चीजें हैं, मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाए कि कोई इसे न बेचे, न भंडारण करे, न आयात-निर्यात करे और उस पर कड़ा कानून बने। जब लोगों के बीच कानून का भय नहीं होगा तब सदन या सरकार कितना भी कानून बनाए, यह रुकने वाला नहीं है इसलिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए।

महोदय, शराब पर भी प्रतिबंध लगे। शराब से भी करोड़ों लोग मरते हैं। बिहार में हमारी सरकार ने शराब बंद कर दी। इसमें भी यह प्रस्ताव लाया जाए कि शराब, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू सभी पर प्रतिबंध लगे। सरकार का यह दायित्व है कि आर्थिक सृजन न देखते हुए जनता के हित और देश हित में प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम इस विधेयक के पक्ष में बोलते हुए इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

(इति)

1841 hours

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Sir, this Bill, the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019, specifically looks to ban the use, marketing and production of electronic cigarettes. Electronic cigarettes do have hazardous effects on individual's health whilst if we also look at the fact that there are other smoking tobacco products that cause the same or even, if not, more harm to an individual's body. Therefore, it is imperative that we think why such product has seen an outright ban whereas we have solid and effective data on the effects of consumption of tobacco, smoking and various other such products that have adverse effect on human health.

In India, we are aware that India spends about 1.2 per cent of its GDP on tobacco related illnesses which cost around 27.93 billion dollars. That exceeds over Rs.1 lakh crore. I wish to highlight the fact here that today we are looking at a ban on electronic cigarettes. Is it only because of the adverse effect of consuming or inhaling the smoke from electronic cigarettes? Or, is it, to a certain extent, to provide a protection cover to the cigarette lobbies across the world that bring in their products and sell in this country? Regarding electronic cigarettes, there has been no data so far when you compare it with smoking of cigarettes and consumption of tobacco. There has been no solid data so far about confirmed and adverse effect of the consumption of electronic cigarettes. Although I am of the view that it is harmful but at the same time, we know that the effect of smoking traditional cigarettes, which have various tar and other chemicals that go into the human body and remain buried in the lungs, causes cancer. There is widely available data across the world that this is leading to grave loss to the exchequer of various countries across the world, including our own, as I have just pointed out. India has recorded about 2,60,000 adult smokers. Also, at the same time, I would like to point out मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर में लोगों के लिए मैं प्रधान मंत्री राहत कोष को पत्र लिखता हूं, जिन्हें धूम्रपान और स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ है, उनको प्रधान मंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद दिलाने का काम करते हैं।

(1845/VR/SK)

Sir, I would like to point out the fact that when a person burns a cigarette, he inhales not just the tobacco and the nicotine that he gets from it but also the tar which is the main cause of illnesses that happen to him. Therefore, this Bill begs the question, why just electronic cigarettes are being banned and why not the cigarettes altogether? Now, the simple answer, to a certain extent, seems that the Government is protecting the cigarette lobby, the cigarette producers of the country and also of the world, who see India as a huge market to push their products.

Electronic cigarette, on the other hand, although is injurious to health, can also be looked upon within the same ambit. It is a fact that in India a large number of farmers depend on tobacco farming and it is the second largest employment generation sector in the farming community, which I think is a welcome thing. If one looks to ban the production of cigarettes altogether, that would have adverse effects on our farmers. That is something that the Government needs to think about.

But, at the same time, one can argue with the same rhetoric that production of electronic cigarettes or use or sale of electronic cigarettes within our country would also generate employment, would also create jobs and if we tax it correctly, just like we tax tobacco cigarettes, it can also generate the right amount of revenue for the Government.

On the other hand, the question that can be raised is, why not ban everything altogether, why not ban tobacco, why not ban tobacco products, why not ban *supari* and why not ban *surti* that causes tremendous health hazards to our citizens and also causes a lot of money to our exchequer? The simple answer to that, which comes to my mind is, of course, it affects our exchequer because it generates a lot of money through sale and taxation on such products. A lot of farmers depend on production of tobacco and its byproducts for their livelihood. But, at the same time, should this argument not also apply to e-cigarettes?

The other point that I would like to make is regarding Article 19 (1) (g) of the Constitution of India where the Right to Freedom is given. The Article guarantees to protect practice of any profession, any occupation, trade or business. Are we not at this point being partial to give protection to a particular

product that causes harm to human body whereas for electronic cigarettes we say that it is injurious to public health and in lieu of that we are banning it? But, on the other hand, a similar product that has more disastrous effects on the human body is being allowed to be traded. Therefore, within our Constitution the right that has been preserved for doing trade is being challenged by such a law where you are getting biased towards one product.

So, this is very clear that the Government is trying to help and benefit certain lobbies which are looking to secure their market, which are looking to ensure that they occupy the entire market and no other product or competition should enter there. This is very sad and I think the Government should answer this question and provide reasoning as to why they have not banned the consumption and usage of tobacco cigarettes, *gutka, surti* and everything of that sort.

Sir, one hon. Member has rightly pointed out that there are various other products that are injurious to health such as drinking alcohol. It should also fall within its ambit. If one product is being treated in such a way, why not the others?

(1850/SAN/MK)

That is the question that ought to be answered over here. Now, I would like to conclude my speech by saying that though we support this Bill, at the same point, it should also extend to other products that are harmful and injurious to human health.

At the same time, I would like to point out here that सबसे ज्यादा लोग, जिनको इससे कष्ट होता है, जिनको इससे उत्पन्न बीमारियों को झेलना पड़ता हैं, वे गरीब तबके के लोग हैं। खैनी, सुरती, सिगरेट, बीड़ी और तम्बाकू से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं जिनको उन्हें झेलना पड़ता है। इस से निपटने के लिए हमें इन सब चीजों के ऊपर एक कानून बनाने की जरूरत है। किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट करके, किसी व्यक्ति-विशेष या किसी विशेष मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा कानून न लेकर आएं, जिससे कहीं न कहीं अधिकारों का हनन और अपने संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन हो।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Mr. Ritesh Pandey has given a new dimension to the whole discussion today. I think, he has given a lot of scope to the Minister to explain.

1851 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am thankful that the House is sitting so long at the desire of the hon. Speaker who wants to make up for the time lost yesterday. It is a good initiative.

HON. CHAIRPERSON: You have supported it.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I have supported extension of the time because he is trying to complete the Business of the House which is a good thing.

Let me make it clear at the outset that I was one of those who moved a Statutory Resolution against the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Ordinance, 2019. I oppose the Ordinance because I do not like the Government taking the Ordinance route. It circumvents the democratic procedure and it was only a matter of one or two months. So, the Government should not have resorted to the Ordinance.

Having said that opposing the use of Ordinances, let me make it absolutely clear that my Party is for the Bill, for banning of electronic cigarettes. My Party is also against smoking. It is not a personal question; it is a political view that smoking causes lung cancer and should be banned.

The Health Minister is an eminent ENT surgeon himself. He has seen at close range the amount of cancer cigarettes produce. So, if he has taken this step, I would have no objection, but like my young friend, Ritesh Pandey, I have a lot of questions to ask the hon. Minister.

In Bengali, there is a proverb which says *jhi ke mere bouke shekhano* which means that you beat up the maid servant to teach a lesson to your daughter-in-law. This is what the Minister is doing. Actually, his intention is to take on the tobacco lobby and the manufacturers, but he lacks the courage to do it at one go. So, he has taken up a very small percentage of tobacco users where only 3.95 per

cent of Indian population were aware of e-cigarettes and the percentage of users stood at 0.02. So, he is leaving 99.98 per cent free of this law; he is only touching the 0.02 per cent. Is it wise? Is it efficacious?

HON. CHAIRPERSON: Is the use of e-cigarettes not increasing year after year?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, e-cigarettes are diminishing year after year because they are costly and beyond the reach of most of the people.

(1855/RBN/IND)

Earlier, the ITC was importing e-cigarettes from China. There is not much manufacture of e-cigarettes anywhere. It is a very advanced electronic item. It is mostly imported. Big companies like the ITC and Philip Morris used to import these things and market them in India.

What is an e-cigarette? The Minister said something about it. But basically it is a hardware which is designed to replicate the traditional cigarette. It gives a sort of cigarette smoking experience with the help of battery, atomizer, and e-liquid juice. It produces vapour by passing current through an atomizer from the battery which vaporises the e-juice. I would like to state that it is not marketed as a cessation device. That means nobody gives up smoking cigarette because of e-cigarettes, and it is used only as a substitute for traditional cigarettes. So, as I said, there is a battery. You press the button. Then, it atomises and then there is the e-liquid which is used. That is why, I think that the Minister is only touching the fringe of the problem. From his Ordinance, from his hurry, it would seem as if he is taking a massive step against smoking *per se*. But, as my young friend, Shri Ritesh Pandey said, it is not only smoking, but chewing tobacco also is equally dangerous. Other tobacco products like the pan parag, zarda etc. are equally dangerous. So, he is touching only the fringe of the problem and that too with much fanfare. This is what I think should not have happened.

1856 hours (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

You may ask as to what is my solution. The Minister has stated many steps that he would take, like electronic cigarette industry will be taken under his control, production, manufacture, import, export, advertisement, etc will be stopped, storage of electronic cigarettes will be stopped, all stocks and disposing of stocks will be controlled by an authorised officer. This is like what you do for cocaine and marijuana. If anybody contravenes this Act, there is a provision for imprisonment which may extend up to one year and a fine which may extend up to Rs. 1 lakh or more.

I have another question to ask of the hon. Minister. He is taking so much trouble to enforce this ban. He will authorise an officer to enforce this ban. But has ban really prevented things from happening? For example, in Gujarat there is prohibition. Ban on alcohol drinking is in practice for so many years. Has drinking stopped in Gujarat? Bihar has had a ban on alcohol for so many years now. Has consumption of alcohol stopped in Bihar? The idea of ban, which is very popular among Governments in our country is not efficacious. It does not serve the purpose. So, you might ask me as to what is my solution and how to enforce the ban. The way of enforcing the ban is to price it out of the range of the people. This ban will ultimately not have much effect. So, what you can do is to make it expensive beyond limits and regulate them by imposing taxes. You can do it for other products also and not just for e-cigarettes. So, ban is no solution. Making it available beyond their buying capacity seems more reasonable than banning products. Even if the Government bans e-cigarettes, they should not let cigarettes and bidis be sold freely which kills 1.2 million people every year. That is the main question. You are not stopping sale of cigarettes, bidis, gutka, chewing tobacco, pan parag, etc. But you are just banning electronic cigarettes and you have promulgated an Ordinance for the same.

(1900/SM/RAJ)

As it is, e-cigarettes are priced high. So, if we increase the cost further, it will be more efficacious. I shall not oppose the Bill. I have got many amendments to move but I shall not oppose the Bill.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): But you have to admit the spirit of the Bill.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes, Sir. All I am saying is that let the Minister see this. Sir, the Minister's conclusions are somewhat sketchy. He has said that available scientific evidence indicates that use of e-cigarettes is hazardous for an active as well as a passive user. Where is the scientific evidence? He should have quoted the scientific evidence on e-cigarettes.

Secondly, he has said that ICMR has issued a White Paper. But the White Paper has not been circulated to us. ICMR is Indian Council of Medical Research. That White Paper is not available with us. The International Association for the Study of Lung Cancer also does not recommend the use of e-cigarettes for treating nicotine dependence even in cancer patients, due to the absence of sufficient evidence on their efficacy and safety. So, even the International Association has not recommended this banning of e-cigarettes.

So, my appeal to you, Sir, is that please rethink about this. I am giving a specific amendment in that sense. He has mentioned about three types of electronic cigarettes. It is mentioned that 'electronic cigarette' means an electronic device that heats a substance, with or without nicotine and flavours, to create an aerosol for inhalation and includes all forms of Electronic Nicotine Delivery Systems, Heat Not Burn Products, e-Hookah and the like devices. I said, ok, where nicotine is delivered electronically, you can eliminate them. You can also eliminate e-Hookah. But they say that there are some Heat Not Burn Products. We just heat the tobaccos but do not burn them. They should be classified in the same say.

Sir, in cigarettes, there are three dangerous things. One is nicotine, second is the paper and the third is tar that is formed. So, if the Heat Not Burn Products is used, at least tar and paper's smoke will not occur.

So, I would like to ask the hon. Minister whether you would like to rethink on this matter. Sir, having put my objections, let me again say that the most

dangerous thing today is chewing tobacco. 51 million people are using it. How does tobacco stock exist in the market? He has not done anything about it.

Earlier they said that cigarette, bidi will not be sold within so many metres of school premises or religious places. That is also happening.

So, the hon. Minister has to take many more steps to ensure the lessening of cigarette smoking. Banning is surely not the way by which it will be lessened.

I would again ask the Minister to think of more efficacious ways to cut down smoking. I know with tobacco industry's giant like ITC, Philip Morris, Godfrey Philip etc., you will not be able to close down the tobacco industry. Thousands and millions of farmers are tobacco farming in Andhra Pradesh and other States. You will not be able to meet the challenge of those tobacco farmers' lobby.

(1905/AK/VB)

So, he is taking just a token step to say that : "See, I am Harsh Vardhan, ENT Specialist and a Minister, and I am opposing e-cigarettes through this. I am paying my token allegiance to the cause of stopping cigarette smoking.".

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): So, you are giving a compliment to the Minister!

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): No, he is a top ENT Surgeon. There is no doubt. He is the best man BJP has in Delhi. There is no doubt. He should have been made Chief Ministerial candidate, but that is another question.

I would say that let him rethink on all the points that I have put. Thank you, Sir.

(ends)

HON. CHAIRPERSON: You have made very valid points regarding this issue.

Now, I would call upon hon. Member, Dr. M.K. Vishnu Prasad.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): He is also a doctor.

1906 hours

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Thank you, Chairperson. I am a Medical Doctor, and I am very grateful for getting an opportunity to speak on the prohibition of electronic cigarettes.

First and foremost, I would like to say that the very idea of our hon. Prime Minister is 'Digital India'. The moment he says 'Digital India', I was thinking that the country is going to promote e-commerce, e-tender and robotic surgery. But I was shocked to know how e-cigarette is being banned.

Anyway, to start with, I want to tell you a quote : "Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know it because I have done it 1,000 times". I would really say that the youngsters of this age who really wanted to quit smoking have opted for these e-cigarettes. Honestly, I appreciate the initiative taken by the Government of focusing on e-cigarettes to be banned. What will happen to the people who have already resorted to e-cigarettes after that ban? Is there any proposal by the Government for any rehabilitation for those three per cent people who have already indulged in e-cigarettes?

The meaning of e-cigarette is 'the device that heats a substance with or without nicotine'. It clearly says that 100 per cent nicotine is not used among all the users. It varies, but most of them wanted to quit cigarette. So, they opted for e-cigarettes and they are trying to wean out the habit of smoking. But I would like to know about this issue when the Government is so strict on banning e-cigarettes by bringing this promulgation order. The e-cigarettes are very expensive. It costs almost Rs. 5,000. Nearly, 99.8 per cent of the population, who have already indulged in smoking, are only smoking cheaper cigarettes. These 0.02 per cent people are spending almost Rs. 5,000 to get a stick of e-cigarette with a filler. Is the Government very much bothered only about the rich children of this country? Otherwise, can we say that the Government is blind towards the poor people who are already indulged in smoking? Is it not the responsibility of the Government to save them also from smoking instead of bringing this Bill completely banning it?

The Government is always quoting United States, UK, Germany, but e-cigarettes are not banned there. They have a regulation for it. Instead, the nicotine-fillers can be banned. This has been adopted by many other countries, which we are always very proud to follow. If at all the Government wants to ban

e-cigarettes because of the fear that the people who start with e-cigarettes will eventually lead to conventional smoking, then in that case, why can the Government not follow the Korpa system very strictly? Moreover, I think that the Government is feeling that since 0.02 per cent only have started smoking e-cigarettes, banning entire tobacco products or 99.8 per cent people from smoking is rather a difficult job or a Himalayan task.

(1910/SPR/PC)

So, you want to nip it in the bud itself by banning the e-cigarettes. Okay, I agree. At the same time, is it not the responsibility of the Government to stop giving licence to the Hookah Bars because everywhere Hookah Bars are being introduced? The new culture of Hookah Bars is coming with varied licence of the Government. I urge upon the Government to kindly also consider banning Hookah Bars while banning e-cigarettes because Hookah Bars are in the initial stage. It is in the budding stage. You are very strict on e-cigarettes. At the same time, try to focus on banning or stop giving licence to Hookah Bars.

Probably the reading is different. The e-cigarettes might cause accidents because it is an electronic thing. Sometimes it bursts and causes damage to the face. Hon. Minister, you are a very learned person. I have high regards for you. First and foremost, the forensic people would ask, when they come across any fire accident, whether there was cigarette butt. So, the fire in the cigarette butt has caused major fire accidents all across the world. No doubt. Causing accidents cannot be a substantive point for you to ban these e-cigarettes.

I think, the Government is keener in banning a blade than a sword; the Government is keen on banning a stone than a bullet. I think, definitely, the Government is under heavy pressure by the tobacco lobby because 99.8 per cent of the tobacco is freely available and there is only 0.2 per cent non-tobacco users. E-cigarette users are going to have a big challenge in the near future.

It is stated in the Bill that an officer, not less than the rank of a Sub-Inspector, can enter upon any house, in the name of search or suspicion. I think, this will give room for wide misuse. So, I would request the Government to relook into this particular aspect. You want to ban e-cigarettes. These e-cigarettes are only to help the people who wanted to stop smoking. What about the fruit bear, non-alcoholic bear, and the ginger bear? Is the Government coming up with any proposal to even stop those products? I was astonished to

see the countries which have been quoted as an example for banning e-cigarettes – Brazil, Argentina, Japan and Thailand. These countries are heavy cigarette smoking and tobacco using countries. Naturally, they will ban e-cigarettes because proportionally their business will increase.

Last but not least, I welcome banning of e-cigarettes subject to terms and conditions. The Government is now coming with this proposal to ban e-cigarettes. Will the same Government come with any plan to ban Electronic Voting Machines? That is also harmful for the country.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): That is a different subject.

SHRI M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): One of the hon. Members was giving statistics about the US. He was comparing the age. The average age is 17 for e-cigarette smokers, and 35 for the conventional smokers. Both the e-cigarette smokers and conventional smokers have increased. Sir, I agree e-cigarette smokers and conventional cigarette smokers have increased. No doubt. Why are you focusing only on e-cigarettes? Why do you not treat them equally? Why is this partiality? This is not my question but the question from outside. So, I urge the Government to come back with a comprehensive Bill. You have an absolute majority. You can make the Sun rise from the West also. The Government has that kind of power. Why does the Government not protect the interests of the tobacco farmers while banning the usage?

In this Bill, the prohibition of e-cigarettes includes production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution, storage, advertisement and everything is covered but usage is not covered. So, kindly include that also. Thank you for the opportunity.

(ends)

(1915/KDS/UB)

1915 बजे

श्री रवि किशन (गोरखपुर): धन्यवाद महोदय कि आपने मुझे ई-सिगरेट पर जो सरकार प्रतिबंध लगा रही है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया। जी हां, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं समर्थन इसलिए करता हूं कि बहुत सारे माननीय सदस्य, अपनी-अपनी पार्टी से बोल रहे थे कि ई-सिगरेट क्या है? एक कहावत है, जो पहले हम सुनते थे-"अंग्रेज इस देश में दो चीज छोड़कर चले गए- सॉरी और सिगरेट।" उस सिगरेट को हम आज भी ढो रहे हैं। उस एडिक्शन को अभी तक हम निकाल नहीं पाए हैं। तम्बाकू का बिजनेस हो गया, खेतिहर किसानों का बिजनेस हो गया, लेकिन जो एडिक्शन है, उस कैंसर को हम लादे चल रहे हैं। लगभग डेढ़ सौ साल हो गए हैं। अंग्रेज सिगरेट को यहां पर ठूंस कर चले गए।

महोदय, हमारे कुछ साथी नहीं चाह रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगे। वे चाहते हैं कि अब यह नई ई-सिगरेट आए और इसको बढ़ावा दिया जाए। इनको पता ही नहीं है कि यह सिगरेट क्या है? ई-सिगरेट एक पतली सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके साथ एक पॉड लगा रहता है। वह पॉड करीबन दो हजार रुपये का आता है और ई-सिगरेट करीबन चार-साढ़े चार हजार रुपये की आती है। छ: हजार रुपये में यह पैकेट आता है। इसका एडिक्शन लगा था। यह बहाना फैलाकर मार्केट में कर दिया गया, ज़ूल एक कंपनी है, जिसने अमेरिका में यह फैलाया कि "If you want to get rid of cigarettes, and not to get addicted to this, you will definitely quit smoking." मोस्टली क्या हुआ कि अमेरिका के घरों के 9 साल, 10 साल,11 साल के बच्चे, They started carrying it to the schools. इसमें स्मेल नहीं आता, गंदी बदबू नहीं आती। आप कहीं पर भी बैठकर पी लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। यह एक आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गया। अमेरिका इसके खिलाफ है। अमेरिका को जब पता चला, तो वाशिंगटन में They have written on 19th September ई-सिगरेट प्रतिबंधित करने का भारत का फैसला ऐतिहासिक है। यह वहां के अखबार की हेडलाइन थी। नशीले पदार्थों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अमेरिका के समूह ने कहा कि ई-सिगरेट को प्रतिबंधित करने जैसा ऐतिहासिक फैसला लेकर भारत युवाओं को समस्याओं से बचाने की लड़ाई में विश्व में अग्रणी बन गया है।

'Campaign for tobacco free kids' के अध्यक्ष मैथ्यू ने कहा कि राष्ट्र भर में ई-सिगरेट की बिक्री उत्पादन, निर्यात और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने का भारत का फैसला युवाओं को निकोटिन की लत से बचाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। उन्होंने भारत में ई-सिगरेट की लत से युवाओं को बचाने के संबंध में लिए गए सरकार के इस निर्णायक कदम की सराहना की। दुनिया भर के देशों में ई-सिगरेट के तेजी से पहुंचने के कारण उन देशों की सरकारों के लिए नई चुनौतियां आ गई हैं और उनको इनका सामना करना पड़ रहा है। जो युवा नशे की लत से बचने के लिए तम्बाकू का इस्तेमाल कम करने की जद्दोजहद कर रहे थे, अब वे ई-सिगरेट के एडिक्ट हो गए हैं।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यह महंगा नहीं है। हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह महंगा है। गरीब आदमी इसको ले नहीं सकता। No, No. China started making copies of e-cigarettes. यह पांच सौ रुपये, आठ सौ रुपये में भी आ गया है। हजार रुपये में अब तो लोग नकली ई-सिगरेट पीने लगे हैं। इसमें अलग-अलग फ्लेवर्स हैं। एप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर आदि अनगिनत फ्लेवर हैं। So, you get addicted to this. यह बहुत ही खतरनाक है। एक गाने से हम बर्बाद हुए। वह गाना बड़ा हिट हुआ था:

"मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।"

सबको लगा कि फिक्र धुएं से उड़ेगी और सब लोग सिगरेट पी-पीकर कैंसर लेने लगे। मैं टेक्सस की एक कहानी सुनाता हूं। I am going to tell you. हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसके हार्म क्या हैं?

(1920/MM/SNT)

नुकसान सुनिएगा, तब पता चलेगा कि सरकार क्यों इस बिल को लेकर आयी है और ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा रही है। आप पहले इसके हार्म जानिए, यहां माननीय सदस्य नहीं है, शायद चले गए हैं। I just wanted to tell them about a case. A lady in Texas said that smoking habit left her with blood clots fluid in her lungs. She was vaping on and off for three years. In June, she started to cough and had a bad chest pain. She spent 24 days in hospital, and went directly into coma. इसमें स्ट्रेट डैथ है, ब्रेन स्ट्रोक होता है। स्ट्रेट हार्ट अटैक है, आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। आपको सांस लेने का, चिल्लाने का या आवाज देने का समय भी नहीं मिलता है, तुरंत आप ऊपर निकल लेते हैं। Till now, 400 people in America, only in California, are suffering from this disease. यह मिसटिरियसली पता ही नहीं चला कि what they are suffering from. इसका धुआं लंग्स में जाकर एक काई सी जमा देता है और पूरे लंग्स को लॉक कर देता है, जिससे आप ब्रीद नहीं कर सकते हैं। यह केमिकल से बनता है। It is made from crystal. They make this by crushing crystal. उससे इतना सारा धुआं निकलता है। वह जो स्मोक होता है, जिसको आप हुक्के में भी देखते हैं। इसके अजीब-अजीब टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके छाती में जाते हैं। ईश्वर ने हमारा एक सुंदर शरीर बनाया है, जो रेड है। हमारे फेफड़े रेड हैं, हमारा हार्ट रेड है, उसको पूरा ब्लैक कर देता है, जैसा कि सिगरेट से होता है। ईश्वर ने जिसे रेड बनाकर भेजा था, हम उसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं और मृत्यु की ओर हम लोग तुरंत अग्रसर हो जाते हैं।

महोदय, इसमें पांच परसेंट निकोटिन का कंटेंट होता है, जो कि बीस पैकेट सिगरेट के बराबर होता है। इसके चार पॉड्स आते हैं, जो कि एक सिगरेट के पैकेट के बराबर होता है, इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इससे हार्म नहीं होता है। इससे बहुत हार्म होता है और डायरेक्ट डैथ होती है। यह बहुत ही खतरनाक है। यह बैटरी से चलता है। ऐसा भी हुआ है कि e-cigarettes have exploded and shattered people's job, according to FDA (Food and Drug Administration). They have appeared to associate with battery related issues. People are smoking और उनके जबड़े फट गए हैं। पूरे विश्व में 65 प्रतिशत बच्चे, सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी मेरे देश में है, तो मैं क्यों अपने युवाओं को बर्बाद होने दूंगा, मैं क्यों अपने देश के नौजवानों को बर्बाद होने दूंगा? जो लोग इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वे अपने बच्चों को यह सिगरेट देंगे? क्या इनको अच्छा लगेगा, जब इनका बच्चा यह सिगरेट पीएगा? क्या ये अपने बच्चों को यह सिगरेट देंगे? अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दीजिए। आप घर में तो अपने बच्चे को पीटने लगते हैं। मैं क्यों न मेरे देश के युवाओं को अभी से बचाऊं? अंग्रेज इस देश से चले गए हैं और हम सिगरेट को ढो रहे हैं। हमारा आधा देश एडिक्टिड हो गया है और अब यह नये वैपन

को भी क्या आने दिया जाएगा? ई-सिगरेट, आप भी आइए। आपका स्वागत है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमारा आजाद मुल्क है और लोकतन्त्र है। सभी का स्वागत है। डिबेट होगी और दो हां बोलेंगे, एक ना बोलेगा और डिबेट शुरू हो जाएगी। This is wrong. मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी चले गए हैं, हमारी सरकार क्या नहीं कर रही है। वर्ष 2015 में सरकार स्ट्रिक्ट हुई। मैं सिनेमा से हूं। We used to smoke in the movies. …(व्यवधान) हम लोग सिनेमा में कभी-कभी सिगरेट पीते हैं। यह कला में एक स्टाइल के रूप में आती है। वर्ष 2015 में 8.2 प्रतिशत सिगरेट पीने वालों की संख्या कम हुई है। पर्दे पर अगर सिगरेट पीते हुए हीरो दिखाई देता है तो नीचे चेतावनी की पट्टी भी आती है। सिगरेट के पैकेट पर सड़ा हुआ जबड़ा, कैंसर से फटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ई-सिगरेट पर ऐसा कुछ भी नहीं है। There are no warnings. सिगरेट के पैकेट पर इतना बड़ा मुंह होता है, जो बहुत ही गंदा होता है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

श्री रवि किशन (गोरखपुर): सर, मैं क्षमा चाहता हूं, हम भावनाओं में बह गए।

HON. CHAIRPERSON: Please continue and conclude.

(1925/SJN/RSG)

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : महोदय, मैंने जो… *(Not recorded)* शब्द बोला है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार उस पर एक डरावना-सा चेहरा बनाकर इस ओर काम कर रही है। मैं अपने शब्द को ठीक कर लेता हूं। उसको सरकार सिगरेट के पैकेट पर दिखाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम लोग किसी लॉबी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इसमें हमारा कोई स्वार्थ है। लेकिन इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है। हमारे देश के नौजवानों को खत्म करना या उनके फेफड़ों को खराब करने की मंशा या स्वार्थ हम लोगों का नहीं है। हमारे नौजवानों को इस मां भारती की धरती पर श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी और हमारी भारत सरकार यह कभी नहीं चाहेगी। इस सरकार का उद्देश्य हमारे देश को बचना और उसकी रक्षा करना है। हम सभी लोग उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, बहुत सारी बाते हैं। मैं बहुत देर से सबको सुन रह था, क्योंकि बहुत कम जानकारियां थीं। ई-सिगेरट से इंसान सीधे कोमा में चला जाता है। हार्ट का स्ट्रोक आता है। लंग्स से संबंधित सारी बीमारियां इससे जुड़ी हुई हैं। इसका कोई उपाय नहीं है। क्रिस्टल से बना धुआं होता है। It damages your body. It straightway hits your brain. आपको ब्रेन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको छिपाना बहुत ही आसान है। यह बढ़ रहा है। बहुत तरीकों से लोगों को इसकी जानकारी है। इसको हुक्का के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के जवान, मेरे देश के नवयुवक आज जिनकी आबादी 65 प्रतिशत है, वह किसी भी प्रकार से अपने शरीर को किसी भी मात्रा में, किसी भी तंबाकू से अपने आपको नुकसान पहुंचाए। चाहे वह सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो या कुछ भी हो, वे अपने शरीर को बर्बाद न करें। यह शरीर एक मंदिर है, पवित्र है। अतः मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इति)

1927 बजे

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं हर उस चीज का समर्थन करता हैं, जो प्रतिबंध या बैन लगाने की बात करता है। जिसकी वजह से नशे की लत लगती है या हम अपने नौजवानों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देखते हैं। माननीय मंत्री जी, आज ई-सिगरेट को बैन करने का बिल लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सदन के अंदर जितने भी लोग हैं, वे पूरी तरह से इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि इस मुल्क के अंदर हर एक मिनट में या एक मिनट के अंदर 10 लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। मंत्री जी, आप इस बात को मानेंगे कि ई-सिगरेट्स तो इस देश के अंदर एक नया फिनॉमिना है। यह अभी-अभी नया-नया इन्ट्रोड्यूज़ हुआ है और पूरी तरह से देश भर में फैला भी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर इतनी सारी मौतें हो रही हैं, तो आप खुद मानेंगे कि जो लोग मर रहे हैं, वे या तो सिगरेट पीकर मर रहे हैं या बीड़ी पीकर मर रहे हैं या गुटखा खाकर मर रहे हैं या किसी दूसरे नशे का इस्तेमाल करके मर रहे हैं या शराब पीकर मर रहे हैं।

सभापति महोदय, हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर यह लिखा हुआ होता है कि “Cigarette smoking is injurious to health”. मुझे मालूम है कि जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े होंगे, तो वह यह दावा करेंगे कि आपके दौर में अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से तंबाकू से संबंधित मौतें कम हो रही हैं। तंबाकू की खपत कम हो रही है। जबकि हकीकत यह है कि इस मुल्क के अंदर वर्ष 1998 में 79 मिलियन स्मोकर्स हुआ करते थे। वर्ष 2018 में जिनकी संख्या बढ़कर 120 मिलियन हो गई है। यानी 20 सालों के अंदर 40 मिलियन स्मोकर्स का इज़ाफा हुआ है। महोदय, जब गुटखे के ऊपर बैन लगाया गया था, जब महाराष्ट्र की सरकार ने और अलग-अलग राज्यों की सरकार इसको लेकर आई थी, तब न जाने कितानी माताओं ने दुआएं दी थीं कि जिसकी वजह से कैंसर होता है, अब हमारे बच्चों को यह प्रोडक्ट बाजार में नहीं मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हकीकत क्या है।

सभापति महोदय, मैं जब रविवार की रात को अपने संसदीय क्षेत्र - औरंगाबाद से निकल रहा था, तो मैंने अपने लड़के से कहा कि बाजार से जाकर गुटखा लेकर आओ। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और मुझसे पूछा कि भईया आप तो गुटखा नहीं खाते हैं। आप यह क्यों मंगा रहे हैं? तब मैंने कहा कि मैं इस महान सदन को यह दिखाना चाहता हूं कि हम बिल तो लेकर आते हैं, वह बिल पास भी हो जाता है। लेकिन इसका इंप्लीमेन्टेशन जमीन के ऊपर कैसे होता है।

(1930/PS/GG)

महोदय, मैं ये पूरे गुटखे और पान मसाले के पैकेट्स ले कर आया हूँ और आपके जरिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को यह देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जितने भी गुटखे और पान मसाले पैकेट्स हैं इनको आप अपनी हैल्थ की किसी भी लैबोरेट्री के अंदर चैक करवाइए तो आपको पता चलेगा कि न तो यह गुटखा है, न तो यह पान मसाला है, बल्कि ज़हर का सामान है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Member, it is not allowed. You can speak on the subject only.

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद): सर, यह हम आपके ज़रिए मंत्री साहब को देना चाहते हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, it is not allowed. You can speak on the subject.

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद): सर, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके ज़रिए स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहते हैं, क्योंकि यह ज़हर बाज़ार के अन्दर खुलेआम बिक रहा है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: If you bring some items, then every hon. Member can bring items.

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद): सर, ठीक है, हम नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो हम बाद में स्वास्थ्य मंत्री जी को देना चाहेंगे, ताकि इसकी जांच कराई जाए कि किस तरह से खुलेआम इस तरह का यह कारोबार बैन होने के बावजूद भी चल रहा है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can personally meet the hon. Minister and explain to him.

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): All right, Sir. सर, मेरा यही कहना है कि आज आप ई-सिगरेट्स के ऊपर बैन ले कर आ जाएंगे और वह बिल पास भी हो जाएगा। लेकिन गुटखे के ऊपर बैन होने के बावजूद भी आज 51 मिलियन लोग गुटखा बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं और खा रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है अगर सिर्फ ई-सिगरेट जो सिर्फ छोटा सा एक कंपोनेंट है, इस ज़हर को आप निकालना चाह रहे हैं और बाकी पूरे ज़हर को रहने देना चाह रहे हैं, चाहे वह गुटखा हो, शराब हो, बाकी दूसरे जो ज़हर हों, बीड़ी हो सिगरेट हो। अभी-अभी एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि बीड़ी के ऊपर पूरा बैन कैसे ले कर आ सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग इसकी खेती करते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उनको जिंदा रखने के लिए हम करोड़ों लोगों की जान का सौदा करें? सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार को कहना चाहिए कि बीड़ी फार्मिंग को कम किया जाए, हम रीहैबिलिटेट करेंगे।

महोदय, आज इत्तेफाक से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो दस मंत्र दिए थे, उनमें एक मंत्र यह भी था कि नशे से दूर रहो। हमने बाबा साहब की पुस्तक को तो अपना लिया है। लेकिन उनके इस मंत्र को नहीं अपनाया है। यह नशे का कारोबार इस मुल्क में बंद होना चाहिए।

महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। वर्धा – जहां पर महात्मा गांधी जी का आश्रम है, वहां पर शराब नहीं मिलती है, वहां पर बैन कर दिया गया है। तो क्या बापू ने यह कहा था कि मेरा शहर जो होगा, मैं जहां पैदा हुआ हूँ, मेरा आश्रम जहां है, वहां पर शराब नहीं मिलनी चाहिए, बाकी पूरे देश के अंदर शराब मिलनी चाहिए? यह किस तरह से सिलेक्टिव ओपिनियन अपना लेते हैं, सिलेक्टिव बिल्स ले कर आते हैं?

महोदय, जब गुटखा बैन हुआ तो न जाने कितनी ऐसी इल्लिगल फैक्ट्रीज़ तैयार हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो महीने पहले मैंने औरंगाबाद शहर के अंदर पुलिस और प्रशासन को कहा था कि नौजवान नस्लों को बर्बाद करने वाला, यह नशे का करोबार बंद करना है, तो आप गुटखे का कारोबार पूरी तरह से यहां पर बंद कर दें। बंद तो नहीं हुआ, फिर एक दिन हमने कार्यकर्ताओं के साथ जा कर एक बड़े गुटखे के गोदाम पर रेड की। लाखों का गुटखा वहां पर मिला, फिर पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम बंद कर देंगे। लेकिन नतीजा यह हुआ कि आज भी वहां गुटखा मिल रहा है और हो यह रहा है कि जो गुटखा व्यापारी वहां पर थे, जिस पुलिस स्टेशन को एक लाख रुपये हफ्ता देते थे, अब हमारा नाम दिखा कर, हमारा डर दिखा कर वह हफ्ता एक लाख रुपये की जगह पर दो लाख रुपये कर दिया है और गुटखा वैसे का वैसे चालू है।

महोदय, जब यह गुटखा मैं ले कर आ सकता हूँ, तो क्या वजह है कि फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता चलता है, पुलिस को नहीं पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे देता है कि केवल एफडीए ही इसके ऊपर कार्यवाही करेगा। यह फूड से रिलेटिड है, पुलिस से नहीं नहीं है। मेरा यही कहना है कि अगर आप कानून ले कर आ रहे हैं तो उसको लागू करने के लिए भी आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, वर्ना हम लोग झूठे तरीके से अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि देखो हमने गुटखे के ऊपर पांबंदी लगा दी है और आज हम इलैकिट्रॉनिक्स सिगरेट्स के ऊपर भी पाबंदी लगा देंगे। अगर उसका इम्पिलिमेंटेशन सही नहीं होगा, तो पीठ थपथपाने का कोई मतलब नहीं है।

धन्यवाद।

(इति)

1934 बजे

श्री हुनमान बेनिवाल(नागौर): सभापति महोदय, ई-सिगरेट - उत्पादन, विनिर्माण, आयात-निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भण्डारण व विज्ञापन (प्रतिषेध) विधेयक 2019 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी, पक्ष-विपक्ष के सभी लोगों ने नशे को ले कर बड़ी चिंता जाहिर की है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान भारत के अंदर हैं। भारत की युवा पीढी नशे के अंदर, दिन-प्रति दिन जो प्रतिशत बताए गए हैं, वह नशा बढ़ता जा रहा है।

(1935/KN/RU)

मैं प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा। ई-सिगरेट जो एक बहुत बड़ा प्रचलन हो गया, शहरों के अंदर हुक्का बार, जिनका चलन था, उसके बाद सबसे ज्यादा नौजवान ई-सिगरेट का सेवन करते हैं, वह इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें भी निकोटीन की मात्रा है। वे सोचते हैं कि यह सिगरेट से हट कर है, यह नुकसान नहीं करता। इसलिए नशे की प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और इस विधेयक की पालना सुनिश्चित हो। इसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को भी पाबंद करें और समय-समय पर मॉनीटरिंग का सिस्टम होना चाहिए।

सभापति महोदय, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार ई-सिगरेट के घातक प्रभाव व युवाओं में बढ़ती लत, इससे होने वाले रोग, इनके मद्देनज़र यह बिल युवा-पीढ़ी के स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार लेकर आई है। विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में बताया गया है कि वैश्विक समुदाय ने व्यक्तिगत व जन स्वास्थ्य पर इन नए उत्पादों के सम्भावित प्रभाव के बारे में चिंता की है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम देश की सरकार ने उठाया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ई-सिगरेट पर श्वेत पत्र जारी किया। आज संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। देश को प्रधान मंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, सब ने सम्बोधित किया और आह्वान भी किया कि किन परिस्थितियों के अंदर हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद जिस भारत की परिकल्पना, उस समय शहादत देने वाले हमारे शहीदों ने, उस समय आज़ादी के आंदोलन के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं ने की थी, निश्चित रूप से वह अभी तक अधूरी है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि भारत का मान विश्व के अंदर बढ़ाया। एक दिन में सारी तकलीफें दूर नहीं होतीं। मैं तो देखता हूँ कि किस-किस तरीके की सोच के साथ, किस-किस तरीके के नए बिल रोज़ आप लेकर आते हो और इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी ने बहुत बड़ी मेहनत की होगी। हमारे देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों में इसका मैसेज भी जाएगा, एक रोक लगेगी और कड़ी कार्रवाई का संदेश जाएगा। मैं तो यह भी निवेदन करूँगा कि तम्बाकू पर प्रतिबंध लगना चाहिए। शराबबंदी के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा। गुजरात सरकार ने गुजरात के अंदर शराबबंदी पहले से ही कर रखी है। यह देश भी चाहता है कि शराब मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो और नशे की प्रवृत्ति का सबसे ज्यादा शिकार यदि कोई होता है, देखिए, रईस लोग जो होते हैं वह तो टाइम पास करने के लिए नशा करते हैं। उनका समय कैसे बीते, शाम को बार में चले जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे, नशा कर लेंगे। महँगी

दारू भी खरीद लेंगे, महंगी सिगरेट खरीद लेंगे। जो बार का विदेशी सामान है, वह भी उनको मिल जाएगा। लेकिन गरीब जो झुग्गी-झोपड़ी के अंदर रहने वाला आदमी है, वह समय व्यतीत करने के लिए बेवजह नशे की प्रवृत्ति के अंदर चला जाता है और उसके बाद वह नशे का आदी हो जाता है। नशा छूटता नहीं है, जैसे स्मैक का नशा है, कितना ही प्रयास कर लो, आप उसको अस्पताल के अंदर ले जाओ, जो स्मैकिया हो गया, नशेड़ी हो गया, वह स्मैक नहीं छोड़ता और कई नशे तो ऐसे हैं कि लोग पैसों के लिए अपने माँ-बाप को मारकर पैसा छीन कर भाग जाते हैं। ऐसी घटनाएँ भी इस देश के अंदर हुईं। सभापति महोदय, मेरा तो इसके अंदर एक ही निवेदन है। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please address the Chair and come to the subject under discussion.

…(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): आपके उधर से कोई बोलने वाला है नहीं। आप सब तो खुशी मना रहे हो। महाराष्ट्र में जैसे आपका ही कोई मुख्य मंत्री बन रहा है। मैं दो-तीन मिनट लूँगा। सदन खाली पड़ा है। आपको हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। आधा घंटा बोलो और भाषण दो।…(व्यवधान) *… (Not recorded)* शायद सिगरेट पीने गए होंगे। कोई कह रहा था, मुझे नहीं पता, पीकर अब वापस आएंगे। सर, दो मिनट बोलने दीजिए। सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 47 के अंदर प्रधान मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया।

(1940/CS/KKD)

स्वास्थ्य के बारे में भी लिखा गया। पहले अध्यादेश के रूप में और अब बिल के रूप में आज देश की सरकार युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर करने के लिए कारगर कदम उठा रही है।

महोदय, मैं दो मिनट निवेदन करना चाहूँगा।…(व्यवधान) थोड़ा जरूरी भी है।…(व्यवधान) मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।…(व्यवधान)

महोदय, आप देख लीजिए और उसके बाद मुझे बिठाइएगा। आप चारों तरफ नजर घुमाओ। मैं दो-तीन आंकड़े आपको बता देता हूँ। वर्ष 2015 में विश्व भर में ई-सिगरेट की एक हजार करोड़ डॉलर की बिक्री थी। 16 प्रदेशों ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। इस कानून के अंतर्गत अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। यह स्वागत योग्य है, क्योंकि सजा का नाम सुनकर जो बच्चे ई-सिगरेट पी रहे हैं, वे इसे पीना छोड़ देंगे। विश्व भर में 30 से ज्यादा देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। प्रधान मंत्री जी इस मामले में बहुत चिंतित हैं, सरकार चिंतित है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इसके साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी बहुत चिंतित हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आईसीएमआर के अनुसार अगर यही हालात बने रहे तो वर्ष 2020 तक भारत में 17 लाख नए कैंसर के मामले सामने आ सकते हैं।

महोदय, हम सबको मिलकर भारत को बचाने के लिए सोचना होगा। मैं इस सरकार को धन्यवाद दूँगा। मैं एनडीए के सहयोगी दल के रूप में हूँ। हम लोग छात्र राजनीति से विधान सभा और

लोक सभा के अंदर पहुँचे हैं। हमेशा नौजवान गलत दिशा की तरफ जाता है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका कहीं न कहीं नशे की होती है। वह नशेड़ी बन जाता है, चाहे सिगरेट के माध्यम से हो, चाहे अफीम के माध्यम से हो, चाहे चरस, स्मैक, अभी जितनी चीजों के बारे में सभी लोगों ने यहाँ बताया है। इसकी चिंता सरकार को करनी होगी कि हमारी युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए। युवा पीढ़ी को बचाने के लिए मेरे हिसाब से तो भारत के अंदर अगर कोई क्रान्ति लेकर आया है, तो वह स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान को माननीय प्रधान मंत्री जी लेकर आए। उससे पहले कांग्रेस वाले उसे नहीं लाए, क्या 50 साल से इन्हें इसे लाने के लिए किसी ने मना किया था। ये उसे क्यों नहीं लाए? अब अगर यह तय कर लेंगे कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए, तो नशा मुक्त भारत हो जाएगा, क्योंकि देश का नौजवान प्रधान मंत्री जी के आह्वान का इंतजार कर रहा है कि प्रधान मंत्री जी क्या कह रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान की तरह नशा मुक्त भारत अभियान भी इस देश के अंदर चलना चाहिए। प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिल रहा है। किसान, जवान और अब इनके बारे में सोचना होगा। अब इनके बारे में सोचने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे जो दो मेन काम थे, धारा 370, 35ए और राम मंदिर, वे काम तो हो गए। अब जो बचे हुए काम हैं, उसमें किसान, नौजवान और जितने घोटाले लोगों ने कर दिए, उसमें उनकी जाँचें, जहाँ उनकी जगह है, उन्हें वहाँ ले जाकर फिट करना, कई लोग आराम कर रहे हैं।

माननीय सभापति (श्री कोडिकुन्निल सुरेश): हमारा विषय ई-सिगरेट है।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): महोदय, मैं बिल के साथ-साथ देश पर भी आऊँगा। मैं केवल बिल पर थोड़े ही बोलूँगा। मुझे बोलते हुए लाखों लोग देख रहे हैं कि हनुमान बैनिवाल बोल रहा है। हनुमान बैनिवाल बोल रहा है, तो फिर वह उस बात को भी बोलेगा।…(व्यवधान) हाँ, पूरा देश सुन रहा है।

इस बिल के साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से अपनी तरफ से विशेष निवेदन यह भी करूँगा कि हम नौजवानों के अंदर और ज्यादा जागरूकता लेकर आएं ताकि नशे की प्रवृत्ति से हिन्दुस्तान का नौजवान दूर रहे।

माननीय सभापति : आपके दस मिनट हो गए हैं।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): आप ई-सिगरेट को बंद कर रहे हो। उसके बाद सिगरेट, बीड़ी और जितने भी इस तरह के तंबाकू उत्पाद हैं, इन सब पर रोक लगाकर एक नया संदेश देश के अंदर दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति : हनुमान जी, गुड स्पीच।

(1945/RCP/RV)

1945 hours

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this important Bill. The fact is that tobacco consumption, either by chewing or by smoking, compromises on the health and economic well-being of all citizens – children, youth, men and women – in the country. Its use presents dangerous consequences for everyone. Use of both smoking and smokeless tobacco causes many forms of cancers leading to early and painful deaths of users in their productive years. It is, therefore, critical to raise awareness to help reduce its use to protect the health of people.

According to the World Health Organisation, tobacco kills more than seven million people each year. Over six million deaths are a result of its direct consumption, whereas 8,90,000 deaths are the result of passive smoking. Nearly 100 million premature deaths have been recorded in the 20th century and the figure is set to increase to one billion by the 21st century. Smoking kills over one million people in India annually and is the fourth leading cause of non-communicable diseases such as cancer and heart diseases which account for 53 per cent of all deaths in India.

I would like to convey my thanks to the hon. Minister who has brought this Bill for banning electronic cigarettes in India and this step will protect the future of the youth of our country.

I appreciate your stand to ban e-cigarettes, but, at the same time, we strongly feel it defies logic, taking into consideration the surprising move of not touching the regular cigarettes and other tobacco products. I would like to make a request to the hon. Minister to kindly ban all types of smoking and tobaccos in India for the better future of our youth.

On my own behalf and on behalf of my constituents, I would like to take this opportunity to thank the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan *ji* for granting permission to start Government Medical College in Ramanathapuram district which was a long-standing demand.

(ends)

1947 hours

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak in support of the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019.

A variety of devices are currently sold in the international market that deliver nicotine and other chemicals with flavours by electronically heating materials containing nicotine, so-called, e-cigarettes. These devices are marketed as substitutes for cigarette cessation tools for chronic cigarette smokers.

Now, coming to the natural history of smoking, first of all, I would like to explain about natural history of smoking in India. It has been known that since, at least, 2000 BC, cannabis or *bhang* was smoked for medicinal purpose; that was written in Atharvaveda. History also suggested that tobacco leaf containing nicotine was introduced to Columbus by native Americans and then its addiction rapidly spread to Europe. In India, tobacco was introduced in the 17th century by Portuguese but its use became more popular since the 20th century.

To save youth of India today, we have to take steps so that people do not make another movie, 'Udta India' after making the movie 'Udta Punjab'. It is because WHO has observed that e-cigarettes are heavily marketed towards the youth aged between 15 years and 24 years by adding flavouring agents on promotional strategies. Through e-cigarette device, there is a risk of use of other psychotropic substances also that are harmful physically and mentally.

The WHO and ICMR reports on suggestive use of e-cigarettes may cause negative impact on human health because it produces significant toxic substances and carcinogens. When tobacco burns, in addition to nicotine, more than 7000 other compounds are produced resulting from volatilization, pyrolysis and pyrosynthesis.

Now, I come to the health effects arising out of smoking e-cigarettes. Nicotine is an addictive component which may cause long-term consequences in brain development of youth like difficulty in paying attention during learning at school and anxiety disorder. Recently, a nicotine-induced seizure case was reported in Goa.

(1950/SMN/MY)

Tobacco smoking may cause cancer of the lungs, oral cavity, gastro-intestine tract, genito-urinary tract, blood cancer, acute mild leukemia, breast cancer in female, in respiratory system, COPD and popcorn lungs, in cardio-vascular system, coronary arteries and heart attack, cerebrovascular accident, aortic aneurysm, in pregnant women, spontaneous labour, pre-term delivery, high perinatal mortality rate, and in infants, infant respiratory distress syndrome, low birth weight; and sudden infant death syndrome were noticed.

Although in India, prevalence of e-cigarette smoking is very low but recently in Delhi, 150 vaping devices of e-cigarettes were found in school bags during the surprise check in one school.

Now, what is the necessity of prohibiting e-cigarettes? At present, 42 countries have banned e-cigarette because it has highly addictive nature of the nicotine and has the risk of misuse by youth by adding other psycho-active substances with regular liquids. E-cigarettes may be seen as substitutes to traditional cigarettes but young people may use the more harmful forms of nicotine or other forms of harmful substances. No conclusive evidence has been found that the use of e-cigarette has effective tobacco cessation. There has been no evidence of having benefit and relief to chronic smokers by using e-cigarette. Economical burden has increased on the nation and on the families.

So, in the end, while concluding, I support the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Bill, 2019.

Thank you, Sir.

(ends)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS,
PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)